Website : www.mantrabharat.com

जुनून है सच लिखने का

E-Mail : mantrabharatmumbai@gmail.com, Mo. 7007837917

संस्करण : मुंबई
वर्ष : 10
अंक : 344
पृष्ठ : 8
मूल्य : 2.00
शुक्रवार, 19 दिसम्बर, 2025

मंत्र भारत

हिन्दी दैनिक

मुंबई, लखनऊ, प्रयागराज एवं ग्वालियर से एक साथ प्रकाशित एवं ठाणे, नवी मुम्बई, पालघर, नासिक एवं पुणे से प्रसारित

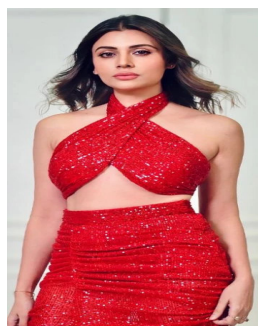

3 महाराष्ट्र भूषण राम सुतार का राजकीय ....

4 लकड़ी की नाव और मसालों की खुशबू...

7 एसएमएटी : ईशान किशन का फाइनल में....

संक्षिप्त न्यूज

संस्कृतभारती रेवाड़ी में आयोजित करेगी शीतकालीन संस्कृत प्रबोधन वर्गः डॉ.नवीन शर्मा

वेदों की मूल संस्कृत भाषा भारतीय ज्ञान परम्परा का मुख्य आधार है। सम्पूर्ण ज्ञान विज्ञान संस्कृत ग्रन्थों में ही निबद्ध है। वर्तमान सरकार भी भारतीय ज्ञान परम्परा के संरक्षण हेतु कटिबद्ध है अतः भारत सरकार ने नई शिक्षा नीति 2020 में संस्कृत व संस्कृत में निबद्ध भारतीय ज्ञान के प्रचार-प्रसार हेतु विशेष महत्व दिया है। संस्कृतभारती एक सामाजिक संगठन है जो न केवल भारत में अपितु विश्व के 28 देशों में संस्कृत के संरक्षण व प्रचार प्रसार हेतु कार्य कर रहा है।

संस्कृतभारती के द्वारा विदेशों एवं भारत के विभिन्न राज्यों में संस्कृत सम्भाषण के प्रशिक्षण हेतु शिविरों का आयोजन किया जाता है। जिनमें भाग लेने वाले शिक्षार्थी मात्र दस दिन में ही संस्कृत बोलने व लिखने में समर्थ होने लगते हैं। संस्कृतभारती हरियाणा के प्रान्त प्रशिक्षण प्रमुख ज्योतिषाचार्य डॉ. नवीन शर्मा ने कैथल के कार्यकर्ताओं को टीक में सम्बोधित करते हुए जानकारी दी कि इस बार यह संस्कृत प्रबोधन वर्ग रेवाड़ी के सनग्लो इण्टरनेशनल स्कूल में 02 जनवरी से 10 जनवरी 2026 तक आयोजन किया जा रहा है। इस प्रबोधन वर्ग में हरियाणा के अम्बाला, कुरुक्षेत्र, पंचकूला, करनाल, पानीपत, कैथल, हिसार, गुरुग्राम, सिरसा इत्यादि 22 जिलों के विद्यालयों, महाविद्यालयों व विश्वविद्यालयों से छात्र-छात्राएं भाग लेंगे।

संस्कृतभारती हरियाणा के प्रान्ताध्यक्ष डॉ. सोमेश्वर दत्त ने बताया कि इन संस्कृत प्रशिक्षण शिविरों की विशेषता यह है कि ये शिविर शीतकालीन अवकाशों में आयोजित किए जाते हैं ताकि विद्यार्थियों के अवकाशों का भी सदुपयोग हो। शिविर में प्रातः से लेकर शाम तक संस्कृतमय वातावरण रहता है।

लोकसभा से पास हुआ जी राम जी बिल, शिवराज बोले- कांग्रेस ने बापू के आदर्शों का किया नाश, हम भेदभाव नहीं करते

नई दिल्ली। संसद के हंगामेदार सत्र में, लोकसभा ने गुरुवार को विकसित भारत गारंटी रोजगार एवं आजीविका मिशन (ग्रामीण) (वीबी-जी राम जी) विधेयक, 2025 पारित कर दिया। इसके विरोध में विपक्षी सांसदों ने तीखे विरोध प्रदर्शन किए और सरकार पर राष्ट्रपिता महात्मा गांधी का अपमान करने तथा महात्मा गांधी राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी अधिनियम (एमजीएनआरईजीए) के प्रावधानों को कमजोर करने का आरोप लगाया। केंद्रीय ग्रामीण विकास मंत्री शिवराज सिंह चौहान ने इस कदम का बचाव करते हुए कहा कि महात्मा गांधी का नाम एनआरईजीए में 2009 के चुनावों को ध्यान में रखते हुए जोड़ा गया था।

शिवराज सिंह चौहान ने विपक्ष के हंगामे पर लोकसभा में कहा कि अपनी बात कहना है और फिर जवाब नहीं सुनना भी 'हिंसा' है, विपक्ष के लोग बापू के आदर्शों के खिलाफ काम कर रहे हैं। उन्होंने कहा कि कांग्रेस के लोग मनरेगा के नाम ढोंग करते हैं, मोदी सरकार काम करती है। चौहान ने प्रियंका गांधी पर पलटवार करते हुए कहा कि नाम

रखने की सनक कांग्रेस की है, बहुत सारी योजनाओं के नाम नेहरू परिवार को महिमामंडित करने के लिए रखे गए। शिवराज ने कहा कि यह आवश्यक हो गया था कि मनरेगा के पैसे का सही उपयोग हो, लूट बंद हो, पारदर्शिता हो, इसलिए इस योजना पर खुले मन से विचार किया गया और नई योजना लाने का फैसला हुआ। उन्होंने जोर देते हुए कहा कि विकसित भारत के लिए विकसित गांव जरूरी है, यही इस योजना का उद्देश्य है। चौहान ने लोकसभा में बोलते हुए कहा कि शुरुआत में यह एनआरईजीए था और विधेयक में महात्मा गांधी का नाम शामिल नहीं था। बाद में, जब 2009 के आम चुनाव आए, तो कांग्रेस ने वोट पाने के लिए बापू गांधी का नाम याद किया। मैं कहना चाहूंगा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने एमजीएनईजीए को सही ढंग से और मजबूती से लागू किया।

जीआरएम जी विधेयक पर आठ घंटे चली चर्चा पर प्रतिक्रिया देते हुए चौहान ने जोर देकर कहा कि मोदी सरकार अपने द्वारा की गई विभिन्न पहलों के माध्यम से महात्मा गांधी के आदर्शों को बरकरार रखने को सुनिश्चित कर रही है। चौहान ने कहा, 'कांग्रेस ने बापू के आदर्शों का नाश किया, एनडीए ने प्रधानमंत्री आवास योजना, उज्ज्वला योजना, स्वच्छ भारत मिशन और आयुष्मान भारत के तहत बने पक्के मकानों के जरिए बापू के जीवन को संजोया।' वरिष्ठ भाजपा नेता ने कांग्रेस नेता प्रियंका गांधी की इस आलोचना का भी खंडन किया कि मोदी सरकार मनमाने ढंग से योजनाओं के नाम बदलती है और जवाहरलाल नेहरू और महात्मा गांधी के नाम पर रखे गए कई कल्याणकारी कार्यक्रमों का उदाहरण दिया।

संसद में हंगामा करने को लेकर विपक्ष पर भड़के चिराग पासवान, दे दी यह बड़ी नसीहत

नई दिल्ली। केंद्रीय मंत्री चिराग पासवान ने गुरुवार को संसद में विकसित भारत गारंटी रोजगार एवं आजीविका मिशन (ग्रामीण) विधेयक पारित होने के दौरान हंगामा करने के लिए विपक्ष की कड़ी आलोचना की और कहा कि इस विधेयक को पारित कराने में विपक्ष की भूमिका शर्मनाक है। केंद्रीय मंत्री ने आरोप लगाया कि कांग्रेस सांसदों ने अध्यक्ष के सामने खड़े होकर शिष्टाचार का उल्लंघन किया। पत्रकारों से बात करते हुए पासवान ने कहा कि ग्राम योजना देश के गांवों को मजबूत करने, गरीबों को सशक्त बनाने और गांवों एवं शहरों के बीच की दूरी को कम करने के उद्देश्य से लाई गई थी। महात्मा गांधी ने कहा था कि भारत की आत्मा गांवों में बसती है। इन्हीं गांवों को मजबूत करने के उद्देश्य से यह योजना लाई गई है।

चिराग ने आगे कहा कि मुझे लगता है कि इस विधेयक को पारित कराने में विपक्ष की भूमिका शर्मनाक है। देश की सबसे पुरानी पार्टी ने पुरानी परंपराओं को कुचला है, यह कभी स्वीकार्य नहीं हो सकता। विरोध करें, आपको ऐसा करने का अधिकार है। लेकिन अगर आप मर्यादा भंग करके अपनी मानसिकता को आगे बढ़ाना चाहते हैं... कांग्रेस सांसदों ने अध्यक्ष के सामने खड़े होकर मर्यादा का उल्लंघन किया। अगर आप अपने विचार इस तरह पेश करते हैं, तो यह परंपराओं के अनुरूप नहीं है और इसे कभी स्वीकार नहीं किया जाएगा।

भाजपा सांसद रवि शंकर प्रसाद ने भी विपक्ष की आलोचना करते हुए कहा, 'आज लोकसभा में कांग्रेस पार्टी ने कैसा व्यवहार किया? रात तक 10 घंटे चर्चा चली। आपको अपनी बात रखने का मौका मिला, लेकिन जब शिवराज सिंह चौहान जवाब देने आए, तो आप विधेयक फाड़ रहे थे... क्या कांग्रेस पार्टी अब अराजक पार्टी बन गई है?' भाजपा सांसद ने आगे कहा कि उन्हें गांधीजी का नाम लेना बंद कर देना चाहिए।

शिवकुमार ने की नेशनल हेराल्ड मामले में एफआईआर वापस लेने की अपील, कहा- मामला पहले ही खारिज किया जा रहा

बैंगलुरू। कर्नाटक के उपमुख्यमंत्री डीके शिवकुमार ने गुरुवार को नेशनल हेराल्ड मामले को लेकर केंद्र सरकार की कड़ी आलोचना की और कांग्रेस के खिलाफ दर्ज एफआईआर वापस लेने का आग्रह करते हुए कहा कि मामला पहले ही खारिज किया जा रहा है।

पत्रकारों से बात करते हुए शिवकुमार ने कहा, 'देखिए, नेशनल हेराल्ड मामला पहले ही खारिज किया जा रहा है, लेकिन फिर भी एक एफआईआर दर्ज है। बेहतर होगा कि वे एफआईआर वापस ले लें। दिल्ली पुलिस में उन्होंने जो भी एफआईआर दर्ज कराई है, वह उनके लिए अच्छी होगी; वरना वे सिर्फ हमें परेशान कर सकते हैं, बस इतना ही। शिवकुमार ने आरोप लगाया कि केंद्रीय अधिकारियों ने नेशनल हेराल्ड मामले से ध्यान हटाने के लिए जानबूझकर फंड जारी करने में देरी की। उन्होंने कहा कि वे ध्यान भटकाना चाहते थे क्योंकि वे जानते हैं कि हम नेशनल हेराल्ड का मुद्दा उठा रहे हैं। वे राहुल गांधी और सोनिया गांधी को परेशान कर रहे हैं। हम इस मुद्दे को उठाना चाहते थे, इसलिए उन्होंने गृह लक्ष्मी के बहाने इसे रोक दिया। उन्होंने अन्य योजनाओं के लिए निधि आवंटन में देरी पर भी सवाल उठाते हुए कहा कि ऊपरी भद्रा परियोजना का पैसा क्यों नहीं दिया गया? एमएनआरईजीए का पैसा क्यों नहीं दिया गया? जल जीवन मिशन और एमएनआरईजीए की धनराशि अभी तक वितरित नहीं की गई है। हमारे वित्त के लिए पैसा नहीं दिया गया है।

मनरेगा विवाद पर बोले मल्लिकार्जुन खरगे

गरीबों के अधिकार छीन रही सरकार, हम अंत तक लड़ेंगे...,

नई दिल्ली। राज्यसभा में विपक्ष के नेता और कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खरगे ने गुरुवार को केंद्र सरकार पर महात्मा गांधी राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी अधिनियम (एमजीएनआरईजीए) में छेड़छाड़ करके काम के अधिकार को कमजोर करने का आरोप लगाया और कहा कि पार्टी देश भर में सड़कों पर उतरकर इसका विरोध करेगी। वरिष्ठ कांग्रेस नेता ने इस बात पर जोर दिया कि यह मुद्दा सिर्फ नाम बदलने से कहीं बढ़कर है और इसके खिलाफ आंदोलन होगा।

पत्रकारों से बात करते हुए खरगे ने कहा कि यह एमजीएनआरईजीए का नाम बदलने का मामला नहीं है, यह काम के अधिकार का मामला है। वे हमसे हमारा ही अधिकार छीन रहे हैं। वे लोगों के अधिकार छीन रहे हैं। यह

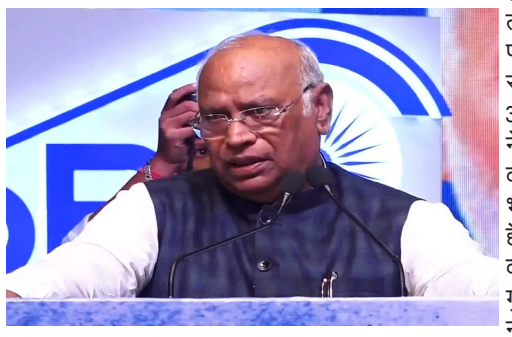

एक बड़ा मुद्दा है और गरीबों के लिए यह बहुत मुश्किल है। कांग्रेस अध्यक्ष ने गरीबों के अधिकारों पर हमले के विरोध में पार्टी द्वारा राष्ट्रव्यापी आंदोलन शुरू करने की बात कही। उन्होंने कहा कि हम इसके लिए अंत तक लड़ेंगे। हम सड़कों पर उतरेंगे और हर राज्य के हर जिले में आंदोलन होगा। कांग्रेस नेता दिग्विजय सिंह ने कहा कि यह हीन भावना से प्रेरित निर्णय है। यह महात्मा गांधी का अपमान है।'

गुरुवार को कांग्रेस नेताओं और कई विपक्षी सांसदों ने संसद परिसर में गांधी प्रतिमा से मकर द्वार तक एमएनआरईजीए का नाम बदलकर वीबी जी राम जी किए जाने के विरोध में प्रदर्शन किया। सांसदों ने 'महात्मा गांधी का अपमान बर्दाश्त नहीं करेंगे' नारे वाले पोस्टर लेकर मार्च निकाला। विपक्षी सांसदों ने अल्पसंख्यकों के खिलाफ अत्याचारों का मुद्दा भी उठाया और संसद परिसर में विरोध प्रदर्शन किया। बुधवार को लोकसभा में विकसित भारत-ग्राम रोजगार और आजीविका मिशन संशोधन विधेयक पर लगभग 14 घंटे तक बहस चली। विपक्ष ने प्रस्तावित विधेयक को स्थायी समिति के पास भेजने की मांग की, वहीं सत्तारूढ़ भारतीय जनता पार्टी (भाजपा) ने विधेयक का जोरदार बचाव करते हुए इसे 2047 तक विकसित भारत के लक्ष्य को प्राप्त करने की दिशा में एक निर्णायक कदम बताया।

महात्मा गांधी के नाम पर राजनीति हुई तेज, सांस्कृतिक राष्ट्रवाद के मुकाबले ममता बनर्जी ने पेश किया संवैधानिक राष्ट्रवाद!

कोलकाता। पश्चिम बंगाल की मुख्यमंत्री ममता बनर्जी ने एक सार्वजनिक कार्यक्रम में बड़ा राजनीतिक और वैचारिक बयान देते हुए राज्य सरकार की रोजगार योजना 'कर्मश्री' का नाम महात्मा गांधी के नाम पर रखने की घोषणा की। उन्होंने कहा कि उन्हें इस बात पर 'शर्म' महसूस होती है कि राष्ट्रीय स्तर पर महात्मा गांधी के नाम को कल्याणकारी योजनाओं से हटाया जा रहा है। ममता बनर्जी का इशारा महात्मा गांधी राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी अधिनियम के नाम में किए गए कथित बदलावों की ओर था, जिसे लेकर विपक्ष लगातार केंद्र सरकार पर हमलावर है।

मुख्यमंत्री ने कहा कि 'कर्मश्री' योजना के तहत राज्य में 75 से 100 दिनों तक रोजगार दिया जाता है और अब यह योजना महात्मा गांधी के नाम से जानी जाएगी। ममता बनर्जी ने भावुक अंदाज़ में कहा, 'मैं वास्तव में शर्मिंदा हूं। राष्ट्रपिता का नाम योजनाओं से हटाया जा रहा है। मैं किसी और को दोष नहीं देती, क्योंकि मैं इसी देश की नागरिक हूं। हम राष्ट्रपिता को भूलते जा रहे हैं, यह दुखद है।'

उन्होंने केंद्र सरकार पर परोक्ष हमला करते हुए कहा कि अगर केंद्र महात्मा गांधी को सम्मान नहीं देगा तो बंगाल देगा। ममता ने कहा, 'अगर आप महात्मा गांधी का सम्मान नहीं करेंगे, तो हम करेंगे।' अपने भाषण में ममता बनर्जी ने महात्मा गांधी के साथ-साथ नेताजी सुभाष चंद्र बोस, गुरुदेव रवींद्रनाथ टैगोर, डॉ. भीमराव आंबेडकर, मौलाना अबुल कलाम आज़ाद, सरदार पटेल और लाल-बाल-पाल का भी उल्लेख किया। उन्होंने बंगाल की 'समावेशी संस्कृति' की बात करते हुए कहा कि राज्य हर समुदाय और हर विचारधारा का सम्मान करता है। देखा जाये तो यह बयान ऐसे समय आया है जब MGNREGA के नाम और पहचान को लेकर देशभर में राजनीतिक बहस चल रही है और तृणमूल कांग्रेस इसे केंद्र सरकार की 'इतिहास और प्रतीकों को बदलने की राजनीति' बता रही है।

इसके अलावा, ममता बनर्जी का यह फैसला सिर्फ एक योजना का नाम बदलने का एलान नहीं है, बल्कि यह आगामी पश्चिम बंगाल विधानसभा चुनावों की राजनीतिक पटकथा का पहला स्पष्ट अध्याय भी है। ममता बनर्जी जानती हैं कि बंगाल की राजनीति केवल विकास के आंकड़ों से नहीं, बल्कि भावनात्मक और वैचारिक मुद्दों से संचालित होती है। और गांधी से बड़ा प्रतीक भारतीय राजनीति में शायद ही कोई हो।

कर्मश्री योजना को महात्मा गांधी के नाम से जोड़कर ममता बनर्जी ने एक साथ कई निशाने साधे हैं। पहला, उन्होंने खुद को गांधीवादी मूल्यों की रक्षक के रूप में प्रस्तुत किया है। दूसरा, केंद्र सरकार पर यह आरोप मजबूती से चस्पा किया है कि वह राष्ट्रपिता की विरासत को हाशिए पर डाल रही है। और तीसरा, ग्रामीण, गरीब और श्रमिक वर्ग के साथ एक भावनात्मक रिश्ता फिर से गढ़ने की कोशिश की है। यह वही वर्ग है जो कभी वाम मोर्चे की ताकत हुआ करता था और आज तृणमूल की राजनीति की रीढ़ है।

बहरहाल, आगामी चुनावों को देखते हुए ममता बनर्जी साफ तौर पर राजनीति को 'संविधान बनाम सत्ता', 'गांधी बनाम विचारधारा' और 'राज्य बनाम केंद्र' की धुरी पर ले जाना चाहती हैं। यह वही रणनीति है जिसने उन्हें पहले भी भाजपा के आक्रामक चुनावी अभियान के सामने खड़ा रखा।

जीरामजी बिल को लेकर केंद्र पर भड़के स्टालिन, बताया राज्य सरकारों पर थोपा गया एक बोझ

चेन्नई। तमिलनाडु के मुख्यमंत्री एम.के. स्टालिन ने गुरुवार को महात्मा गांधी राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी योजना (एमजीएनआरईजीए) में प्रस्तावित बदलावों को लेकर भाजपा के नेतृत्व वाली सरकार पर तीखा हमला बोला। उन्होंने नई 'विकसित भारत गारंटी रोजगार और आजीविका मिशन-ग्रामीण' (वीबी जी आरएम जी) को ग्रामीण गरीबों की आजीविका पर प्रहार करने वाली एक धोखाधड़ी बताया। एक्स पर एक पोस्ट में, मुख्यमंत्री स्टालिन ने भाजपा पर एकता को बढ़ावा देने का दावा करते हुए इस प्रमुख योजना को कमजोर करने का आरोप लगाया।

मुख्यमंत्री स्टालिन ने लिखा कि एकता का दावा करने वाली भाजपा गरीबों के पेट पर वार कर रही है; और थिरु पलानीस्वामी इसमें उनका साथ दे रहे हैं! VBGRAMG योजना में 125 दिन का काम एक छल मात्र है! 100 दिन के काम की गारंटी देने वाला कानून होने के बावजूद, भाजपा शासन में लोगों को केवल 20 से 25 दिन का काम मिला। उन्होंने मासिक आधार पर मजदूरी और परियोजना खर्च जारी न करके लोगों को धोखा दिया। स्थिति इतनी दयनीय थी कि हमें बकाया राशि पाने के लिए भी संघर्ष करना पड़ा।

ं पर पोस्ट में आगे कहा गया है कि अब, नियमों में बदलाव के बाद, जिसमें कहा गया है कि अधिकारी केवल अपनी इच्छा से और केंद्र सरकार के विवेकाधिकार के तहत ही काम दे सकते हैं, एक या दो दिन का काम भी मिलना दुर्लभ हो गया है। तमिलनाडु को निधि आवंटन में भारी वित्तीय नुकसान होने वाला है। राज्यों को परियोजना लागत का 40इ वहन करना होगा, यह शर्त जीएसटी कर परिवर्तनों के बाद गंभीर वित्तीय संकट का सामना कर रही राज्य सरकारों पर थोपा गया एक बोझ है; यह एक दंड है!

पंजाब ग्रामीण चुनावों में आप की शानदार जीत मान सरकार पर मुहर : अरविंद केजरीवाल

नई दिल्ली। आम आदमी पार्टी (आप) के राष्ट्रीय संयोजक अरविंद केजरीवाल ने बृहस्पतिवार को कहा कि पंजाब में जिला परिषद और पंचायत समिति चुनावों में उनकी पार्टी के जोरदार प्रदर्शन से यह पता चलता है कि ग्रामीण क्षेत्रों के लोगों ने भगवंत मान के नेतृत्व वाली सरकार के कार्यों पर अपनी मुहर लगाई है। केजरीवाल ने कहा, "जिला परिषद और पंचायत समिति चुनावों में लगभग 70 प्रतिशत सीट आम आदमी पार्टी ने जीती हैं।"

उन्होंने कहा, "यह बहुत बड़ी बात है। इससे पता चलता है कि ग्रामीण क्षेत्रों के लोगों ने भगवंत मान के नेतृत्व में आप सरकार द्वारा किए गए कार्यों पर अपनी मुहर लगाई है।" पार्टी प्रमुख ने कहा कि 2027 में पंजाब विधानसभा के लिए होने वाले चुनाव से लगभग एक साल पहले यह चुनाव हुआ है। केजरीवाल ने कहा कि जिला परिषद और पंचायत समिति के चुनाव स्वतंत्र और निष्पक्ष तरीके से कराए गए हैं, साथ ही मतदान और मतगणना की वीडियोग्राफी भी की गई थी।

उन्होंने बताया कि कुल सीट में से 580 ऐसी सीट थीं जहां जीत का अंतर 100 मतों से कम था और इनमें से आप ने 261 सीट जीतीं जबकि विपक्ष ने 319 सीट पर जीत दर्ज की। यह दिखाता है कि चुनाव निष्पक्ष तरीके से कराए गए थे। चुनावों के अब तक घोषित परिणामों के अनुसार, पंजाब में जिला परिषद और पंचायत समिति चुनावों में सत्तारूढ़ आम आदमी पार्टी (आप) आगे चल रही है।

नीतीश कुमार की बढ़ाई गई सुरक्षा, सोशल मीडिया पर मिली थी धमकी

पटना। बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार की सुरक्षा बढ़ा दी गई है, क्योंकि हिजाब से जुड़े विवाद ने पूरे देश में तीखी राजनीतिक प्रतिक्रियाएं पैदा कर दी हैं। आधिकारिक सूत्रों के अनुसार, खुफिया एजेंसियों द्वारा घटना के मद्देनजर मिली विशिष्ट जानकारियों के बाद उनकी सुरक्षा बढ़ाने का निर्णय लिया गया। इस मुद्दे ने राजनीतिक तनाव को और बढ़ा दिया है, विपक्षी नेता इस घटना को लेकर मुख्यमंत्री की कड़ी आलोचना कर रहे हैं। यह विवाद सोमवार को शुरू हुआ, जब नीतीश कुमार पटना में एक कार्यक्रम में नव नियुक्त आयुष डॉक्टरों को नियुक्ति पत्र वितरित कर रहे थे।

समारोह के दौरान, उन्होंने कथित तौर पर एक मुस्लिम महिला का हिजाब हटा दिया, जो अपना नियुक्ति पत्र लेने के लिए आगे आई थी। घटना का वीडियो जल्द ही सोशल मीडिया पर

वायरल हो गया, जिससे व्यापक आक्रोश फैल गया। राष्ट्रीय जनता दल (आरजेडी) समेत कई विपक्षी नेताओं ने मुख्यमंत्री के इस कदम को शर्मनाक और अस्वीकार्य बताया। उन्होंने नीतीश कुमार पर धार्मिक भावनाओं को ठेस पहुंचाने का आरोप लगाया और इस घटना के लिए जवाबदेही की मांग की। जैसे-जैसे राजनीतिक प्रतिक्रियाएं बढ़ती गईं, अधिकारियों ने मुख्यमंत्री की सुरक्षा व्यवस्था का तुरंत पुनर्मूल्यांकन किया। मामले में गंभीर घटनाक्रम के चलते कुमार को पाकिस्तान से भी धमकी मिली है। पाकिस्तानी डॉन शहजाद भट्टी ने कथित तौर पर मुख्यमंत्री को धमकी दी है। हालांकि, अधिकारियों ने सुरक्षा व्यवस्था में किए गए सुधारों के बारे में कोई विस्तृत जानकारी नहीं दी है। धमकी मिलने के बाद बिहार के पुलिस महानिदेशक ने शहजाद भट्टी से जुड़े वीडियो की विस्तृत जांच के आदेश दिए हैं। अधिकारियों ने बताया कि जांच पूरी होने के बाद आगे की कार्रवाई की जाएगी।

लगातार चौथे दिन बाजार में गिरावट, सेंसेक्स 78 अंक फिसला

नई दिल्ली **(एजेंसी)**। स्थानीय शेयर बाजार में बृहस्पतिवार को लगातार चौथे दिन गिरावट आई। अमेरिका के साथ व्यापार समझौते को लेकर अनिश्चितता और वैश्विक बाजारों में नरम रुख से सेंसेक्स 78 अंक के मामूली नुकसान में रहा जबकि निफ्टी स्थिर बंद हुआ। बीएसई का 30 शेयरों पर आधारित मानक सूचकांक सेंसेक्स 77.84 अंक यानी 0.09 प्रतिशत टूटकर 84, 481.81 पर बंद हुआ। कारोबार के दौरान यह 84, 780.19 अंक के ऊपरी और 84, 238.43 अंक के निचले स्तर तक भी गया। इस तरह इसमें 541.76 अंक की घट-बढ़ हुई। एनएसई का 50 शेयरों पर आधारित मानक सूचकांक निफ्टी तीन अंक यानी 0.01 प्रतिशत की मामूली गिरावट के साथ 25, 815.55 अंक पर स्थिर रहा।

सेंसेक्स में शामिल शेयरों में सन फार्मा, टाटा स्टील, पावर ग्रिड, एशियन पेंट्स, एनटीपीसी और भारती एयरटेल प्रमुख रूप से नुकसान में रहें। दूसरी तरफ, लाभ में रहने वाले शेयरों में टाटा कंसल्टेंसी सर्विसेज, टेक महिंद्रा, इन्फोसिस, अडानी पोर्ट्स, एक्सिस बैंक और एचसीएल टेक शामिल हैं। रेलिगेयर ब्रोकिंग लिमिटेड के वरिष्ठ उपाध्यक्ष (शोध) अजीत मिश्रा ने कहा, 'वैश्विक संकेतों और रुपए से जुड़ी चिंताओं का निवेशक धारणा पर असर बना रहा। इसकी वजह से कारोबारियों ने सतर्कता बरती।'

व्यापक बाजार में मझोली कंपनियों का बीएसई मिडकैप सूचकांक 0.05 प्रतिशत चढ़ गया जबकि छोटी कंपनियों के स्मालकैप सूचकांक में 0.28 प्रतिशत की गिरावट दर्ज की गई।

कोर्ट ने जारी किया था गिरफ्तारी वारंट, सीएम फडणवीस ने खेल मंत्री माणिकराव कोकाटे का इस्तीफा मंजूर किया

मुंबई(संवाददाता)

मंत्र न्यूज

महाराष्ट्र के कैबिनेट मंत्री माणिकराव कोकाटे ने गुरुवार को उपमुख्यमंत्री अजीत पवार को अपना इस्तीफा सौंप दिया। उन्हें एक दिन पहले ही सभी मंत्री पद से हटा दिया गया था। नासिक की एक अदालत द्वारा 1995 के आर्थिक रूप से कमजोर वर्ग (ईडब्ल्यूएस) आवास आरक्षण धोखाधड़ी मामले में कोकाटे और उनके भाई विजय की गिरफ्तारी वारंट जारी करने के बाद कोकाटे को उनके सभी मंत्री पद खो दिए गए। कोकाटे को राज्य के 10 प्रतिशत आर्थिक रूप से कमजोर वर्ग (ईडब्ल्यूएस) आरक्षण के तहत अपनी आय कम बताकर दो फ्लैट हासिल करने के आरोप में दो साल के कठोर कारावास की सजा सुनाई गई है।

मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस ने कोकाटे का इस्तीफा स्वीकार कर लिया और आगे की कार्रवाई के लिए इसे राज्यपाल आचार्य देवव्रत को भेज दिया। राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी (एनसीपी) के मंत्री माणिकराव कोकाटे ने बुधवार को बॉम्बे उच्च न्यायालय में याचिका दायर कर धोखाधड़ी और जालसाजी के आरोपों में दोषी ठहराए जाने और दो साल की

जेल की सजा सुनाए जाने के निचली अदालत के आदेश पर रोक लगाने की मांग की। 67 वर्षीय कोकाटे ने निर्वाचित प्रतिनिधि के रूप में अपना कार्यकाल जारी रखने के लिए अपनी दोषसिद्धि और सजा पर रोक लगाने का अनुरोध किया है। लोक प्रतिनिधित्व अधिनियम, 1951 के तहत आपराधिक मामले में दो साल या उससे अधिक की कैद की सजा पाने वाले निर्वाचित प्रतिनिधियों को अयोग्य घोषित किया जाता है। कोकाटे की ओर से पेश हुए अधिवक्ता अनिकेत निकम ने न्यायमूर्ति आरएन लड्ढा के समक्ष तत्काल सुनवाई की मांग करते हुए याचिका का उल्लेख किया और कहा कि इस मामले में उनकी दोषसिद्धि और सजा के परिणामस्वरूप मंत्री पद से अयोग्य घोषित किया जा सकता है।

क्या है पूरा मामला

यह मामला 1989 से 1992 के बीच का है। राज्य सरकार ने जरूरतमंदो के लिए आवास योजना शुरू की। जरूरतमंद की परिभाषा थी, जिनकी वार्षिक आय 30 हजार रुपये से अधिक न हो। कोकाटे और उनके भाई विजय ने फ्लैट हासिल करने के लिए आय के संबंध में फर्जी हलफनामा दायर किया। आमदनी 30 हजार रुपये से कम बताई। दोनों को 1994 में नासिक में फ्लैट आवंटित किए गए। यानी उन्होंने EWS फ्लैट की पात्रता को लेकर झूठे दावे पेश किए थे। केस के रिकार्ड के मद्देनजर सत्र न्यायालय ने कोकाटे की सजा को कायम रखा। कोकाटे को IPC की धारा 420 (धोखाधड़ी), 465 (जाली दस्तावेज बनाना), 468 (धोखाधड़ी के उद्देश्य से जालसाजी) और 471 (बेईमानी से फर्जी दस्तावेजों का इस्तेमाल) में सजा सुनाई गई थी। अभियोजन पक्ष ने नासिक कोर्ट में फर्जीवाडे से जुड़े कई दस्तावेज पेश किए। जिन पर गौर करने के बाद निचली अदालत ने कोकाटे को राहत देने से इंकार कर दिया।

एकला चलो की राह पर अजित पवार, 50 सीटों के लिए बनाया प्लान

मुंबई(संवाददाता)

मंत्र न्यूज

अधिकांश शहरी स्थानीय निकायों में भाजपा और शिवसेना के एक साथ चुनाव लड़ने की संभावना है, जबकि राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी (एनसीपी) ने सत्तारूढ़ महायुति गठबंधन के भीतर और बाहर दोनों जगह चुनाव लड़ने की तत्परता जताई है। पार्टी की चुनाव निर्णय समिति की हाल ही में हुई बैठक में एनसीपी नेताओं ने कहा कि सभी संभावित स्थितियों के लिए तैयारियां पूरी हो चुकी हैं। आगामी नगर निगम चुनावों से पहले महाराष्ट्र में राजनीतिक गतिविधियां तेज हो गई हैं, और सभी पार्टियां गठबंधन की गणना और सीटों की तैयारियों में तेजी ला रही हैं।

एनसीपी मुंबई की 50 सीटों के लिए तैयार

सूत्रों के अनुसार, एनसीपी ने मुंबई की कम से कम 50 सीटों के लिए जमीनी तैयारी पूरी कर ली है। महायुति गठबंधन में पार्टी के बने रहने या न रहने का अंतिम निर्णय अजीत पवार द्वारा लिया जाना अपेक्षित है। राजनीतिक गलियारों में उनकी इस निर्णय पर गहरी नजर है, क्योंकि इससे राज्य में गठबंधन के समीकरणों में गंभीर बदलाव आ सकता है।

बीजेपी के विरोध के बावजूद नवाब मलिक पर भरोसा

बीजेपी के कड़े विरोध के बावजूद अजित पवार ने बीएमसी चुनाव की जिम्मेदारी को लेकर नवाब मलिक पर भरोसा बरकरार रखा है। एनसीपी के एक नेता ने बताया कि महायुति से चर्चा के लिए एक समन्वय समिति बनाई जा सकती है। मंत्री अदिति तटकरे, मुंबई के दो अन्य नेता सहित विधायक सना मलिक को इसमें शामिल करने पर चर्चा चल रही है। एनसीपी लीडर ने बताया कि अजित ने कहा है कि हम अंत तक महायुति चुनाव लड़ने की कोशिश करग। याद बात नहीं तो हमें अकेले मैदान में उतरने के लिए तैयार रहना चाहिए। वहीं, मुंबई बीजेपी अध्यक्ष अमित साटम ने कहा है कि अगर नवाब मलिक एनसीपी के चुनाव प्रमुख हैं, तो तो हम उनके साथ नहीं रह सकते।

क्यों अजित पवार के लिए मलिक जरूरी ?

वर्ष 2017 के बीएमसी चुनाव में एनसीपी (अविभाजित) के 9 नगरसेवक चुनकर आए थे। इसमें से दो पूर्व नगरसेवक अजित गुट और 2 शरद गुट के साथ है। बाकी शिंदे गुट में शामिल हो गए है। नवाब मलिक मुंबई में एनसीपी के लिए एक महत्वपूर्ण नेता है। नवाब की सेक्युलर इमेज के कारण मुस्लिम और दलित वोटर्स पर पकड़ है। मुंबई में एनसीपी ज्यादा ताकतवर नहीं है। अजित पवार के साथ मुंबई में नवाब मलिक का परिवार ही पार्टी की मजबूती है। इसलिए अजित नवाब को अकेला नहीं छोड़ना चाहते है। वर्ष 2024 के विधानसभा चुनाव में भी यही स्थिति पैदा हुई थी, तब पवार नवाब के साथ खड़े थे।

जमानत की पाबंदियों में ढील, बॉम्बे हाई कोर्ट ने गौतम नवलखा को दिल्ली लौटने की अनुमति दी,

मुंबई(संवाददाता)

मंत्र न्यूज

बॉम्बे हाई कोर्ट ने एल्गार परिषद-माओवादी संबंधों के मामले में आरोपी मानवाधिकार कार्यकर्ता गौतम नवलखा को मुकदमे की सुनवाई समाप्त होने तक मुंबई से दिल्ली स्थित उनके आवास पर स्थानांतरित होने की अनुमति दी। अदालत के इस फैसले में कुछ शर्तें भी हैं। 74 वर्षीय नवलाखा को अपना पासपोर्ट राष्ट्रीय जांच एजेंसी (एनआईए) को सौंपने के लिए कहा गया है और उन्हें एनआईए की विशेष अदालत से पूर्व अनुमति के बिना दिल्ली छोड़ने पर प्रतिबंध लगा दिया गया है। यह अदालत एल्गार परिषद-भीमा कोरेगांव हिंसा मामले में नवलाखा समेत 16 आरोपियों पर मुकदमा चला रही है। नवलाखा को यह भी आदेश दिया गया है कि आरोपियों के खिलाफ आरोप तय होने के समय वे ट्रायल कोर्ट में उपस्थित रहें और एनआईए के निर्देशानुसार उसके बाद की हर सुनवाई में भी शामिल हों। हालांकि, उन्हें जरूरत पड़ने पर मुंबई की र्कें स्पेशल कोर्ट में हाजिर होने का निर्देश दिया है। अदालत से छूट मिलने पर ही वे गैर हाजिर हो सकते है। हर शनिवार को नवलखा को दिल्ली के स्थानीय पुलिस स्टेशन में हाजरी लगानी होगी। उन्हें अपना पासपोर्ट जमा करना होगा। वे अदालत की अनुमति के बिना दिल्ली नहीं छोड़ सकते। आरोप तय होने के दौरान भी उन्हें मुंबई आना होगा।

पिछले दिनों नवलखा ने याचिका दायर कर कहा था कि मुंबई में रहना खर्चीला है इसलिए उन्हें दिल्ली स्थित उनके घर में लौटने की अनुमति दी जाए। दरअसल एनआईए की विशेष अदालत ने नवलखा को बेल देते समय शर्त लगाई थी कि वे अदालत की अनुमति के बिना मुंबई के बाहर नहीं जा सकते है। नवलखा ने हाई कोर्ट का दरवाजा खटखटाया। बेल मिलने के बाद दो सालों से वह अपने परिवार से अलग मुंबई में रह रहे थे। बेंच ने कहा कि नवलखा को अपनी स्वतंत्रता का अधिकार है लेकिन अभी तक वे स्वतंत्र व्यक्ति नहीं है। अदालत ने मंगलवार को मौखिक रूप से कहा था कि नवलखा के 'देश से फरार होने का खतरा' नहीं है, क्योंकि ऐसा कोई मामला सामने नहीं आया है, जब उन्होंने भागने की कोशिश की हो।

पशिचम रेलवे पर ऊर्जा संरक्षण सप्ताह 2025 का आयोजन

मुंबई(संवाददाता)

मंत्र न्यूज

रेलवे अपने नेटवर्क पर सतत विकास को बढ़ावा देने हेतु निरंतर महत्वपूर्ण कदम उठा रही है, जिससे ऊर्जा संरक्षण एवं पर्यावरणीय उत्तरदायित्व के प्रति उसकी प्रतिबद्धता और सुदृढ़ होती है। इसी क्रम में, पश्चिम रेलवे द्वारा राष्ट्रीय ऊर्जा संरक्षण दिवस (जो प्रत्येक वर्ष 14 दिसंबर को मनाया जाता है) के अवसर पर 08 से 14 दिसंबर 2025 तक ऊर्जा संरक्षण सप्ताह का आयोजन किया गया। इसका उद्देश्य ऊर्जा संरक्षण के प्रति जागरूकता फैलाना तथा पश्चिम रेलवे द्वारा इस दिशा में की गई पहलों को उजागर करना था।

पश्चिम रेलवे के मुख्य जनसंपर्क अधिकारी श्री विनीत अभिषेक द्वारा जारी एक प्रेस विज्ञप्ति के अनुसार, सप्ताह भर चले इस आयोजन के दौरान पश्चिम रेलवे के सभी छह मंडलों, पाँच कारखानों एवं मुख्यालय में विभिन्न ऊर्जा संरक्षण जागरूकता कार्यक्रम आयोजित किए गए। इनमें सेमिनार, पंपलेट का वितरण, रेलवे स्टेशनों पर सार्वजनिक घोषणाएँ, एसएमएस अलर्ट, बैनर प्रदर्शन आदि शामिल थे। इसके अतिरिक्त, निबंध लेखन एवं चित्रकला प्रतियोगिताओं जैसी सहभागितापूर्ण गतिविधियाँ भी

आयोजित की गईं, जिनका उद्देश्य रेलवे कर्मचारियों के साथ-साथ आम जनता को ऊर्जा संरक्षण के महत्व के प्रति संवेदनशील बनाना था।

ऊर्जा संरक्षण सप्ताह 2025 के अंतर्गत एक सेमिनार का आयोजन किया गया, जिसकी अध्यक्षता पश्चिम रेलवे के महाप्रबंधक विवेक कुमार गुप्ता ने की। इस सेमिनार में अपर महाप्रबंधक, प्रमुख विभागाध्यक्ष, मंडल रेल प्रबंधक, वरिष्ठ रेल अधिकारी एवं कर्मचारी उपस्थित रहे। सेमिनार में भारतीय रेल एवं पश्चिम रेलवे द्वारा सतत ऊर्जा उपयोग को बढ़ावा देने तथा राष्ट्रीय एवं वैश्विक जलवायु लक्ष्यों के समर्थन में निभाई जा रही महत्वपूर्ण भूमिका पर प्रकाश डाला गया।

विनीत ने आगे बताया कि ऊर्जा संरक्षण के क्षेत्र में वर्ष 2024-2025 के दौरान उत्कृष्ट कार्य करने वाले पंद्रह रेलवे अधिकारियों को उनकी उल्लेखनीय उपलब्धियों एवं ऊर्जा दक्षता बढ़ाने तथा नवोन्मेषी ऊर्जा बचत उपायों के कार्यान्वयन हेतु मेरिट प्रमाणपत्र एवं नकद पुरस्कार प्रदान कर सम्मानित किया गया।

अपने समापन संबोधन में महाप्रबंधक श्री विवेक कुमार गुप्ता ने पश्चिम रेलवे पर विभिन्न ऊर्जा संरक्षण पहलों की योजना, कार्यान्वयन एवं निगरानी के लिए विद्युत विभाग द्वारा किए जा रहे सतत एवं समर्पित प्रयासों की सराहना की। उन्होंने नवीन तकनीकों को अपनाने तथा कर्मचारियों एवं हितधारकों के बीच जागरूकता फैलाने के विभाग के सक्रिय दृष्टिकोण की प्रशंसा की।

महाप्रबंधक ने भविष्य में ऊर्जा संरक्षण उपायों को और अधिक सुदृढ़ एवं सतत बनाने हेतु महत्वपूर्ण मार्गदर्शन एवं सुझाव भी दिए। उन्होंने निरंतर निगरानी, नवीन ऊर्जा दक्ष तकनीकों को अपनाने, नवीकरणीय ऊर्जा के अधिक उपयोग तथा सभी विभागों की सामूहिक भागीदारी के महत्व पर बल दिया। उन्होंने अधिकारियों एवं कर्मचारियों से आग्रह किया कि वे दीर्घकालिक पर्यावरणीय एवं वित्तीय लाभ प्राप्त करने हेतु ऊर्जा संरक्षण को अपनी दैनिक कार्यप्रणाली का अभिन्न हिस्सा बनाएं। पश्चिम रेलवे संगठन के प्रत्येक स्तर पर ऊर्जा संरक्षण पहलों को सुदृढ़ करने एवं निरंतरता की संस्कृति को प्रोत्साहित करने के लिए निरंतर प्रतिबद्ध है।

बीजेपी शिवसेना की बैठक में हो गया फैसला, 150 सीटों के बंटवारे पर बनी सहमति

दिव्यांश

मुंबई(संवाददाता)

बृहन्मुंबई नगर निगम (बीएमसी) चुनावों से ठीक पहले एक महत्वपूर्ण कदम उठाते हुए, भारतीय जनता पार्टी (भाजपा) और शिवसेना के शीर्ष नेताओं ने गुरुवार (18 दिसंबर) को महत्वपूर्ण वार्ता की और सीट बंटवारे पर एक अहम समझौता किया, जिससे मुंबई के राजनीतिक परिदृश्य में बड़ा बदलाव आ सकता है। एशिया के सबसे धनी नगर निकाय, बीएमसी की 227 सीटों पर चुनाव होने हैं, ऐसे में गठबंधन का लक्ष्य विपक्षी प्रतिद्वंद्वियों के खिलाफ अपनी शक्ति को मजबूत करना है। यह बैठक एकता की दिशा में एक महत्वपूर्ण कदम है, जिसमें न केवल संख्या बल पर बल्कि चुनावों के लिए एक ठोस रणनीति पर भी ध्यान केंद्रित किया गया।

चर्चा का मुख्य बिंदु सीटों का आवंटन था, जिस पर दोनों दलों ने कुल 227 वार्डों में से 150 वार्डों के बंटवारे पर सहमति जताई। इससे 77 सीटें अभी भी खाली हैं, जिन पर नेताओं ने अगले दो से तीन दिनों के भीतर बातचीत पूरी करके अंतिम समझौते को अंतिम रूप देने का वादा किया है। वार्ता से जुड़े सूत्रों ने सकारात्मक संकेत दिए, जिससे पता चलता है कि गठबंधन धनी बीएमसी में अपनी अधिकतम सीटें जीतने के लिए उन गढ़ों को प्राथमिकता दे रहा है जिन पर जीत हासिल की जा सकती है। बीएमसी का बजट कई भारतीय राज्यों से भी अधिक है।

शीर्ष नेताओं द्वारा अंतिम सीट निर्धारण

सूत्रों के अनुसार, मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस और उपमुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे शेष 77 सीटों पर संयुक्त रूप से निर्णय लेंगे और जल्द ही औपचारिक घोषणा होने की उम्मीद है। गठबंधन स्तर की वार्ता अब अंतिम चरण में पहुंच गई है और सीट बंटवारे के फार्मूले पर गहन विचार-विमर्श लगातार जारी है। राजनीतिक गलियारों में यह उम्मीद जताई जा रही है कि आने वाले दिनों में सीट बंटवारे की पूरी योजना अंतिम रूप ले लेगी, जिससे बीएमसी चुनावों में भाजपा-शिवसेना के संयुक्त अभियान का मार्ग प्रशस्त होगा।

दिव्यांगों की शादी के बारे में पारंपरिक सोच बदलने के लिए सरकार की पहल

सरकार दिव्यांगों की शादी को बढ़ावा दे रही है- सेक्रेटरी तुकाराम मुंढे

मुंबई(संवाददाता)

मंत्र न्यूज

दिव्यांग कल्याण विभाग के सेक्रेटरी तुकाराम मुंढे ने कहा कि दिव्यांग अव्यांग विवाह प्रोत्साहन योजना में काफी सुधार किए गए हैं, और सब्सिडी की रकम बढ़ाकर इस स्कीम को और असरदार बनाया गया है। दिव्यांगों की शादी को लेकर समाज में जो सामाजिक और सांस्कृतिक गलतफहमियां हैं, उनका उनकी ज़िंदगी पर लंबे समय तक असर पड़ता है। दिव्यांगता को अक्सर नाकाबिलियत या अधिकारों की कमी के तौर पर देखा जाता है। इस संदर्भ में, इस सोच को बदलने की ज़रूरत पर ज़ोर देते हुए, सरकार ने दिव्यांगों की शादी को बढ़ावा देने के लिए यह अहम फ़ैसला लिया है।

सेक्रेटरी मुंढे ने कहा, दिव्यांग व्यक्ति की शादी माता-पिता की नज़र में एक मुश्किल ज़िम्मेदारी बन जाती है। अक्सर शादी टाल दी जाती है या कोई अलग साथी दे दिया जाता है। खासकर, दिव्यांग महिलाओं को महिलाओं और दिव्यांगों के तौर पर दोहरा भेदभाव झेलना पड़ता है। इस संदर्भ में, सरकार, सामाजिक और गैर-सरकारी संगठन दिव्यांगों को मुख्यधारा में लाने की कोशिश कर रहे हैं। दिव्यांग-अव्यांग विवाह प्रोत्साहन अनुदान स्कीम में बढ़ोतरी के साथ, दिव्यांग-दिव्यांग विवाह का एक नया हिस्सा शामिल किया गया है। नई बदली हुई स्कीम के अनुसार, दिव्यांग-अव्यांग विवाह के लिए 1,50,000 रुपये और दिव्यांग-दिव्यांग विवाह के लिए 2,50,000 रुपये की सब्सिडी दी जाएगी। सेक्रेटरी मुंढे ने कहा कि यह रकम डायरेक्ट बेनिफिट ट्रांसफर सिस्टम के ज़रिए पति-पत्नी के जॉइंट बैंक अकाउंट में जमा की जाएगी, और कपल के लिए इसका 50 परसेंट हिस्सा पांच साल के लिए फिक्स्ड डिपॉजिट में रखना ज़रूरी है।

स्कीम की मुख्य शर्तें

दुल्हन या दूल्हे के पास आधार के साथ एक वैलिड यूनिवर्सल आइडेंटिटी कार्ड (ळअ्छ) होना चाहिए और पर्सन्स विद डिसेबिलिटीज़ एक्ट के अनुसार कम से कम 40इ या उससे ज़्यादा डिसेबिलिटी होनी चाहिए। दिव्यांग दूल्हे या दुल्हन में से एक महाराष्ट्र राज्य का निवासी होना चाहिए। शादीशुदा दूल्हे और दुल्हन की पहली शादी होनी चाहिए और अगर दूल्हे या दुल्हन का तलाक हो चुका है, तो ऐसी मदद पहले नहीं ली गई होनी चाहिए।

शादी मैरिज रजिस्ट्रेशन ऑफिस में कानूनी तौर पर रजिस्टर होनी चाहिए। शादी के एक साल के अंदर, उन्हें इस स्कीम का फ़ायदा उठाने के लिए संबंधित डिस्ट्रिक्ट दिव्यांग एम्पावरमेंट ऑफिसर के पास अप्लाई करना होगा।

एप्लीकेंट को ज़रूरी डॉक्यूमेंट्स के साथ एक पूरा एप्लीकेशन डिस्ट्रिक्ट ऑफिस में जमा करना होगा। एलिजिबल बेनिफिशियरी का सिलेक्शन चीफ एग्जीक्यूटिव ऑफिसर, डिस्ट्रिक्ट काउंसिल की हेड वाली एक कमेटी करेगी। अप्रूव्ड बेनिफिशियरी की लिस्ट कमिश्नर, दिव्यांग वेलफेयर, पुणे को भेजी जाएगी और फंड दिए जाएंगे।

इस बारे में सरकार का फ़ैसला दिव्यांग वेलफेयर डिपार्टमेंट ने जारी किया है और यह महाराष्ट्र सरकार की वेबसाइट पर अवेलेबल है।

पशिचम रेलवे बांद्रा टर्मिनस एवं जयपुर के बीच चलाएगी स्पेशल ट्रेन

मुंबई(संवाददाता)

मंत्र न्यूज

पश्चिम रेलवे द्वारा यात्रियों की सुविधा तथा उनकी बढ़ती यात्रा मांग को ध्यान में रखते हुए बांद्रा टर्मिनस एवं जयपुर स्टेशनों के बीच विशेष किराये पर एक स्पेशल ट्रेन चलाई जाएगी।

पश्चिम रेलवे के मुख्य जनसंपर्क अधिकारी श्री विनीत अभिषेक द्वारा जारी एक प्रेस विज्ञप्ति के अनुसार, इस ट्रेन का विवरण इस प्रकार है:

ट्रेन संख्या 09704/09703 बांद्रा टर्मिनस - जयपुर स्पेशल (02 फेरे)

ट्रेन संख्या 09704 बांद्रा टर्मिनस - जयपुर स्पेशल शुक्रवार, 26 दिसंबर, 2025 को बांद्रा टर्मिनस से 10:15 बजे प्रस्थान करेगी तथा अगले दिन 07:30 बजे जयपुर पहुंचेगी।

इसी प्रकार, ट्रेन संख्या 09703 जयपुर - बांद्रा टर्मिनस स्पेशल गुरुवार, 25 दिसंबर, 2025 को जयपुर से 08:10 बजे प्रस्थान करेगी तथा अगले दिन 07:25 बजे बांद्रा टर्मिनस पहुंचेगी।

यह ट्रेन दोनों दिशाओं में बोरीवली, वापी, वलसाड, सूरत, वडोदरा, रतलाम, विक्रमगढ़ आलोट, भवानी मंडी, रामगंज मंडी, कोटा, सवाई माधोपुर एवं दुर्गापुरा स्टेशनों पर ठहरेगी।

इस ट्रेन में फर्स्ट एसी, एसी 2-टियर, एसी 3-टियर, स्लीपर क्लास तथा जनरल सेकेंड क्लास के कोच होंगे।

ट्रेन संख्या 09704 की बुकिंग 20 दिसम्बर, 2025 से सभी पीआरएस काउंटरों एवं आईआरसीटीसी की वेबसाइट पर शुरू होगी। ट्रेनों के ठहराव, समय एवं संरचना के संबंध में विस्तृत जानकारी के लिए यात्री कृपया www.enquiry .indianrail.gov .in पर जाकर अवलोकन कर सकते हैं।

पश्चिम मध्य रेल

सामग्री प्रबंधन विभाग

(भंडार आपूर्ति हेतु ई– निविदा सूचना, संख्या/ईपीएस/111/2025)

प्रमुख मुख्य सामग्री प्रबंधक, पश्चिम रेल भारत के राष्ट्रपति की ओर से ई–खरीद प्रणाली के जरिए निम्नलिखित विज्ञापन निविदाएं आमंत्रित करते है। कोई भी हस्तालिखित/डाक प्रस्ताव स्वीकार नही किए जाएंगे। पूर्ण विवरण/विनिर्देशन के लिए वेबसाईट https://ireps.gov.in पर 'ई' निविदा संबंधी जानकारी प्राप्त की सकती है।

क्र.	टेंडर नं.	संक्षिप्त वर्णन	निविदा मात्रा	नियत तारीख
1	8125WCRTP-01	रेट कॉन्ट्रैक्ट फॉर मैन्युफैक्चरिंग & सप्लाई ऑफ हाई Viscous नायलॉन–66 (HVN-66) इंसुलेटिंग लाइनर	1490000 नंबर	05.01.2026
2	38255017	एलस्टोमेरिक pad डिजाइन बी as per RDSO Drg- no- WD 21109-S-02, Alt-2,	23780 नंबर	08.01.2026
3	8125WCRTP-06	रेट कॉन्ट्रैक्ट फॉर मैन्युफैक्चरिंग – सप्लाई ऑफ हाई Viscous नायलॉन– 66 (HVN-66) इंसुलेटिंग लाइनर	1500000 नंबर	12.01.2026
4	8125WCRTP-03	Manufacture – सप्लाई ऑफ 1–in–12 Weldable कास्ट मैंगनीज स्टील क्रासिंग B.G. फॉर 60E1 रेल सेक्शन	590 सेट	15.01.2026
5	8125WCRTP-05	Manufacture एंड सप्लाई ऑफ 10 mm थिक कम्पोजिट Grooved रबर सोले प्लेट	2933420 नंबर	22.01.2026

50 लाख रूपये से कम अनुमानित मूल्य वाली निविदाओं के लिए इच्छुक फर्मों को www.ireps.gov.in पर जाने की सलाह दी जाती है।

(हस्ता)

कृते प्रमुख मुख्य सामग्री प्रबंधक, पश्चिम मध्य रेल, जबलपुर

स्वच्छ भारत अभियान एक कदम स्वच्छता की ओर

मध्य रेल

सोलापुर मंडल

निर्माण और आपूर्ति कार्य

भारत के राष्ट्रपति के लिए एवं उनकी ओर से मंडल स्टोर कार्यालय मध्य रेलवे, सोलापुर, निम्नलिखित कार्यों के लिए सक्षम, प्रतिष्ठित फर्मों/ठेकेदारों से रेलवे की ई-प्रोक्योरमेंट वेबसाइट **www.ireps.gov.in** पर ऑनलाइन ई-निविदाएं आमंत्रित करता है। **टेंडर नंबर संख्या: SUR/SR.DMM/T.NO. 96255648, दिनांक: 17.12.2025. विवरण**: 6400 मिमी. ओवर राइडिंग डिरेलिंग स्विच 8.5 में 1, टी / आउट बीजी (1673 मिमी) 60 किग्रा पीएससी स्लीपर्स पर आरडीएसओ ड्रॉइंग नंबर टी-6068 अल्ट. 4 के अनुसार नवीनतम बदलावों के साथ और स्पेसिफिकेशन नंबर आईआरएस: टी-10-2025 के अनुरूप, नवीनतम शुद्धिपत्र के साथ जो टैंडर बंद होने की वास्तविक तारीख तक जारी किया गया हो। **मात्रा**: 36 सेट। **बयाना राशि (INR)**: रु. 218380/-. **www.ireps.gov.in पर निविदा बंद होने की तिथि और समय 12.01.2026 11:30 बजे के बाद**। संभावित निविदाकर्ताओं को सलाह दी जाती है कि वे निविदा समाप्ति की तिथि से पहले वेबसाइट पर बार-बार विजिट करते रहें ताकि इस निविदा के लिए जारी किए गए किसी भी परिवर्तन / शुद्धिपत्र पर ध्यान दिया जा सके। वेबसाइट: **www.ireps.gov.in**

वरिष्ठ मंडल सामग्री प्रबंधक मध्य रेल, सोलापुर

DE/Sur-73

खतरनाक व विस्फोटक सामान के साथ यात्रा करना दंडनीय अपराध है

मध्य रेल

सोलापुर मंडल

निर्माण और आपूर्ति कार्य

भारत के राष्ट्रपति के लिए एवं उनकी ओर से मंडल स्टोर कार्यालय मध्य रेलवे, सोलापुर, निम्नलिखित कार्यों के लिए सक्षम, प्रतिष्ठित फर्मों/ठेकेदारों से रेलवे की ई-प्रोक्योरमेंट वेबसाइट **www.irep.gov.in** पर ऑनलाइन ई-निविदाएं आमंत्रित करता है। **टेंडर नंबर संख्या: SUR/SR.DMM/T.NO. 96255643, दिनांक: 17.12.2025. विवरण**: 60 किग्रा. रेल के लिए जॉगल्ड फिश प्लेट्स का निर्माण और आपूर्ति, जो आरडीएसओ ड्रॉइंग नंबर टी5849 के अनुसार हो, जॉगल्ड फिश प्लेट्स में शामिल हैं: **(i)** आरडीएसओ ड्रॉइंग नंबर टी-5849 के अनुसार 4 छेद वाली जॉगल्ड फिश प्लेट्स 2 नग **(ii)** ड्रॉइंग नंबर टी 11513 के अनुसार बोल्ट और नट 4 नग **(iii)** आरडीएसओ ड्रॉइंग नंबर टी-10773 के अनुसार सिंगल कॉइल स्प्रिंग वॉशर 4 नग और **(iv)** ड्रॉइंग के अनुसार स्पेशल वॉशर (50X50 मिमी.) और 10 मिमी. मोटा जिसमें 27 मिमी. व्यास का छेद हो 8 नग। विनिर्देश: फिश प्लेट्स आईआरएस टी-1-2021 (रिव. 01) (टेंडर बंद होने की तारीख तक नवीनतम बदलाव और संशोधित विनिर्देशों के साथ) के अनुरूप होनी चाहिए। **मात्रा**: 2584 सेट। **बयाना राशि (INR)**: रु. 267100/-. **www.ireps.gov.in पर निविदा बंद होने की तिथि और समय 14.01.2026 11:30 बजे के बाद**। संभावित निविदाकर्ताओं को सलाह दी जाती है कि वे निविदा समाप्ति की तिथि से पहले वेबसाइट पर बार-बार विजिट करते रहें ताकि इस निविदा के लिए जारी किए गए किसी भी परिवर्तन / शुद्धिपत्र पर ध्यान दिया जा सके। वेबसाइट: **www.ireps.gov.in**

वरिष्ठ मंडल सामग्री प्रबंधक मध्य रेल, सोलापुर

DE/Sur-72

खतरनाक व विस्फोटक सामान के साथ यात्रा करना दंडनीय अपराध है

मध्य रेल

ई-निविदा सूचना

उप मुख्य सामग्री प्रबंधक (स.मा.वि .) सवारी व मालडिब्बा कारखाना माटुंगा, मुंबई - 400019. **निविदा सूचना No. CWE/MTN/85257438 /2025 due on 20/01/26. निविदा विवरण**: 125 लीटर स्टेनलेस स्टील एयर जलाशय आईसीएफ ड्राइंग संख्या आईसीएफ/एसटीडी - 3 - 5-039 एएलटी-एफ **मात्रा: 288 Nos. नियत तारीख**: 20.01.2026. **राशि**: 8665920.

DE-751

खतरनाक व विस्फोटक सामान के साथ यात्रा करना दंडनीय अपराध है

महाराष्ट्र भूषण राम सुतार का राजकीय सम्मान के साथ अंतिम संस्कार- मुख्यमंत्री फडणवीस ने श्रद्धांजलि दी

मुंबई(संवाददाता)

मंत्र न्यूज

विश्व प्रसिद्ध मूर्तिकार महाराष्ट्र भूषण राम सुतार का राजकीय सम्मान के साथ नोएडा के वैकुंठ श्मशान घाट में अंतिम संस्कार किया गया। महाराष्ट्र सरकार की ओर से प्रोटोकॉल और मार्केटिंग राज्य मंत्री जयकुमार रावल ने पुष्पांजलि अर्पित की। केंद्रीय सामाजिक न्याय राज्य मंत्री रामदास आठवले ने भी श्रद्धांजलि दी।

दुनिया की सबसे ऊंची मूर्ति, 'स्टैच्यू ऑफ यूनिटी' के मूर्तिकार राम वंजी सुतार का 101 साल की उम्र में नोएडा स्थित अपने आवास पर बुढ़ापे के कारण निधन हो गया। दिवंगत सुतार का अंतिम संस्कार दोपहर में नोएडा के वैकुंठ भूमि में पूरे राजकीय सम्मान के साथ किया गया। इस अवसर पर महाराष्ट्र सरकार की ओर से मार्केटिंग मंत्री जयकुमार रावल ने श्रद्धांजलि दी। रावल ने कहा, पद्म विभूषण राम सुतार, विश्व प्रसिद्ध महान मूर्तिकार, ने 'स्टैच्यू ऑफ यूनिटी' सहित कई ऐतिहासिक मूर्तियों के माध्यम से भारत को वैश्विक स्तर पर पहुंचाया। उनके निधन से कला क्षेत्र को बहुत बड़ी क्षति हुई है। पूर्णता और जीवंतता उनकी कला की पहचान थी। उनकी मूर्तियां हमेशा उनके महान कार्य की गवाह रहेंगी।

इस अवसर पर केंद्रीय सामाजिक न्याय राज्य मंत्री रामदास आठवले ने कहा कि महाराष्ट्र के सपूत राम सुतार ने मूर्तिकला के क्षेत्र में बहुत बड़ा योगदान दिया है। उन्होंने छत्रपति शिवाजी महाराज, महात्मा गांधी, डॉ. बाबासाहेब अंबेडकर सहित कई गणमान्य व्यक्तियों की मूर्तियां बनाईं। उन्होंने दिल्ली में रहकर महाराष्ट्र की प्रतिष्ठा बढ़ाई। उनकी कलाकृतियां अमर रहेंगी। उनके बेटे उनकी विरासत को आगे बढ़ाएंगे, आठवले ने यह भी कहा।

अंतिम संस्कार से पहले, दिवंगत सुतार का पार्थिव शरीर दर्शन के लिए उनके आवास पर रखा गया था। इस अवसर पर, महाराष्ट्र सरकार के रेजिडेंट कमिश्नर और सचिव आर विमला, सूचना निदेशक हेमराज बागुल, सहायक रेजिडेंट कमिश्नर नितिन शेंडे ने महाराष्ट्र सरकार के संस्कृति विभाग की ओर से श्रद्धांजलि दी। साथ ही, गौतम बुद्ध नगर के जिला कलेक्टर मेधा रूपम ने उत्तर प्रदेश सरकार की ओर से श्रद्धांजलि दी। दिवंगत सुतार के प्रशंसकों के साथ-साथ कला, सामाजिक और राजनीतिक क्षेत्रों के गणमान्य व्यक्तियों ने उनके पार्थिव शरीर को श्रद्धांजलि दी। इस अवसर पर उनके बेटे अनिल सुतार और उनके परिवार के सदस्य मौजूद थे। पिछले महीने, सुतार को 'महाराष्ट्र भूषण 2024' पुरस्कार से सम्मानित किया गया था। यह पुरस्कार उन्हें नोएडा में उनके घर पर मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस, उपमुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे और उपमुख्यमंत्री अजीत पवार, और सांस्कृतिक मामलों के मंत्री एडवोकेट आशीष शेलार ने प्रदान किया था।

मुख्यमंत्री फडणवीस की भावभीनी श्रद्धांजलि

मुख्यमंत्री फडणवीस ने सुतार के बेटे अनिल सुतार को फोन करके अपनी संवेदना व्यक्त की। उन्होंने कहा, 'कुछ दिन पहले, हम उन्हें 'महाराष्ट्र भूषण' पुरस्कार देने उनके घर गए थे। जब उन्होंने पुरस्कार लेते समय 'महाराष्ट्र माझा' गाने की पंक्तियाँ सुनाईं, तो हम भावुक हो गए। 100 साल की उम्र में भी, वे इंदु मिल में डॉ. बाबासाहेब अंबेडकर स्मारक के काम में लगे हुए थे। उनकी मूर्तियाँ सदियों तक जीवित रहेंगी और हर बार जब हम हर मूर्ति को देखेंगे, तो हमें उनकी याद आएगी। हम उन्हें दिल से श्रद्धांजलि देते हैं। हम उनके परिवार के दुख में शामिल हैं।'

उपमुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे की भावभीनी श्रद्धांजलि

उपमुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे ने कहा है कि राम सुतार के निधन से मूर्तिकला का 'कोहिनूर' समय के पर्दे के पीछे चला गया है। उन्होंने भारतीय संस्कृति और महापुरुषों के विचारों को दुनिया तक पहुँचाया।

वे 'स्टैच्यू ऑफ यूनिटी' और संसद में महात्मा गांधी की मूर्ति जैसी अपनी अमर कलाकृतियों के कारण हमेशा जीवित रहेंगे। 100 साल की उम्र तक कला का अभ्यास करने वाले सुतार ने हजारों कलाकारों का मार्गदर्शन किया। शिंदे ने यह भी कहा कि उनके निधन से ऐसा लगता है कि मूर्तिकला के विश्वविद्यालय ने अपनी शान खो दी है।

उपमुख्यमंत्री अजीत पवार की भावभीनी श्रद्धांजलि

उपमुख्यमंत्री अजीत पवार ने अपनी संवेदना व्यक्त करते हुए कहा कि राम सुतार के निधन से मूर्तिकला के क्षेत्र के भीष्म पितामह समय के पर्दे के पीछे चले गए हैं। उन्होंने छत्रपति शिवाजी महाराज, महात्मा गांधी, डॉ. बाबासाहेब अंबेडकर, सरदार पटेल जैसे महापुरुषों की मूर्तियों के माध्यम से देश के इतिहास को जीवंत किया और भारतीय स्मारकीय मूर्तियों को वैश्विक पहचान दिलाई। ग्रामीण इलाकों से निकले इस सरल और विनम्र मूर्तिकार ने जीवन के अंत तक कला का अभ्यास किया और कई कलाकारों को बनाया। उनकी मूर्तियाँ युगों तक याद की जाती रहेंगी। यह प्रार्थना करते हुए कि उनके परिवार वालों को दुख सहने की शक्ति मिले, उपमुख्यमंत्री अजीत पवार ने दिल से श्रद्धांजलि दी।

सांस्कृतिक मामलों के मंत्री एडवोकेट आशीष शेलार की संवेदनाएं

सांस्कृतिक मामलों के मंत्री एडवोकेट आशीष शेलार ने अपनी संवेदनाएं व्यक्त करते हुए कहा कि राम सुतार ने न केवल मूर्तियों को आकार दिया, बल्कि राष्ट्र की भावना, संस्कृति के गौरव और इतिहास की जीवंत दृष्टि को भी मूर्त रूप दिया। उनकी प्रतिभा ने वैश्विक स्तर पर भारत की पहचान को रोशन किया। यह उज्ज्वल विरासत हमेशा याद रखी जाएगी।

राज्य के 21 जिलों में विशेष सिकल सेल स्क्रीनिंग अभियान- स्वास्थ्य मंत्री प्रकाश आबिटकर

मुंबई। सिकल सेल स्क्रीनिंग के लिए विशेष पखवाड़े अभियान के तहत, राज्य के 21 जिलों में जहां सिकल सेल बीमारी ज़्यादा है, वहां हर नागरिक की सिकल सेल स्क्रीनिंग की जानी चाहिए। सार्वजनिक स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्री प्रकाश आबिटकर ने निर्देश दिया है कि यह सुनिश्चित करने के लिए सख्त कदम उठाए जाएं कि कोई भी नागरिक सिकल सेल स्क्रीनिंग से वंचित न रहे।

स्वास्थ्य मंत्री आबिटकर की कैबिनेट में सार्वजनिक स्वास्थ्य विभाग के विभिन्न मुद्दों पर एक समीक्षा बैठक हुई। इस बैठक में स्वास्थ्य विभाग के सचिव ई. रविंद्रन, स्वास्थ्य आयुक्त डॉ. कादंबरी बालकवड़े, स्वास्थ्य निदेशक डॉ. विजय कांडेवाड, संयुक्त निदेशक डॉ. सुनीता गोलहाइट और वरिष्ठ अधिकारी मौजूद थे।

सार्वजनिक स्वास्थ्य विभाग की ओर से राज्य में 18 दिसंबर से 15 जनवरी 2026 तक सिकल सेल अभियान की तैयारी की जाएगी। इसके बाद, 15 जनवरी से 31 जनवरी 2026 तक 'सिकल सेल स्क्रीनिंग विशेष पखवाड़ा' आयोजित किया जाएगा। इसे लागू किया जाएगा। इस स्क्रीनिंग अभियान के दौरान, सभी एजेंसियां प्रभावी योजना बनाएं ताकि सिकल सेल बीमारी के ज़्यादा मामलों वाले 21 जिलों में कोई भी नागरिक स्क्रीनिंग से वंचित न रहे। सिकल सेल बीमारी का जल्दी पता लगाना, मरीजों को उचित इलाज और रेफरल सेवाएं प्रदान करना बहुत महत्वपूर्ण है, और राज्य में कोई भी सिकल सेल मरीज स्क्रीनिंग से वंचित नहीं रहना चाहिए, मंत्री आबिटकर ने यह भी कहा।

इस मौके पर स्वास्थ्य मंत्री ने यह भी साफ किया कि सार्वजनिक स्वास्थ्य विभाग के तहत काम करने वाले मेडिकल अधिकारियों और कर्मचारियों का वेतन हर महीने की 1 तारीख से 5 तारीख के बीच दिया जाना चाहिए। वेतन भुगतान में देरी होने पर संबंधित अधिकारी को जिम्मेदार ठहराया जाएगा, मंत्री आबिटकर ने यह भी साफ किया।

स्वास्थ्य मंत्री ने जिला स्वास्थ्य संस्थानों को यह भी निर्देश दिया कि वे केवल ज़रूरत के हिसाब से खरीदारी करें, अनावश्यक खर्च से बचें और अपने काम में पारदर्शिता बनाए रखें।

उपमुख्यमंत्री अजीत पवार की ओर से वरिष्ठ मूर्तिकार को श्रद्धांजलि

मूर्तिकला के भीष्म पितामह राम सुतार को भावभीनी श्रद्धांजलिः पर्दे के पीछे - उपमुख्यमंत्री अजीत पवार

मुंबई(संवाददाता)

मंत्र न्यूज

उपमुख्यमंत्री अजीत पवार ने शोक व्यक्त करते हुए कहा है कि वरिष्ठ मूर्तिकार राम सुतार के निधन से मूर्तिकला के क्षेत्र में एक स्वर्णिम युग का अंत हो गया है और इस क्षेत्र के भीष्म पितामह समय के पर्दे के पीछे चले गए हैं।

उपमुख्यमंत्री अजीत पवार ने अपने शोक संदेश में कहा है कि राम सुतार ने दुनिया के हर कोने में सैकड़ों मूर्तियां बनाईं। उनकी हर मूर्ति अद्वितीय सुंदरता का एक अद्भुत उदाहरण है। उन्होंने छत्रपति शिवाजी महाराज, महात्मा गांधी, डॉ. बाबासाहेब अंबेडकर, सरदार वल्लभभाई पटेल जैसे महापुरुषों की मूर्तियों के माध्यम से देश के इतिहास को जीवंत किया। उन्होंने इन महापुरुषों के कार्यों और विचारों को सभी तक पहुंचाया। पिछले महीने, जब उनका स्वास्थ्य ठीक नहीं था, तो राज्य सरकार ने मुख्यमंत्री की उपस्थिति में नोएडा स्थित उनके आवास पर उन्हें महाराष्ट्र भूषण पुरस्कार से सम्मानित किया था।

राम सुतार महाराष्ट्र के धुले जिले के ग्रामीण इलाके से आए थे और उन्होंने दिल्ली में अपनी पहचान बनाई। उन्होंने अपनी आखिरी सांस तक काम किया। यह उनके काम के प्रति उनके समर्पण को दर्शाता है। इतनी ऊँची स्थिति पर पहुँचने के बाद भी वे सभी से आत्मीयता और स्नेह से बात करते थे। सादगी और विनम्रता उनके स्थायी गुण थे। देश भर में कई मूर्तिकारों को गढ़ने में उनका बहुमूल्य योगदान था। हालांकि पत्थर से जीवंत भावनाएं गढ़ने वाला जादूगर आज हमारे बीच नहीं रहा, लेकिन उनके द्वारा बनाई गई मूर्तियां सदियों तक हमें उनकी याद दिलाती रहेंगी। राम सुतार के निधन से हमने एक ऐसे अत्यंत प्रतिभाशाली मूर्तिकार को खो दिया है जिसने भारतीय स्मारक मूर्तियों को वैश्विक पहचान दिलाई। उनके परिवार को इस दुख को सहने की शक्ति मिले, यह प्रार्थना करते हुए उपमुख्यमंत्री अजीत पवार ने राम सुतार को भावभीनी श्रद्धांजलि अर्पित की है।

पश्चिम रेलवे का वसई रोड एवं भायंदर स्टेशनों के बीच मध्यरात्रि को रात्रिकालीन ब्लॉक

मुंबई(संवाददाता)। पश्चिम रेलवे द्वारा रेलपथ, सिगनलिंग प्रणाली तथा ऊपरी उपस्करों के रख-रखाव हेतु शुक्रवार/शनिवार की मध्यरात्रि अर्थात 19/20 दिसम्बर, 2025 को वसई रोड एवं भायंदर स्टेशनों के बीच अप एवं डाउन फास्ट लाइनों पर 05.15 घंटे का जम्बो ब्लॉक लिया जाएगा।

पश्चिम रेलवे के मुख्य जनसंपर्क अधिकारी श्री विनीत अभिषेक द्वारा जारी एक प्रेस विज्ञप्ति के अनुसार, यह ब्लॉक भायंदर एवं वसई रोड स्टेशनों के बीच अप फास्ट लाइन पर 23:30 बजे से 03:00 बजे तक, जबकि डाउन फास्ट लाइन पर 01:15 बजे से 04:45 बजे तक रहेगा। ब्लॉक अवधि के दौरान विरार और भायंदर/बोरीवली स्टेशनों के बीच फास्ट लाइन की सभी ट्रेनें स्लो लाइन पर चलाई जाएंगी।

पर्यावरण मंत्री ने जालना और छत्रपति संभाजीनगर में प्रदूषण नियंत्रण उपायों की समीक्षा की

जालना में वायु प्रदूषण कम करने के लिए तुरंत कदम उठाएं- पर्यावरण मंत्री पंकजा मुंडे

मुंबई(संवाददाता)

मंत्र न्यूज

पर्यावरण और जलवायु परिवर्तन मंत्री पंकजा मुंडे ने जालना और छत्रपति संभाजीनगर में प्रदूषण कम करने के मुद्दे की समीक्षा की। जालना में वायु प्रदूषण पर चिंता जताते हुए, प्रदूषण कम करने के लिए उचित कदम उठाने चाहिए। पर्यावरण मंत्री मुंडे ने उच्च-स्तरीय अधिकारियों के साथ बैठक करने और प्रदूषण फैलाने वाले उद्योगों के खिलाफ तुरंत कार्रवाई करने का भी निर्देश दिया।

पर्यावरण मंत्री मुंडे ने आज मंत्रालय में जालना इंडस्ट्रियल एस्टेट के साथ-साथ छत्रपति संभाजीनगर के वालुंज, शेंद्रा और ऑरिक सिटी इंडस्ट्रियल एस्टेट में वायु और जल प्रदूषण के संबंध में एक बैठक की। इस अवसर पर, विभाग की सचिव जयश्री भोज, महाराष्ट्र प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड के सदस्य सचिव एम. देवेंद्र सिंह, संयुक्त निदेशक (वायु प्रदूषण) सतीश पडवाल, साथ ही दोनों जिलों के क्षेत्रीय अधिकारी, औद्योगिक विकास निगम के अधिकारी और जिला प्रशासन के अधिकारी वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से उपस्थित थे।

जालना इंडस्ट्रियल एस्टेट में स्टील उद्योग धूल के कणों के कारण वायु प्रदूषण फैला रहा है। इस संबंध में कई शिकायतें मिली हैं। ये धूल के कण नागरिकों के स्वास्थ्य को प्रभावित कर रहे हैं और इन्हें नियंत्रित करना आवश्यक है। इसलिए, संबंधित कंपनियों को धूल के कणों को नियंत्रित करने के लिए प्राथमिक वायु प्रदूषण नियंत्रण प्रणालियों में सुधार के बारे में सूचित किया जाना चाहिए। पर्यावरण मंत्री मुंडे ने ऐसे सिस्टम स्थापित नहीं करने वालों के खिलाफ सख्त कार्रवाई करने का निर्देश दिया।

छत्रपति संभाजीनगर के वालुंज इंडस्ट्रियल एस्टेट में जल प्रदूषण को रोकने के लिए एक सीवेज ट्रीटमेंट यूनिट काम कर रही है। यहां के सीवेज के 100 प्रतिशत रीसाइक्लिंग की अनुमति दी गई है। इसलिए, मंत्री मुंडे ने निर्देश दिया कि यहां संसाधित पानी को खाम नदी में छोड़ने के बजाय उसका पुनः उपयोग करने के लिए उचित सावधानी बरती जानी चाहिए।

महाराष्ट्र प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड के सदस्य सिंह ने जालना और वालुंज में प्रदूषण के बारे में जानकारी दी और प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड द्वारा की जा रही कार्रवाई के बारे में बताया। जालना इंडस्ट्रियल एस्टेट में वायु प्रदूषण के स्तर की जांच के लिए एक मोबाइल वाहन द्वारा वायु गुणवत्ता निगरानी की जा रही है। उन्होंने यह भी बताया कि वालुंज इंडस्ट्रियल एस्टेट में अपशिष्ट जल परियोजना में संसाधित अपशिष्ट जल नहीं भेजने वाले 53 उद्योगों को निर्देश दिए गए हैं।

आईआरसीटीसी पश्चिम क्षेत्र, मुंबई द्वारा अक्टूबर 2025 के 'कर्मचारी ऑफ द मंथ' सम्मानित

मुंबई(संवाददाता)

मंत्र न्यूज

मुंबई। भारतीय रेल खानपान एवं पर्यटन निगम लिमिटेड (आईआरसीटीसी), रेल मंत्रालय, भारत सरकार के अधीन एक नवरत्न सार्वजनिक क्षेत्र उपक्रम, अपने कर्मचारियों के उत्कृष्ट प्रदर्शन को निरंतर प्रोत्साहित एवं सम्मानित करता रहा है।

इसी क्रम में, आईआरसीटीसी पश्चिम क्षेत्र, मुंबई कार्यालय में आयोजित एक समारोह के दौरान अक्टूबर 2025 के 'कर्मचारी ऑफ द मंथ' पुरस्कार प्रदान किए गए।

सुआरती राव, कैटरिंग असिस्टेंट, क्षेत्रीय कार्यालय, भोपाल तथा शुभम चव्हाण, सहायक स्टाफ, मानव संसाधन (एचआर) आंचलिक कार्यालय, मुंबई को अक्टूबर 2025 माह के दौरान उनके उत्कृष्ट कार्य एवं समर्पण के लिए सम्मानित किया गया। सम्मानित कर्मचारियों को उनके उत्कृष्ट योगदान के लिए मेरिट प्रमाण पत्र एवं नकद पुरस्कार प्रदान किए गए।

यह पुरस्कार गौरव झा, समूह महाप्रबंधक, आईआरसीटीसी पश्चिम क्षेत्र, मुंबई द्वारा प्रदान किए गए। इस अवसर पर वरिष्ठ अधिकारीगण हर्षवर्धन सिंह रावत, अपर महाप्रबंधक (पर्यटन); सुभाष नायर, प्रबंधक (पर्यटन) तथा नागेश चौधरी, प्रबंधक (मानव संसाधन), आईआरसीटीसी पश्चिम क्षेत्र, मुंबई उपस्थित रहे।

डॉ. ए.के. सिंह, जनसंपर्क अधिकारी, आईआरसीटीसी पश्चिम क्षेत्र, मुंबई ने बताया कि यह कर्मचारी सम्मान पहल वर्तमान वित्तीय वर्ष में समूह महाप्रबंधक गौरव झा द्वारा प्रारंभ की गई थी। अब तक इस पहल के अंतर्गत कुल आठ कर्मचारियों को सम्मानित किया जा चुका है।

आईआरसीटीसी पश्चिम क्षेत्र अपने कर्मचारियों के योगदान को निरंतर प्रोत्साहित कर उत्कृष्टता, नवाचार एवं ग्राहक-केंद्रित सेवाओं की संस्कृति को सुदृढ़ करने के लिए प्रतिबद्ध है।

धुले जिले के सपूत, कला जगत के महान भीष्माचार्य महाराष्ट्र भूषण राम सुतार का निधन हो गया है- मंत्री जयकुमार रावल

मुंबई(संवाददाता)

मंत्र न्यूज

मुंबई। धुले जिले के विश्व प्रसिद्ध मूर्तिकार, महाराष्ट्र भूषण राम सुतार का आज नोएडा स्थित उनके आवास पर 101 वर्ष की आयु में निधन हो गया। उनके निधन की खबर बहुत दुखद है। उनके निधन से देश के कला क्षेत्र को बहुत बड़ी क्षति हुई है और कला क्षेत्र ने उनके रूप में एक भीष्माचार्य खो दिया है, वाणिज्य और शाही प्रोटोकॉल राज्य मंत्री जयकुमार रावल ने शोक व्यक्त करते हुए कहा।

राम सुतार ने अपनी प्रतिभाशाली, समर्पित और ईमानदार कला के माध्यम से 'स्टैच्यू ऑफ यूनिटी' सहित कई अमर मूर्तियां बनाईं।

दुनिया की सर्वश्रेष्ठ मूर्तियां बनाने के लक्ष्य को ध्यान में रखते हुए, उन्होंने जीवन भर कला के क्षेत्र में अथक सेवा की। उन्होंने कई महापुरुषों की मूर्तियां बनाते समय अपार मेहनत, साहस और अद्वितीय समर्पण दिखाया।

उन्होंने भगवान बुद्ध, भगवान महावीर, स्वामी विवेकानंद सहित कई महान हस्तियों की मूर्तियां बहुत जीवंत और मनमोहक शैली में बनाईं। उनकी अनूठी मूर्तिकला के कारण देश के साथ-साथ धुले जिले का नाम भी विदेशों तक पहुंचा है। मंत्री जयकुमार रावल ने कहा।

भारतीय कला, संस्कृति और मूर्तिकला परंपरा को अपूरणीय क्षति- मंत्री एडवोकेट आशीष शेलार

मुंबई(संवाददाता)

मंत्र न्यूज

मुंबई। जाने-माने मूर्तिकार पद्म राम सुतार के निधन से भारतीय कला, संस्कृति और कलात्मक परंपरा को अपूरणीय क्षति हुई है। उन्होंने अपने प्रतिभाशाली हाथों से जो अनगिनत मूर्तियां बनाईं, वे सिर्फ पत्थर और धातु की कलाकृतियां नहीं हैं, बल्कि हमारे राष्ट्र की पहचान और गौरव बन गई हैं, सांस्कृतिक मामलों के मंत्री एडवोकेट आशीष शेलार ने अपनी संवेदना व्यक्त की।

राम सुतार ने अपने लंबे करियर के माध्यम से भारतीय मूर्तिकला को वैश्विक पहचान दिलाई। 'स्टैच्यू ऑफ यूनिटी' सहित उनके कई काम देशभक्ति, सांस्कृतिक जड़ों और कलात्मक उत्कृष्टता को दर्शाते हैं। हालांकि एक महान कलाकार हमें छोड़कर चले गए हैं, लेकिन उनकी कलाकृतियां और उनसे मिली प्रेरणा हमेशा जीवित रहेंगी।

इस दुखद अवसर पर, मैं दिवंगत राम सुतार को अपनी हार्दिक श्रद्धांजलि अर्पित करता हूं। मैं उनके परिवार के प्रति अपनी संवेदना व्यक्त करता हूं। ईश्वर उनकी आत्मा को शांति दे, मंत्री एडवोकेट शेलार ने अपनी संवेदना व्यक्त करते हुए कहा।

कांदिवली-बोरीवली सेक्शन पर 6वीं लाइन कार्य हेतु ट्रैफिक कार्य आदेश जारी

मुंबई(संवाददाता)। बोरीवली-कांदिवली सेक्शन के बीच 6वीं लाइन के कार्य को ध्यान में रखते हुए 20 दिसंबर, 2025 से 30 दिनों की अवधि के लिए ट्रैफिक ब्लॉक लिया जाएगा। इस अवधि के दौरान कुछ ट्रेनों को शॉर्ट टर्मिनेट/शॉर्ट ओरिजिनेट किया जाएगा, कुछ ट्रेनों का समय रेगुलेट एवं रिशेड्युल किया जाएगा तथा कुछ ट्रेनें बोरीवली स्टेशन पर अपने निर्धारित ठहराव के अनुसार नहीं ठहरेंगी।

विस्तृत व्यवस्था निम्नलिखित परिशिष्टों (एनेक्सर्स) में दी गई हैः परिशिष्ट-I: शॉर्ट टर्मिनेट/शॉर्ट ओरिजिनेट एवं निरस्?त की जाने वाली ट्रेनें। परिशिष्ट-II: रिशेड्युल की जाने वाली ट्रेनें। परिशिष्ट-III: रेगुलेट की जाने वाली ट्रेनें

परिशिष्ट-IV बोरीवली स्टेशन पर नहीं ठहरने वाली ट्रेनें तथा जिन्हें वसई रोड एवं अंधेरी।

स्टेशनों पर अतिरिक्त ठहराव प्रदान किया गया है।

सम्पादकीय

कोहरे और प्रदूषण के बीच बढ़ी लापरवाही, हादसों पर भारी चुप्पी और जवाबदेही किसी की नहीं

गहराते प्रदूषण संकट के बीच ठंड बढ़ने के साथ ही कोहरे की मार पड़ने लगी है। राष्ट्रीय राजमार्गों पर आए दिन गाड़ियों के टकराने की खबरें आ रही हैं। मंगलवार को धुंध के कारण यमुना एक्सप्रेसवे पर आगरा से नोएडा के बीच सात बसों और तीन गाड़ियों के टकराने एवं कई अन्य शहरों में भी इसी तरह की दुर्घटनाओं में 25 लोगों की जान जाने के बाद यह बहस तेज हो गई है कि जवाबदेही कौन लेगा और कैसे रोकथाम के लिए कोई रास्ता निकलेगा।

अभी तक तो प्रदूषण एवं धुंध के कारण बढ़ते संकट के बीच राजनीतिक बयानबाजी भर सामने आती रही है और जिम्मेदारी से बचने की कोशिश में सत्ता प्रतिष्ठान एवं प्रशासन दिखा है। हालात ये हैं कि सुप्रीम कोर्ट की तल्ख टिप्पणियों का कोई असर नहीं पड़ रहा है। दिल्ली और आसपास के इलाकों में प्रदूषण की समस्या धीरे-धीरे गंभीर होती है और धुंध बढ़ने के साथ राजमार्गों पर दुर्घटनाएं बढ़ने लगती हैं। राजमार्गों पर धुंध के बीच रफ्तार पर लगाम को लेकर न कोई चेतावनी है, न कोई अंकुश।

दरअसल, प्रदूषण का गहराता संकट मौसम की मार तो है ही, सरकार की अनदेखी और लापरवाही से समस्या में कई गुना बढ़ोतरी हुई है। इस तरह की दिक्कतों को लेकर चर्चा होती है, लेकिन सरकार की ओर से कोई ठोस कदम नहीं उठाए जाते। हाल में खबर आई कि दिल्ली दुनिया की सर्वाधिक प्रदूषित राजधानी है। एक रिपोर्ट के मुताबिक, देश के सर्वाधिक प्रदूषित 32 शहरों में ग्यारह हरियाणा के पाए गए।

स्पष्ट है कि दिल्ली और आसपास के इलाकों में आसमान में धुएं की परत के आगे बेबसी है। सरकारी स्तर पर कवायद घोषणाओं और आरोप-प्रत्यारोप तक सीमित दिखती है। यही वजह है कि पिछले दिनों सुप्रीम कोर्ट ने केंद्र व राज्य सरकारों को फटकार लगाई कि प्रदूषण रोकने के लिए जमीनी स्तर पर प्रयास न के बराबर हैं।दरअसल, हर साल ठंड शुरू होते ही हवा की दशा-दिशा में बदलाव के साथ ही आसमान में धुएं की परत जमने लगती है। यही वजह है कि पराली संकट व अन्य कारणों से बढ़ते प्रदूषण से चिंतित सुप्रीम कोर्ट को कहना पड़ा कि प्रदूषण मुक्त वातावरण में रहना नागरिकों का मौलिक अधिकार है।

हालत यह है कि बहुत सारे लोगों के सामने सांस से संबंधित परेशानियों सहित कई तरह की मुश्किलें पैदा हो रही हैं, लेकिन अब भी प्रदूषण को कम या दूर करने के लिए कोई ईमानदार इच्छाशक्ति नहीं दिखती। किसानों के मुद्दों को जोर-शोर से उठाकर श्रेय लेने वाले राजनेताओं की जवाबदेही तय होनी चाहिए।

बंपर पैदावार का श्रेय लेने वाले नेता तब कहां चले जाते हैं, जब पराली जलाने का संकट पैदा होता है? यह भी हकीकत है कि प्रदूषण संकट के मूल में सिर्फ पराली समस्या ही नहीं है। हमारी उपभोक्ता संस्कृति, वाहनों का अंबार, सार्वजनिक यातायात सुविधा का पर्याप्त न होना, अनियोजित निर्माण कार्य, जीवाश्म ईंधन का प्रयोग तथा कूड़े का वैज्ञानिक तरीके से निस्तारण न होना भी प्रदूषण संकट के मूल में है।

शासन को भी आग लगने पर कुआं खोदने की मानसिकता से बचना होगा और दूरगामी प्रभावों वाली नीतियां लागू करनी होंगी। जवाबदेही तय होनी चाहिए।

लकड़ी की नाव और मसालों की खुशबू, 5000 साल पुरानी दोस्ती, क्यों कहा जाता है ओमान को गेटवे ऑफ गल्फ

प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी 17 दिसंबर से ही ओमान के दौरे पर हैं। उनके टूर का आज दूसरा दिन है। साल 2020 में अपने चचेरे भाई सुल्तान काबूस बिन सईद के निधन के बाद सत्ता में आए थे। प्रधानमंत्री मोदी सुल्तान हैथम बिन तारिक के निमंत्रण पर ओमान की यात्रा पर पहुंचे। ओमान की यह यात्रा भारत और ओमान के बीच राजनयिक संबंधों की स्थापना की 70वीं वर्षगांठ के अवसर पर हुई। ओमान वो मुस्लिम देश है जो हमेशा से ही यह अभी की बात नहीं है। शुरुआत से ही भारत हितेषी रहा है। भारत का शुभचिंतक रहा है। चाहे हम 1971 में बांग्लादेश के साथ जिस तरीके की स्थिति परिस्थिति बनी थी उस दौरान बात करें तो कई ऐसे देश थे जो भारत के खिलाफ हो गए थे। पाकिस्तान का साथ दे रहे थे अपने फायदे के लिए। लेकिन तब भी ओमान ने भारत का साथ नहीं छोड़ा।

पीएम मोदी की मस्कट यात्रा से भारत ओमान के बीच की मित्रता और द्विपक्षीय संबंधों को मजबूती मिलने की उम्मीद है। ओमान अरब दुनिया का सबसे पुराना स्वतंत्र देश है जिसके सुल्तान तारिक दिसंबर 2023 में भारत के दौरे पर भी आए थे। सुल्तान तारिक अपनी लग्जरी लाइफ स्टाइल अक्सर चर्चा में रहते हैं। ऐसे में आपको बताते हैं कि तारिक कौन है और व कैसी लाइफ स्टाइल जीते हैं। वैसे भारत और ओमान का रिश्ता आज का नहीं है। यह रिश्ता सिंधु घाटी सभ्यता के समय का है। तब ओमान को मगन कहा जाता था। गुजरात के लोथल बंदरगाह से जहाज ओमान जाते

थे। उस समय इंजन वाले जहाज नहीं होते थे। लकड़ी की नावें होती थीं। भारत से मसाले, कपड़ा और अनाज ओमान जाता था. बदले में वहां से खजूर और मोती भारत आते थे।

68 साल के हैथम बिन तारिक अरब देश ओमान के सुल्तान और प्रधानमंत्री हैं हैथम कबूस बिन सैद के चचेरे भाई हैं जो उनसे पहले ओमान के सुल्तान थे साल 2020 में सैद का का निधन हो गया जिसके बाद हैथम ओमान के सुल्तान बने कबूस ने अपनी वसीयत में हैथम को अपना उत्तराधिकारी बताया था जिसके बाद उन्हें ओमान का सुल्तान बनाया गया सुल्तान हैथम बिन तारिक ओमान में छह विशाल महलों के मालिक हैं उनके विशाल महलों में 200 साल पुराना महल अल आलम पैलेस भी शामिल है इसकी खूबसूरती ऐसी है कि टूरिस्ट भी इसके सामने के गेट पर फोटो खिंचवाने पहुंचते हैं।

महल के मैदान में एक पूल स्पा और दीवारों वाले शानदार गार्डन के साथ एक गेस्ट के लिए विला भी है इसे 16वीं शताब्दी में पुर्तगालियों द्वारा बनाया गया था इस महल में इंग्लैंड की रानी किंग चार्ल्स डचेस ऑफ कॉर्नवेल और नीदरलैंड की रानी जैसे राजाओं की मेजबानी की है शाही परिवार के पास इंग्लैंड में लग्जरी पैलेस है स्टेफोर्ड शायर में 14 एकड़ के हैसे लर हाउस पैलेस है डर्बी शायर फ्लैंग स्टोर फ्लोर वाला सात बेडरूम वाला पैलेस भी है ओमान की रॉयल फ्लाइट में शाही इस्तेमाल के लिए सात सरकारी विमान है रॉयल फैमिली के पास तीन बोइंग 747 विमान है जिनकी कीमत 900 करोड़ है यल फैमिली के पास ? 744 करोड़ कीमत के दो एयर बर्स 320` जैसे अत्याधुनिक प्राइवेट जेट भी है। इसके अलावा गल्फ स्ट्रम 550 लॉक हीट मार्टिन म130 सुपर हरकुलिस जहाज और 27 मिलियन डलर कीमत के ए 550 जैसे हेलीकॉप्टर भी हैं जिनकी कीमत करोड़ों में है।

पिछले 281 वर्षों से हैथम का परिवार ओमान की सत्ता संभालता आ रहा है। इसके बावजूद सुल्तान हैथम ने शाही परंपराओं को महज शैली का हिस्सा बनाए रखा है। ओमान में आज भी विशेष अवसरों पर शाही भोजन 48 घंटे तक रेत में दफन होकर पकाया जाता है। 'द मीडियेटर' के नाम से मशहूर हैं हैथम ओमान को अरब जगत का स्विट्जरलैंड कहा जाता है और इसके पीछे है सुल्तान हैथम की तटस्थ कूटनीति। अमेरिका-ईरान, इजराइल हमास, ईरान न्यूक्लियर डील सबमें ओमान के सुल्तान अक्सर पर्दे के पीछे समाधान की राह बनाते रहे हैं। यमन संकट में ओमान एकमात्र खाड़ी देश है जो तटस्थ रहा और 25 हजार से अधिक यमनी शरणार्थियों को शरण दी। सऊदी अरब और हूती विद्रोहियों थी के बीच भी वार्ता 2023 में मस्कट में हुई थी।

ओमान के सुल्तान के पास 600 मिलियन डॉलर यानी करीब 4983 करोड़ की आट है जो दुनिया की सातवी सबसे बड़ी आट है इस यार्ट का नाम है अल सलामा जिसे शांति का जहाज भी कहा जाता है। यार्ट 522 फीट लंबी है यार्ट में 538 वर्ग फीट का अलीशान कमरा है और एक अलग से 431 वर्ग फुट का ड्रेसिंग रूम भी है इसके अंदर स्वीट में एक सैलून और एक हॉट टब के साथ-साथ एक अटैच बाथरूम भी है। सुल्तान तारिक के पास एक दूसरी यार्ट भी है जिसका नाम है अल सैद याड यह 508 फीट लंबी है जिसके छह डॉक में 26 कबन है जिनमें 70 मेहमानों के रोकने की व्यवस्था है। 130 साल विंटेज फरारी के मालिक भी सुल्तान हैथम को विंटेज कारों का भी शौक है। उनके गैरेज में 130 साल पुरानी भाप से चलने वाली दुनिया की सबसे दुर्लभ फरारी और रॉल्स रॉयस भी मौजूद हैं। इसके अलावा मर्सिडीज-मेबैक और बेंटले जैसी दुनिया की सबसे महंगी और चुनिंदा कारें भी शामिल हैं। सीलबंद लिफाफे से हैथम का नाम तय हुआ हैथम बिन तारिक का सत्ता तक पहुंचना भी किसी कहानी से कम नहीं। 2020 में पूर्व सुल्तान काबूस की मृत्यु के बाद एक सीलबंद लाल लिफाफा खोला गया और उसी में उत्तराधिकारी के रूप में हैथम का नाम लिखा था। न कोई संघर्ष, न शोर। बस सत्ता का शांत हस्तांतरण।

ओमान को 'गेटवे ऑफ गल्फ' यानी खाड़ी का दरवाजा कहा जाता है। यह होर्मुज जलडमरूमध्य के पास स्थित है। दुनिया का एक बड़ा हिस्सा तेल व्यापार इसी रास्ते से होता है। ओमान के पास जिसके अच्छे संबंध होंगे, उसका इस रूट पर दबदबा रहेगा। पीएम मोदी इस बात को बखूबी समझते हैं। इसलिए उन्होंने अपनी विदेश नीति में ओमान को टॉप प्रायोरिटी पर रखा है।

ओमान मध्य पूर्व के उन चुनिंदा देशों में से एक है, जिसके भारत के साथ मजबूर रक्षा संबंध हैं। ओमान ने भारत को अपनी नौसैनिक जरूरतों को पूरा करने के लिए एक बंदरगाह भी दिया है। यह पोर्ट रणनीतिक रूप से बहुत अहम है। यह अरब सागर के ठीक मुहाने पर है। यहां से भारत पूरे हिंद महासागर पर नजर रख सकता है। भारतीय नौसेना के जहाज यहां रुक सकते हैं।

जताएं आभार, युवा जीवन की दौड़ में सुकून संतुलन और सफलता का सबसे शांत हथियार

हम जिस दौर में जी रहे हैं, वहां हर कोई तेजी से आगे बढ़ने की दौड़ में लगा है। पढ़ाई, नौकरी, करिअर और रिश्ते - हर जगह प्रतिस्पर्धा इतनी गहन हो गई है कि युवा पीढ़ी को अक्सर तनाव, दबाव और असंतोष का सामना करना पड़ता है। ऐसे समय में आभार व्यक्त करने की आदत एक साधारण-सी लग सकती है, लेकिन इसका असर असाधारण है। आभार जीवन की राह मोड़ सकता है, सोच की दिशा बदल सकता है और व्यक्ति को वह ऊर्जा दे सकता है, जिसकी तलाश वह हर जगह कर रहा होता है।

आभार केवल किसी को धन्यवाद कहने तक सीमित नहीं है, बल्कि यह जीवन जीने का एक नजरिया है। जब हम यह स्वीकार करते हैं कि हमारे जीवन में कितनी चीजें ऐसी हैं, जो हमें खुशी, सहयोग और समर्थन प्रदान करती हैं, तब हमारी दृष्टि समस्याओं से हटकर संभावनाओं पर केंद्रित हो जाती है। यह छोटा-सा बदलाव हमारे व्यक्तित्व में गहरी शांति और आत्मविश्वास जगाता है।

युवा होने के नाते जीवन में अनेक उतार-चढ़ाव आते हैं। असफल परीक्षाएं, बेरोजगारी, टूटते रिश्ते या किसी सपने का पूरा न होना–ये सब परिस्थितियां युवाओं को हताश कर सकती हैं। मगर इन अनुभवों को एक आभारपूर्ण दृष्टिकोण से देखा जाए, तो हर असफलता एक सबक बन सकती है।

आभार का लाभ यह है कि यह मानसिक स्वास्थ्य को सुदृढ़ करता है। जो युवा छोटी-छोटी उपलब्धियों या सहयोग के लिए धन्यवाद प्रकट करते हैं, उनके भीतर आत्मविश्वास और उम्मीद बनी रहती है। वे तनाव से जल्दी उबर जाते हैं और चुनौतियों का सामना दृढ़ता से कर पाते हैं। अनेक मनोवैज्ञानिक शोधों ने यह सिद्ध किया है कि कृतज्ञता का भाव रखने वाले लोग अवसाद से कम ग्रस्त होते हैं और जीवन को अधिक आनंदपूर्वक जीते हैं।

रिश्तों में भी आभार का महत्त्व अत्यधिक है। युवा पीढ़ी के लिए मित्र और परिवार जीवन के हर कदम पर सहारा होते हैं, लेकिन व्यस्तता और तनाव के कारण अक्सर हम इसे भूल जाते हैं। एक साधारण-सा 'धन्यवाद' या स्नेहपूर्ण व्यवहार विश्वास को गहराई देता है। जब हम अपने माता-पिता, दोस्तों या शिक्षकों का आभार मानते हैं, तो उन्हें यह अहसास होता है कि उनकी भूमिका हमारे जीवन में कितनी मूल्यवान है। यह छोटा-सा कदम रिश्तों को और अधिक मजबूत बना देता है।

जीवन के बड़े व्यक्तित्व भी आभार की आदत को सफलता की कुंजी मानते रहे हैं। महात्मा गांधी ने कहा था कि वे अपने विरोधियों के प्रति भी कृतज्ञ रहे, क्योंकि उन्हीं की वजह से उन्हें सत्य और अहिंसा का महत्त्व अधिक गहराई से समझ आया। नेल्सन मंडेला ने जेल की कठिनाइयों को आभार की दृष्टि से देखा और उन्हें ताकत में बदल दिया। ये उदाहरण दर्शाते हैं कि आभार केवल आसान परिस्थितियों में ही नहीं, बल्कि विपरीत हालात में भी सहारा देता है।

युवा पीढ़ी के लिए यह समझना भी आवश्यक है कि आभार केवल दूसरों के लिए नहीं, बल्कि स्वयं के लिए भी जरूरी है। जब कोई युवा अपनी मेहनत, अपनी कोशिशों

और अपने साहस का सम्मान करना सीखता है, तो वह आत्मविश्वास से भर उठता है। स्वयं से आभार व्यक्त करना आत्म-विकास की दिशा में उठाया गया सबसे महत्त्वपूर्ण कदम है। आज की तेज रफ्तार दुनिया में अक्सर युवा अपनी छोटी-छोटी उपलब्धियों को नजरअंदाज कर देते हैं। वे केवल बड़े लक्ष्यों पर ध्यान केंद्रित करते हैं और निराश हो जाते हैं, जब वे जल्द ही पूरे नहीं होते। ऐसे में आभार का अभ्यास यह सिखाता है कि हर छोटी सफलता, हर सहयोग और हर अवसर की महत्ता समझी जाए। यही दृष्टिकोण युवाओं को धैर्यवान और संतुलित बनाता है।

एक और बड़ा पहलू यह है कि आभार समाज में सकारात्मकता का वातावरण बनाता है। जब युवा सहयोग के लिए धन्यवाद देते हैं या किसी अच्छे कार्य की सराहना करते हैं, तो वे दूसरों को भी प्रेरित करते हैं। इस प्रकार एक छोटी-सी भावना समाज में विश्वास, सद्भाव और सहअस्तित्व को बढ़ावा देती है।

अगर हम थोड़ा समय आभार प्रकट करने में दें, तो जीवन अद्भुत रूप से बदल सकता है। यह आदत डायरी लिखने, प्रार्थना करने या सिर्फ उन पलों को याद करने से शुरू हो सकती है, जिनके लिए हम आभारी हैं। धीरे-धीरे यह हमारी सोच और व्यवहार का हिस्सा बन जाती है। भीतर की शांति, रिश्तों में गरमाहट और भविष्य के लिए उत्साह जगाती है।

आभार व्यक्त करना जीवन की कठिनाइयों को मिटा नहीं देता, लेकिन यह उनकी कठोरता को कम कर देता है। यह हमें यह देखने की क्षमता देता है कि हर परिस्थिति में कुछ न कुछ अच्छा छिपा हुआ है। इसलिए युवा पीढ़ी के लिए सबसे बड़ी सीख यही है कि आभार केवल एक औपचारिकता नहीं, बल्कि एक जीवन-दर्शन है। यही दृष्टिकोण उन्हें आगे की कठिन राहों में आत्मविश्वास देगा और उनकी जिंदगी की दिशा सही दिशा में मोड़ देगा।

आर्थिक विकास की चमक के पीछे छिपी सच्चाई, बढ़ती असमानता और महिला भागीदारी की चुनौती

देश की आर्थिक प्रगति ने समाज के कई समुदायों और वर्गों की भी उपेक्षा की है। दरअसल, विकास के क्रम में कतिपय वर्गों के हितों को साधने का प्रयास किया गया। इससे आर्थिक विकास के समक्ष लैंगिक असमानता, जीवन स्तर और जीवन गुणवत्ता में असमानता, निर्धनता, जलवायु परिवर्तन तथा ग्रामीण एवं शहरी क्षेत्रों में असमानता जैसी गंभीर चुनौतियां पैदा हो गई हैं।

हाल में जारी वैश्विक असमानता रपट-2026 के अनुसार देश की कुल संपत्ति का 40 फीसद हिस्सा सिर्फ एक फीसद लोगों के हाथों में है, जबकि 65 फीसद संपत्ति दस फीसद लोगों के पास है। देश में आय के स्तर पर भी स्थिति चिंताजनक है। कुल राष्ट्रीय आय की 58 फीसद हिस्सेदारी दस फीसद लोगों के पास है, जबकि पचास फीसद की हिस्सेदारी में 15 फीसद लोगों की भागीदारी है।

भारत में आय, संपत्ति और लैंगिक समानता में काफी अंतर देखने को मिलता है। महिला श्रम भागीदारी में भी निराशाजनक तस्वीर है। वहीं आज पूरी दुनिया में आर्थिक, लैंगिक और श्रम क्षेत्र में स्त्री-पुरुष विभेद बढ़ रहे हैं। भारत वैश्विक स्तर पर सबसे तेजी से बढ़ती अर्थव्यवस्थाओं में से एक है, मगर जब बात लैंगिक समानता, श्रम क्षेत्र में महिलाओं की भागीदारी और निर्धनता की आती है, तो मालूम होता है कि भारत वैश्विक मानकों पर बहुत पीछे है।

देश में लैंगिक असमानता दुनिया के अन्य देशों की अपेक्षा कहीं ज्यादा है। विश्व आर्थिक मंच की ओर से जारी 'ग्लोबल जेंडर गैप रपट-2025' में भारत 148 देशों में से 131वें स्थान पर है। देश में राजनीतिक असमानता भी दिखाई देती है। वर्ष 2024 के चुनाव के बाद लोकसभा में महिलाओं का प्रतिनिधित्व 13.6 फीसद है, वहीं स्थानीय सरकार में भागीदारी 44.4 फीसद है।

दुनिया भर में लड़कियां और महिलाएं आर्थिक असमानता की शिकार हो रही हैं। इस मसले पर अनेक रपटों में चिंता व्यक्त की गई है। भारत में अन्य देशों की अपेक्षा पुरुषों की तुलना में महिलाओं को वेतन वाले काम कम मिलते हैं। देश के 119 अरबपतियों की सूची में मात्र नौ महिलाएं शामिल हैं।

यदि विकास से जुड़े कार्यों की तुलना की जाए, तो महिलाएं 72 फीसद ही इसे हासिल कर पा रही हैं। महिलाएं पुरुषों की अपेक्षा 28 फीसद कम उपलब्धियां हासिल कर रही हैं। आज दुनिया भर में 15 फीसद ऐसी महिलाएं हैं जो काम करने के योग्य हैं, लेकिन उनके पास काम के अवसर उपलब्ध नहीं हैं। यदि पुरुषों की बात करें, तो यह आंकड़ा दस फीसद है।

भारत में शिक्षा के क्षेत्र में महिलाओं की बात करें, तो वर्ष 2022 में 24.9 फीसद ने ही माध्यमिक और उच्चतर शिक्षा हासिल की है, जबकि पुरुषों की यह संख्या 38.6 फीसद दर्ज की गई है। भारत में विज्ञान, गणित और इंजीनियरिंग विषय में लगभग 43 फीसद महिलाएं स्नातक की उपाधि प्राप्त कर रही हैं। यह आंकड़ा पुरुषों की अपेक्षा महिलाओं की ज्यादा है।

मगर दुनिया भर में शीर्ष प्रशासनिक सेवाओं में महिलाओं की भागीदारी अब भी बहुत कम है। भारत में महिलाओं की स्थिति बहुत स्पष्ट नहीं है। इसी तरह वर्ष 2012 से 2022 के बीच लगभग 44 फीसद युवा लड़कियां शिक्षा और रोजगार से वंचित रह गई थीं। कोई ऐसा क्षेत्र नहीं है, जहां महिलाओं की भागीदारी पुरुषों की अपेक्षा ज्यादा हो।

निजी और सार्वजनिक उपक्रमों में महिलाएं बराबरी के लिए संघर्ष कर रही हैं। भारत में कृषि एक ऐसा क्षेत्र है जहां रोजगार की अपार संभावनाएं हैं, लेकिन इस क्षेत्र में भी महिलाएं बहुत पीछे हैं।

संयुक्त राष्ट्र भी मानता है कि अभी भी पूरी दुनिया में महिलाओं के लिए संसाधन और तकनीकी पहुंच पुरुषों की अपेक्षा सीमित है। आज पूरे विश्व में 62 फीसद पुरुष इंटरनेट का उपयोग करते हैं, वहीं 57 फीसद महिलाएं इंटरनेट का इस्तेमाल करती हैं। डिजिटल तकनीक की सुलभता के मामलों में पुरुषों की अपेक्षा महिलाएं अब भी पीछे हैं। कई ऐसे कार्य हैं जहां महिलाओं की मेहनत का मोल नहीं है। ऑक्सफैम की रपट के अनुसार पूरी दुनिया में घरेलू कार्यों में लगी महिलाएं एक वर्ष में करीब दस हजार अरब डॉलर के बराबर काम करती हैं, जिसका उन्हें वेतन नहीं मिलता है। यदि इन महिलाओं के कार्यों की आर्थिक गणना की जाए, तो वैश्विक सकल घरेलू उत्पाद करीब चार फीसद के बराबर होगा। कृषि कार्यों में जिस काम के लिए पुरुषों को अगर एक रुपया मिलता है, उसी काम को करने के लिए महिलाओं को 82 पैसे मिलते हैं। पुरुषों की अपेक्षा महिलाओं की मजदूरी में लगभग 15 फीसद का अंतर है। अगर श्रम बल आय की बात की जाए, तो यहां भी महिलाओं की भागीदारी महज 18 फीसद है, जबकि पुरुषों का कुल श्रम बल आय 82 फीसद है। भारत में कुल व्यवसाय का लगभग 14 फीसद हिस्सा महिलाओं द्वारा संचालित होता है। वहीं केवल 17 फीसद महिलाओं को नियमित वेतन वाली नौकरी प्राप्त है।

इक्यावन फीसद महिलाओं का कार्य अवैतनिक है। पनचानबे फीसद महिलाओं का कार्य अनौपचारिक और असंगठित है। श्रम बल में महिलाओं की भागीदारी बढ़ने से आर्थिक विकास की उन्नति होती है, गरीबी और भुखमरी घटती है। संयुक्त राष्ट्र खाद्य एवं कृषि संगठन के अनुसार, भारत में महिलाओं की आर्थिक विकास में भागीदारी बढ़ने से लगभग 4.5 करोड़ लोगों की भूख की समस्या से निजात मिलेगी। विश्व में लगभग दो सौ चालीस करोड़ महिलाएं आर्थिक, सामाजिक और अवसर में पुरुषों के बराबर अधिकार से वंचित हैं।

इस असमानता की खाई को कम करने में करीब 50 वर्ष या इससे अधिक वर्ष लग सकते हैं। आर्थिक विकास में महिलाओं की भागीदारी बढ़ाने से वैश्विक अर्थव्यवस्था को 81.6 लाख करोड़ रुपए का लाभ होगा।

भारत में आर्थिक विकास में महिलाओं की भागीदारी सुनिश्चित होने से काफी लाभ होगा। 'मेकिंस्से ग्लोबल इंस्टीट्यूट' के अध्ययन के अनुसार, भारत में महिलाओं की आर्थिक भागीदारी से वर्ष 2025 तक सकल घरेलू उत्पाद 2.9 ट्रिलियन डॉलर की वृद्धि होने की संभावना जताई गई है।

फिर भी भारत जैसे लोकतांत्रिक देश में बढ़ती असमानता संविधान द्वारा प्रदत्त अधिकारों का उल्लंघन है। लोकतंत्र का मूल आधार सभी नागरिकों की समान भागीदारी सुनिश्चित करना है, ऐसे में बढ़ती असमानता लोकतंत्र के लिए भी एक बड़ी चुनौती है।

आर्थिक विकास में समान भागीदारी से नवप्रवर्तन, प्रतिष्ठा में बढ़ोतरी और अलग-अलग आर्थिक क्षेत्रों के सूचकांकों में बेहतरी आएगी। आर्थिक विकास में समान भागीदारी बढ़ाने के लिए प्रत्येक व्यक्ति को उसकी क्षमता और योग्यता के अनुसार कौशल विकसित करना होगा और ज्ञान आधारित विकास पर जोर देना होगा, क्योंकि अब अर्थव्यवस्था तकनीक और डिजिटल की ओर बढ़ रही है।

देश में समान भागीदारी से न सिर्फ आर्थिक उन्नति बल्कि सकल घरेलू उत्पाद को वैश्विक स्तर पर मजबूती मिलेगी। लोगों के जीवन स्तर में सुधार आएगा। निर्धनता घटेगी और खुशहाली बढ़ेगी। समावेशी समाज का निर्माण होगा। किसी भी राष्ट्र की प्रगति समान भागीदारी के बिना संभव नहीं है।

मुक्त विश्वविद्यालय में आर एस एस के विचार एवं व्यवहार पर राष्ट्रीय कार्यशाला आज

प्रयागराज। उत्तर प्रदेश राजर्षि टंडन मुक्त विश्वविद्यालय, प्रयागराज के समाज विज्ञान विद्याशाखा के तत्वावधान में शुक्रवार 19 दिसंबर 2025 को पूर्वाह्न 11:00 बजे सरस्वती परिसर स्थित अटल प्रेक्षागृह में राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ : विचार एवं व्यवहार विषय पर एक राष्ट्रीय कार्यशाला का आयोजन सुनिश्चित हुआ है।

आयोजन सचिव प्रोफेसर आनन्दानन्द त्रिपाठी ने बताया कि उक्त कार्यशाला में मुख्य वक्ता के रूप में अखिल भारतीय क्षेत्र प्रचारक प्रमुख स्वांत रंजन, क्षेत्रीय धर्म जागरण प्रमुख, पूर्वी उत्तर प्रदेश अभय एवं राष्ट्रधर्म के निदेशक मनोज कांत होंगे। कार्यशाला की अध्यक्षता विश्वविद्यालय के कुलपति प्रोफेसर सत्यकाम करेंगे। कार्यक्रम की सफलता के लिए विश्वविद्यालय स्तर पर समन्वयक प्रोफेसर सत्यपाल तिवारी, संयोजक प्रोफेसर संतोषा कुमार, आयोजन सचिव प्रोफेसर आनन्दानन्द त्रिपाठी एवं सह-आयोजन सचिव डॉ. त्रिविक्रम तिवारी की समिति गठित की गयी है। कार्यशाला के अंतर्गत विशिष्ट वक्ताओं द्वारा राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ के विचार एवं व्यवहार के संदर्भ में जानकारी प्रदान की जाएगी।

उल्लेखनीय है कि इसी विषय पर उत्तर प्रदेश राजर्षि टंडन मुक्त विश्वविद्यालय आगामी जनवरी 2026 सत्र से एक पाठ्यक्रम भी प्रारम्भ करने वाला है। जिसकी घोषणा कुलपति प्रोफेसर सत्यकाम ने इसी वर्ष गांधी जयंती के अवसर पर की है। उक्त कार्यशाला में इस पाठ्यक्रम के लेखन से संबंधित शिक्षकों के साथ-साथ विश्वविद्यालय एवं देश के अन्य शिक्षण संस्थानों के शिक्षक, शिक्षार्थी एवं अन्य गणमान्य अतिथि प्रतिभाग करेंगे।

8033 केंद्रों पर होगी यूपी बोर्ड परीक्षा जनपदीय समितियों ने बढ़ाए 585 केंद्र

सबसे ज्यादा निजी स्कूलों को बनाया गया परीक्षा केंद्र यूपी बोर्ड के सचिव भगवती सिंह ने जारी किया सूची

प्रयागराज। उप्र माध्यमिक शिक्षा परिषद प्रयागराज (यूपी बोर्ड) की हाईस्कूल एवं इंटरमीडिएट परीक्षा 2026 के लिए 8033 केंद्र बनाए गए हैं। बोर्ड की ओर से आनलाइन प्रस्तावित केंद्रों पर आई आपत्तियों के निस्तारण के बाद जनपदीय समितियों ने इस बार 585 परीक्षा केंद्र बढ़ा दिए हैं।

जनपदीय केंद्र निर्धारण समितियों ने आफलाइन माध्यम से सबसे ज्यादा निजी स्कूलों के केंद्र बढ़ाए हैं। यूपी बोर्ड सचिव भगवती सिंह ने 30 नवंबर को जारी आनलाइन सूची में 7448 केंद्र बनाए थे, जिनमें 910 राजकीय, 3484 सहायता प्राप्त और 3054 वित्तविहीन माध्यमिक विद्यालय शामिल थे।

यूपी बोर्ड की ओर से जारी आनलाइन केंद्रों पर छात्र, छात्राओं, प्रधानाचार्यों, अभिभावकों और प्रबंधकों से आपत्तियां मांगी गई थी। प्रदेश भर में आठ हजार से अधिक आपत्तियां मिली। जिलाधिकारी की अध्यक्षता में गठित जिला स्तरीय समिति को आपत्तियों को निस्तारित कर केंद्र

बनाने की जिम्मेदारी सौंपी गई थी। आपत्ति निस्तारण के बाद जनपदीय समितियों ने केंद्रों की संख्या बढ़ाकर 8033 कर दी है। इसमें 596 राजकीय इण्टर कालेज, 3453 सहायता प्राप्त (एडेड कालेज) और 3984 वित्तविहीन विद्यालय शामिल हैं। इस तरह सबसे अधिक कटौती राजकीय विद्यालयों के केंद्रों में की गई है।

यूपी बोर्ड ने 910 राजकीय विद्यालयों को केंद्र बनाया था, जबकि जनपदीय समितियों ने इसमें से 314 विद्यालयों को हटा दिया है। 31 एडेड विद्यालयों के केंद्र भी कम किए गए हैं। यूपी बोर्ड के सचिव भगवती सिंह की ओर से बुधवार देर रात परीक्षा केन्द्र आनलाइन माध्यम से प्रस्तावित परीक्षा केंद्रों (विद्यालय छात्र आवंटन सहित) की सूची जनपदीय केंद्र निर्धारण समिति के अनुमोदन के बाद वेबसाइट upmsp.edu.in पर अपलोड कर दी गई है। उन्होंने बताया कि विद्यालय छात्र आवंटन सहित केंद्रों की सूची के संबंध में यदि कोई आपत्ति या शिकायत हो तो छात्र, अविभावक, प्रधानाचार्य या प्रबंधक साक्ष्यों के साथ संबंधित विद्यालय की आईडी से अपना आनलाइन प्रत्यावेदन पोर्टल upmsp.edu.in पर 22 दिसंबर तक भेज सकते हैं। इन प्रत्यावेदनों के निस्तारण के बाद परीक्षा केंद्रों की अंतिम सूची 30 दिसंबर तक अपलोड की जाएगी।

काकोरी ट्रेन एक्सन के बलिदानियों को दी गई श्रद्धांजलि

प्रयागराज। अमर क्रांतिकारी श्रद्धांजलि ग्रुप प्रयागराज के द्वारा मुंशी राम प्रसाद की बगिया मुट्ठीगंज में काकोरी ट्रेन एक्शन के बलिदानियों को उनके बलिदान के पूर्व संध्या पर याद करते हुए श्रद्धांजलि दी। श्रद्धांजलि देते हुए ग्रुप के संरक्षक कुमार नारायण एवं अध्यक्ष राजेश केसरवानी ने कहा कि स्वाधीन भारत के निर्माण में महान क्रांतिकारी पंडित राम प्रसाद बिस्मिल जी के नेतृत्व में क्रांतिकारियों के द्वारा 5 अगस्त 1925 को किया गया काकोरी ट्रेन एक्शन का संघर्ष भारत कभी भूल नहीं सकता और कहा कि काकोरी ट्रेन एक्शन का संघर्ष अंग्रेजों की नींद हराम कर दी थी जिसके कारण अंग्रेजी सरकार ने भयभीत होकर काकोरी ट्रेन एक्शन के संघर्ष करने वाले सभी क्रांतिकारियों को 19 दिसंबर 2027 को अलग-अलग जिलों के जेलों में फांसी दी थी, जिसे हर हिंदुस्तानी कभी भूल नहीं सकता। संचालन शत्रुघ्न जायसवाल ने किया और संयोजक अभिलाष केसरवानी रहे। श्रद्धांजलि अर्पित करने वालों में कुमार नारायण राजेश केसरवानी दिनेश कुमार, धर्मनारायण, सरदार पतिविंदर सिंह, शत्रुघ्न जायसवाल अभिलाष केसरवानी, मुकेश जायसवाल, हर्ष केसरवानी, सौरभ नीरज केसरवानी आदि ने श्रद्धांजलि दी।

डीएलएड : अभ्यर्थियों का झुकाव नहीं, आधी सीटों के लिए आवेदन

शीघ्र जारी होगी मेरिट, अभ्यर्थी भरेगे विकल्प : सचिव अनिल भूषण

2.39 लाख सीटों के सापेक्ष 138857 पंजीकरण, 125333 आवेदन

प्रयागराज। डीएलएड प्रशिक्षण- 2025 में प्रशिक्षण को लेकर अभ्यर्थियों का झुकाव दिनों दिन कम होता जा रहा है। इस बार आधी सीटों के लिए आवेदन हुआ है। कुल 2.39 लाख सीटों के सापेक्ष 138857 अभ्यर्थियों ने आनलाइन पंजीकरण किया है जबकि 125333 अभ्यर्थियों ने आनलाइन शुल्क जमा कर दिया है। अभ्यर्थी आवेदन का आनलाइन प्रिण्ट प्राप्त कर सकते है।

सचिव परीक्षा नियामक प्राधिकारी उप्र प्रयागराज अनिल भूषण चतुर्वेदी ने आज बताया कि डीएलएड की मेरिट तैयार हो रही है जो शीघ्र जारी होगी और उसके बाद अभ्यर्थी आनलाइन विकल्प भरेगे और काउंसलिंग के बाद डायट सहित अन्य शिक्षण संस्थाओं में प्रवेश प्रक्रिया शुरू होगी।

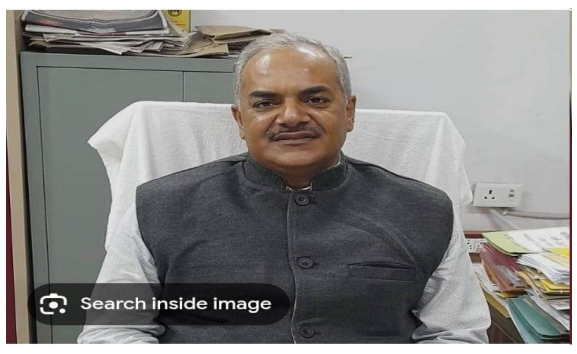

उन्होंने बताया कि डीएलएड में यूपी के अभ्यर्थियों के अतिरिक्त सभी अभ्यर्थी अनारक्षित श्रेणी में माने जाएंगे। ऐसे व्यक्तियों को किसी भी तरह का आरक्षण डीएलएड में प्रवेश के दौरान नही दिया जाएगा। सचिव ने बताया कि डीएलएड प्रवेश से संबंधित सभी दिशा निर्देश वेबसाइट- https://updeled.gov.in पर दिए गए हैं। उल्लेखनीय है कि डीएलएड की कुल 2.39 लाख सीट है जिसमे 10600 सीट डायट में और शेष निजी क्षेत्र के कालेजों में सीटें है।

प्रशिक्षण शिविर में पुलिस कर्मियों को माघ मेले की महत्वपूर्ण जानकारी से किया जा रहा ब्रीफ

प्रयागराज। रिजर्व पुलिस लाइन्स माघ मेला के त्रिवेणी सभागार में आयोजित प्रशिक्षण शिविर के प्रथम कालांश में उपस्थित अधिकारियों/कर्मचारियों को यातायात उपनिरीक्षक अवधेश कुमार सिंह के द्वारा माघ मेला क्षेत्र में पाण्टून पुलों/मुख्य चौराहे/तिराहे पर आवागमन एवं पार्किंग स्थलो के संबंध में सभी को अवगत कराया गया एवं द्वितीय कालांश में प्रभारी निरीक्षक परेड अतुल कुमार सिंह के द्वारा बताया गया कि साइबर फ्राड ऑनलाइन बैंकिंग, सोशल मीडिया, मोबाइल ऐप के जरिये कैसे होता है एवं साइबर फ्रॉड से बचने के लिए हर प्रकार से सतर्क कैसे रहें, किसी सूचना पर बिना सलाह के आगे कदम न बढ़ाये जैसी अनेक जानकारियां के संबंध मे विस्तृत जानकारी दी गई एवं प्रशिक्षण के अंतिम कालांश मे फायरमैन आरक्षी पिरत पाल सिंह के द्वारा आपदा प्रबंधन जैसे मेला क्षेत्र में आग लगने कि स्थिति पर आपातकालीन योजना को कैसे लागू किया जाये महत्वपूर्ण जानकारी से सभी को अवगत कराया गया। प्रशिक्षण के दौरान उपस्थित सभी थाना प्रभारी/शाखा प्रभारी व अन्य कर्मचारीगणो का अपर पुलिस अधीक्षक/नोडल पुलिस अधिकारी माघ मेला विजय आनन्द ने आभार व्यक्त किया ।

भीषण ठंड, कोहरे से आज से इण्टर तक के स्कूलों का समय बदला

यूपी बोर्ड, सीबीएसई, आईसीएसई के विधालयों को निर्देश जारी

प्रयागराज। ठंड और कोहरे को देखते हुए जिले के परिषदीय और इण्टर कालेजों के समय में आज बदलाव किया गया है। प्रयागराज जिले में सभी बोर्डों के बेसिक स्कूलों से लेकर इण्टरमीडिएट कालेजों को सुबह 10:00 बजे से अपराह्न 3:00 बजे तक संचालित होंगे। डीएम मनीष कुमार वर्मा के निर्देश पर बीएसए अनिल कुमार और जिला विधालय निरीक्षक पीएन सिंह ने आज आदेश जारी किया है। बीएसए अनिल कुमार और जिला विधालय निरीक्षक पीएन सिंह ने परिषदीय प्राथमिक, उच्च प्राथमिक, कंपोजिट, राजकीय, अशासकीय सहायता प्राप्त, मान्यता प्राप्त विद्यालय, सीबीएसई, आईसीएसई व सभी बोर्डों के इण्टरमीडिएट तक के स्कूलों पर यह आदेश लागू होगा।

बीएसए ने सभी विद्यालयों के प्रबंधकों और प्रधानाचार्यों को निर्देश दिया है कि इस आदेश का सख्ती से अनुपालन सुनिश्चित करें। यह आदेश अग्रिम निर्देशों तक के लिए प्रभावी रहेगा।

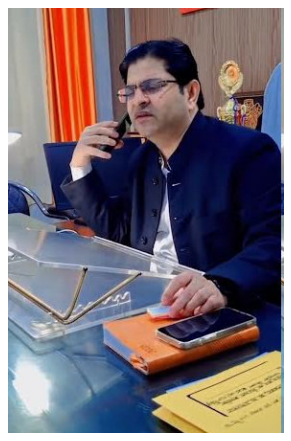

डीआईओएस ने सभी स्कूलों को इस आदेश का सख्ती से अनुपालन का निर्देश दिया है। उन्होंने अग्रिम आदेशों तक इसी समय पर स्कूल संचालित होंगे। महर्षि पतंजलि विधालय (एमपीवीएम) की प्रधानाचार्या श्रीमती अल्पना डे ने डीएम, डीआईओएस और बीएसए के आदेश का स्वागत किया है। उन्होंने कहा कि आदेश का पालन किया जा रहा है। सभी बच्चों और अभिभावकों को ठंड को देखते हुए विधालय के बदले समय की जानकारी दें दी गयी है। उप्र माध्यमिक शिक्षक संघ (एकजुट) के प्रदेश संरक्षक डा हरिप्रकाश यादव ने भीषण ठंड और कोहरे में विधालयों के समय में किए गये परिवर्तन का स्वागत किया है। उन्होंने कहा कि इससे बच्चों, अभिभावक और शिक्षकों को राहत मिलेगी और शिक्षण बेहतर होगा।

नायब तहसीलदार ने बीएलओ कार्यों का किया औचक निरीक्षण

थरवई (प्रयागराज)। विकासखंड सोराम क्षेत्र के प्राथमिक विद्यालय जगदीशपुर पूरे चंदा में गुरुवार को धीरज कुमार पटेल नायब तहसीलदार नवाबगंज सोराम ने बीएलओ द्वारा किए जा रहे मतदाता पुनरीक्षण कार्यों का औचक निरीक्षण किया। निरीक्षण के दौरान उन्होंने क्षेत्र के बीएलओ के कार्यों का गहन सत्यापन किया और अभिलेखों की जांच की।नायब तहसीलदार ने मतदाता सूची पुनरीक्षण कार्य को समयबद्ध एवं पारदर्शी ढंग से पूर्ण करने के निर्देश दिए। उन्होंने कहा कि किसी भी पात्र मतदाता का नाम छूटने न पाए तथा अपात्र नामों को नियमानुसार हटाया जाए। निरीक्षण के दौरान बीएलओ से प्रगति रिपोर्ट भी ली गई।इस अवसर पर गांव के तमाम लोग मौजूद रहे और मतदाता सूची से संबंधित अपनी समस्याएं अधिकारियों के समक्ष रखीं, जिनके शीघ्र निस्तारण का आश्वासन दिया गया।

जीजीआईसी की छात्राओं ने किया मुक्त विश्वविद्यालय का शैक्षिक भमण

प्रयागराज। उत्तर प्रदेश सरकार के अत्यंत महत्वपूर्ण मिशन समग्र शिक्षा अभियान के अंतर्गत राजकीय माध्यमिक विद्यालयों की छात्राओं को उच्च शैक्षिक, तकनीकी, प्रबंधन संस्थानों एवं विश्वविद्यालय में भ्रमण की योजना के क्रम में बृहस्पतिवार को राजकीय बालिका इंटर कॉलेज, बिहार, प्रतापगढ़ की 100 छात्राओं ने प्रधानाचार्य श्रीमती मनीषा रावत के नेतृत्व में उत्तर प्रदेश राजर्षि टंडन मुक्त विश्वविद्यालय का शैक्षिक भ्रमण किया। जिसमें उन्होंने मुक्त विश्वविद्यालय की शैक्षिक कार्य प्रणाली को विस्तार से समझा। इस शैक्षिक भ्रमण का संयोजन प्रोफेसर देवेश रंजन त्रिपाठी द्वारा किया गया। सर्वप्रथम समस्त छात्राओं को पांच समूह में वर्गीकृत किया गया। विश्वविद्यालय की ओर से प्रत्येक समूह का नेतृत्व मार्गदर्शन क्रमशः सहायक आचार्य डॉ0 नीता मिश्रा, डॉ0 सफीना समावी, डॉ0 दीपशिखा श्रीवास्तव, डॉ0 कामना यादव, डॉ सुमन सिंह, डॉ सुषमा सिंह तथा सुसौम्या तिवारी द्वारा किया गया। राजकीय विद्यालय की ओर से प्रत्येक समूह के साथ उनकी शिक्षक श्रीमती अपर्णा त्रिपाठी, श्रीमती निशा पांडेय, श्रीमती अवंतिका, सुरेनू सिंह ने अपना सह नेतृत्व प्रदान किया।

विश्वविद्यालय आगमन पर समूह का स्वागत प्रो0 देवेश ने किया तथा भ्रमण संबंधी आवश्यक दिशा निर्देश सभी को प्रदान किया। कुलसचिव कर्नल विनय कुमार ने विश्वविद्यालय की गतिविधियों से छात्राओं को अवगत कराया। शैक्षिक भ्रमण के दौरान सभी ने विश्वविद्यालयके गंगा परिसर स्थित मीडिया सेल, प्रवेश अनुभाग, स्वअध्ययन सामग्री प्रकोष्ठ, परीक्षा विभाग आदि के संबंध में समझा।भ्रमण के द्वितीय चरण में समूह सरस्वती परिसर स्थित

विशेष सूचनाएँ प्राप्त की। इस परिसर में उन्होंने कुलपति कार्यालय, कुलसचिव कार्यालय, वित्त अधिकारी कार्यालय तथा परीक्षा नियंत्रक कार्यालय की विभिन्न गतिविधियों को विद्याशाखाओं में गये, जहाँ संबंधित निदेशकों तथा अध्यापकों ने विभिन्न कार्यक्रमों और कोर्सो के संबंध में विस्तार से सूचनाएं उपलब्ध कराई। निदेशक आंतरिक गुणवत्ता सुनिश्चियन प्रकोष्ठ प्रोफेसर आशुतोष गुप्ता ने भ्रमण दल के बीच शिक्षकों को मुक्त शिक्षा संचालन के विभिन्न गुणात्मक पहलुओं की जानकारी देते हुए उन्हें भी अपने कैरियर अभिवर्धन में मुक्त विश्वविद्यालय से जुड़ने का संबल प्रदान किया। भ्रमण के तीसरे चरण में छात्राओं और अध्यापकों ने विश्वविद्यालय के पुस्तकालय का अवलोकन कर विभिन्न पुस्तकों के संबंध में अपनी जिज्ञासाओं को शांत किया तथा भविष्य में वह भी इस पुस्तकालय का उपयोग करने की इच्छा व्यक्त की। अंत में भ्रमण दल सरस्वती परिसर स्थित अटल सभागार में इकट्ठा हुए, जहां प्रवेश प्रभारी प्रोफेसर जेपी यादव ने विश्वविद्यालय की सरलतम प्रवेश प्रणाली से सभी को अवगत कराया। तत्पश्चात परीक्षा नियंत्रक प्रोफेसर गिरीश कुमार द्विवेदी ने विश्वविद्यालय की लचीली एवं गुणवत्ता परक परीक्षा प्रणाली को समूह के साथ साझा किया। अंतिम पड़ाव में छात्राओं और शिक्षकों ने अपनी जिज्ञासाओं को प्रस्तुत किया, जिसका समाधान प्रोफेसर देवेश रंजन त्रिपाठी द्वारा करते हुए सभी को विश्वविद्यालय आने पर धन्यवाद दिया एवं कुलपति के प्रति आभार प्रकट करते हुए शैक्षिक भ्रमण को समाप्त किया।

इफको के प्रबंध निदेशक के. जे. पटेल का इफको फूलपुर आगमन

प्रयागराज। इफको फूलपुर इकाई में आज इफको के नव नियुक्त प्रबंध निदेशक के. जे. पटेल का आगमन हुआ। प्रबंध निदेशक का कार्यभार ग्रहण करने के पश्चात पटेल ने अपने प्रथम संयंत्र भ्रमण हेतु इफको फूलपुर इकाई का चयन किया, जो समस्त इफको फूलपुर परिवार के लिए अत्यंत हर्ष और गौरव का विषय है।

इफको फूलपुर इकाई को प्रबंध निदेशक की प्रथम यात्रा के लिए चुना जाना, यहाँ के कर्मचारियों, अधिकारियों एवं प्रबंधन के प्रति उनके विश्वास और इकाई के महत्व को दर्शाता है। इस अवसर पर संपूर्ण इफको फूलपुर परिवार में विशेष उत्साह एवं गर्व का वातावरण देखने को मिला। प्रबंध निदेशक के इस दो दिवसीय दौरे से इकाई के कर्मचारियों में नई ऊर्जा एवं प्रेरणा का संचार हुआ है तथा भविष्य में और बेहतर प्रदर्शन हेतु सभी उत्साहपूर्वक संकल्पित हैं। इस दो दिवसीय दौरे पर प्रबंध निदेशक के.जे.पटेल इफको फूलपुर संयंत्र का तकनीकी निरीक्षण करेंगे तथा इफको परिवार के सभी सदस्यों से मिलेंगे।

प्रबंध निदेशक के. जे. पटेल का इफको फूलपुर आगमन पर महाप्रबंधक (इकाई प्रमुख) पी.के. सिंह, महाप्रबंधक क्रमशः संजय भंडारी, डॉ अनीता मिश्र, पी.के.पटेल, रत्नेश कुमार, संयुक्त महाप्रबंधक क्रमशः अरूण कुमार, एस.के. सिंह, ए.के.गुप्ता, पी.के. वर्मा, अरवेन्द्र कुमार, डॉ सत्य प्रकाश, आर.पी.यादव, पी.के.त्रिपाठी, संदीप गोयल, विभागाध्यक्ष मानव संसाधन शम्भू शेखर, इफको ऑफिसर्स एसोसिएशन के अध्यक्ष अनुराग तिवारी व महामंत्री स्वयम् प्रकाश, इफको इम्पलाइज संघ के अध्यक्ष पंकज पाण्डेय व महामंत्री विजय कुमार यादव, एवं इफको के वरिष्ठ अधिकारियों द्वारा आत्मीय एवं गर्मजोशी से स्वागत किया गया।

नौकरशाहों के लिए 'माननीय' शब्द का इस्तेमाल उचित नहीं : इलाहाबाद हाई कोर्ट

प्रयागराज। इलाहाबाद हाई कोर्ट ने नौकरशाहों और राज्य सरकार के अधिकारियों के लिए 'माननीय' शब्द के प्रयोग पर कड़ा सवाल उठाया है। कोर्ट ने उत्तर प्रदेश राजस्व विभाग के प्रधान सचिव से इस संबंध में व्यक्तिगत हलफनामा दाखिल करने का निर्देश देते हुए पूछा है कि किस कानून या प्रोटोकॉल के तहत अधिकारियों के नाम या पदनाम के साथ 'माननीय' शब्द जोड़ा जा रहा है।

यह आदेश न्यायमूर्ति अजय भनोट और न्यायमूर्ति गरिमा प्रसाद की खंडपीठ ने योगेश शर्मा की याचिका पर सुनवाई करते हुए दिया। कोर्ट ने विशेष रूप से यह प्रश्न उठाया कि 'अतिरिक्त आयुक्त, अपील' को 'माननीय अतिरिक्त आयुक्त, अपील' क्यों कहा जा रहा है।

कोर्ट ने टिप्पणी की कि यह प्रवृत्ति संवैधानिक पदाधिकारियों और न्यायालयों के दर्जे को कम करने का एक सूक्ष्म लेकिन निश्चित तरीका है। हाल के दिनों में राज्य के विभिन्न विभागों में यह चलन बढ़ा है कि सबसे निचले से लेकर उच्चतम स्तर तक के अधिकारियों के पदनाम के आगे आधिकारिक पत्राचार और आदेशों में 'माननीय' शब्द जोड़ा जा रहा है।

खंडपीठ ने स्पष्ट किया कि 'माननीय' शब्द का प्रयोग केवल मंत्रियों और अन्य संप्रभु पदाधिकारियों के लिए उपयुक्त है, न कि नौकरशाहों या राज्य सरकार के अधिकारियों के लिए। कोर्ट ने यह भी उल्लेख किया कि इस मामले में इटावा के जिलाधिकारी ने कानपुर के संभागीय आयुक्त को पत्राचार में 'माननीय आयुक्त' कहकर संबोधित किया है।

कोर्ट ने प्रधान सचिव को निर्देश दिया है कि वे यह स्पष्ट करें कि क्या राज्य सरकार के किसी प्रोटोकॉल के तहत कुछ अधिकारियों को इस शब्द के प्रयोग का अधिकार दिया गया है। मामले की अगली सुनवाई के लिए 19 दिसंबर की तारीख तय की गई है।

केंद्रीय माल एवं सेवा कर आयुक्तालय इलाहाबाद द्वारा छोटे और मझोले व्यापारियों के जीएसटी सम्बंधित समस्याओं के समाधान हेतु बैठक का आयोजन

प्रयागराज। सेंट्रल जीएसटी आयुक्तालय इलाहाबाद द्वारा सिविल लाइन्स स्थित जीएसटी भवन के कौटिल्य सभागार में छोटे और मझोले व्यापारियों / ट्रेडर्स की जीएसटी सम्बंधित समस्याओं के समाधान और जागरूकता के लिए एक बैठक के आयोजन किया गया।

उक्त बैठक की अध्यक्षता रजनी कान्त मिश्र, अपर आयुक्त, सेंट्रल जीएसटी आयुक्तालय इलाहाबाद द्वारा की गयी. सेंट्रल जीएसटी आयुक्तालय इलाहाबाद के अन्य अधिकारी सुरेश कुमार सरोज और अनुपम कुमार तिवारी, सहायक आयुक्त तथा दिलीप यादव, अनुज मिश्र, असीम कुमार सिंह, अधीक्षक आदि भी बैठक में उपस्थित रहे। करदाता सेवा महानिदेशालय नई दिल्ली के अधिकारियों शैलेन्द्र कुमार, सहायक आयुक्त और संसार सिंह तोमर, निरीक्षक ने भी बैठक में हिस्सा लिया. इस दौरान कन्फेडरेशन आफ आल इंडिया ट्रेडर्स की तरफ से प्रदेश अध्यक्ष महेंद्र कुमार गोएल और चार्टर्ड अकाउंटेंट्स एसोसिएशन प्रयागराज की ओर से शाखा के प्रेसिडेंट सीए सुशील कुमार शुक्ला और महिला प्रोफेशनल सीए अनुप्रिया पाण्डेय और सीए आयुषी जैन ने अपने विचार साझा किये. छोटे और मझोले व्यापारियों / ट्रेडर्स ने भी उक्त बैठक में हिस्सा लिया, जिसमे अजय गुप्ता, विभु अग्रवाल, दिनेश केसरवानी, अजय अग्रवाल, आशुतोष गोयल, आलोक अग्रवाल, अंकित अग्रवाल, सौरभ अग्रवाल, राज किशन अग्रवाल, अभिषेक अग्रवाल तथा धर्मेन्द्र कुमार मिश्र आदि प्रमुख रहे।

अंत में रजनी कान्त मिश्र, अपर आयुक्त ने सभी आगंतुकों को बैठक में भाग लेने और अपने विचार साझा करने के लिए धन्यवाद ज्ञापित किया तथा उनके सुझावों और समस्याओं को उचित फोरम पर उठाने का आश्वासन दिया।

भिवंडी में मच्छी मार्केट बंद होने से मछली विक्रेता महिलाओं की बढ़ी परेशानी,मच्छी मार्केट भवन को शीघ्र खोलने की मांग

भिवंडी (संवाददाता)

मंत्र न्यूज

तीनबत्ती में मछली बाजार की इमारत अपनी जर्जर हालत के कारण पिछले छह महीनों से बंद है। मरम्मत कार्य पूरा हुए दो महीने बीत चुके हैं, लेकिन बाजार बंद होने के कारण ग्रामीण गांवों से मछली बेचने आने वाली महिलाओं को अनावश्यक कठिनाइयों का सामना करना पड़ रहा है।यहां बाजार बंद होने के कारण, तालुका के विभिन्न गांवों से आने वाले मछली विक्रेताओं को अपनी बची हुई मछलियां बाहर रखनी पड़ती हैं, जिसके चलते मछली चोरी की लगातार घटनाओं के कारण इन महिलाओं को आर्थिक नुकसान उठाना पड़ता है। यहां बैठने की कोई सुविधा न होने के कारण, इन महिलाओं को पानी भी खरीदना पड़ता है। ये परेशान महिलाएं सोमवार को अपनी शिकायतें लेकर नगर महा पालिका मुख्यालय पहुंचीं, लेकिन उन्हें बिना किसी ठोस आश्वासन के वापस भेज दिया गया।

भिवंडी शहर की तीनबत्ती मछली मार्केट के बंद होने से महिला मछली विक्रेताओं को भारी परेशानी का सामना करना पड़ रहा है। यहाँ व्यापार करने वाली लगभग 50 महिलाएँ इसी तालुका के काल्हेर, काशेली, खरबाव, दुंगे, वड़घर और करिवाली क्षेत्रों से आती हैं और उन्हें यहाँ कोई सुविधा नहीं मिलती। उन्हें प्रतिदिन मार्केट की रसीद फाड़कर पानी खरीदना पड़ता है और शौचालय के लिए उन्हें कुछ दूरी पर स्थित सार्वजनिक शौचालय का उपयोग करना पड़ता है। मछली विक्रेता रेवंती भगत ने मांग की है कि इस समस्या का तत्काल समाधान किया जाए और महिला मछली विक्रेताओं को मच्छी मार्केट में बैठने की अनुमति दी जाए।इधर मार्केट विभाग से इस संबंध में संपर्क करने की कोशिश की गई,लेकिन कोई प्रक्रिया नहीं मिला सका।

फ्लैट बिक्री के नाम पर धोखाधड़ी, तीन आरोपियों पर केस दर्ज

भिवंडी (संवाददाता)

मंत्र न्यूज

भिवंडी। शहर के निजामपुरा इलाके में फ्लैट बेचने के नाम पर लाखों रुपये की धोखाधड़ी का मामला सामने आया है। शांतीनगर पुलिस स्टेशन में दर्ज शिकायत के अनुसार, आरोपियों ने एक ही फ्लैट को अधिक कीमत पर बेचने का झांसा देकर फरियादी से बड़ी रकम वसूल ली। पुलिस के अनुसार, फरियादी एजाज अहमद फजलुर्रशीद अंसारी (40) ने शिकायत दर्ज कराई है कि आरोपी महिला माहेसबा अजमल बिंचु,अंजुम बिंचु और मुफीद ने हाजी अजमल अपार्टमेंट के फ्लैट क्रमांक 401, बाला कंपाउड, निजामपुरा चौथा स्थित फ्लैट को बेचने का सौदा किया। फ्लैट का क्षेत्रफल लगभग 495 वर्गफुट बताया गया और प्रति वर्गफुट 1700 रुपये के हिसाब से कुल 8.41 लाख रुपये में सौदा तय हुआ। आरोप है कि आरोपियों ने फ्लैट का रजिस्ट्रेशन नहीं कराया और बाद में कीमत बढ़ाने की मांग करने लगे। इस दौरान फरियादी से जबरन अतिरिक्त रकम वसूलने का प्रयास किया गया। इतना ही नहीं, सौदे के नाम पर वर्ष 2013 में ही 100 रुपये के स्टांप पेपर पर नोटरी कराकर फरियादी को विश्वास में लिया था। जब फरियादी ने रजिस्ट्रेशन की मांग की तो आरोपियों ने टालमटोल शुरू कर दी। खुद को ठगा हुआ महसूस करने पर फरियादी ने शांतीनगर पुलिस स्टेशन में शिकायत दर्ज कराई। पुलिस ने आरोपियों के खिलाफ भारतीय न्याय संहिता की संबंधित धाराओं के तहत धोखाधड़ी का मामला दर्ज कर जांच शुरू कर दी है।

ऑनलाइन लॉटरी जुए का भंडाफोड़, आरोपी गिरफ्तार

भिवंडी। शहर में अवैध रूप से संचालित ऑनलाइन लॉटरी जुए के एक मामले का पुलिस ने खुलासा किया है। भिवंडी पुलिस ने छापेमारी कर एक आरोपी को रंगेहाथों गिरफ्तार किया है और उसके पास से नकद राशि व जुए से संबंधित सामग्री जब्त की है।

पुलिस से मिली जानकारी के अनुसार, आरोपी की पहचान अब्दुल तारीफ लतीफ खान (37) के रूप में हुई है। वह भिवंडी के नजराना टॉकिज के सामने सब्जी मार्केट इलाके में रहकर ऑनलाइन लॉटरी सेंटर चला रहा था। पुलिस को गुप्त सूचना मिली थी कि उक्त स्थान पर अवैध ऑनलाइन जुआ संचालित किया जा रहा है। सूचना के आधार पर पुलिस टीम ने 17 दिसंबर दोपहर करीब सवा तीन बजे सब्जी मार्केट स्थित नजझाना टर्कीज कर सामने बंद एक दुकान में छापेमारी की। मौके से पुलिस ने आरोपी को गिरफ्तार कर 14,330 की नकद राशि तथा ऑनलाइन जुए में इस्तेमाल होने वाला साहित्य जब्त किया। इस संबंध में आरोपी के खिलाफ जुआर प्रतिबंधित अधिनियम के तहत मामला दर्ज किया है।

भिवंडी में चोरी की दो वारदातें, लाखों का माल उड़ाया, केस दर्ज

भिवंडी (संवाददाता)

मंत्र न्यूज

शहर में चोरी की घटनाएं लगातार बढ़ती जा रही हैं। अलग-अलग थाना क्षेत्रों में हुई दो चोरियों के मामलों में अज्ञात आरोपियों के खिलाफ पुलिस ने केस दर्ज कर जांच शुरू कर दी है। दोनों मामलों में नकदी, सोने के आभूषण और इलेक्ट्रॉनिक सामान पर हाथ साफ किया गया है।

पहली घटना निजामपुरा पुलिस स्टेशन क्षेत्र की है। शिकायतकर्ता जगदीश चंद्रकांत कोडमेंकर (67) के अनुसार,16 दिसंबर की रात 10 बजे से 17 दिसंबर की सुबह 7:30 बजे के बीच अज्ञात चोरों ने उनके भिवंडी स्थित वाणीआली, बाजारपेठ इलाके के घर नंबर 160 को निशाना बनाया। चोरों ने घर के पिछले हिस्से का दरवाजा तोड़कर भीतर प्रवेश किया और सोने के आभूषण व नकदी सहित करीब 3.99 लाख रुपये के आभूषण व नकदी चोरी कर लिया।

दूसरी घटना नारपोली पुलिस स्टेशन क्षेत्र की है। यहां शिकायतकर्ता आनंद जयवंत कांबले (51), जो एक निजी कंपनी में मैनेजर हैं, ने गोदाम में चोरी की शिकायत दर्ज कराई है। 16 दिसंबर की रात से 17 दिसंबर की सुबह के बीच अज्ञात चोरों ने कोहिनूर टेलीवीडियो प्रा. लि. कंपनी के इंडियन लॉजिस्टिक गाला स्थित गोदाम की दीवार और शटर तोड़कर प्रवेश किया। चोरों ने गोदाम में रखे दो होम थिएटर सिस्टम, जिनकी कीमत करीब 64,309 रूपये बताई गई है, चोरी कर लिए,पुलिस दोनों मामलों में भारतीय न्याय संहिता की विभिन्न धाराओं के तहत मामला दर्ज कर आसपास के लगे सीसीटीवी फुटेज खंगाल रही है।

संयुक्त आयुष्मान भारत - महात्मा फुले जन आरोग्य योजना इलाज की संख्या 2,399

मुंबई(संवाददाता)

मंत्र न्यूज

राज्य सरकार ने राज्य में संयुक्त आयुष्मान भारत प्रधानमंत्री जन आरोग्य योजना और महात्मा ज्योतिराव फुले जन आरोग्य योजना को और ज़्यादा प्रभावी बनाने के लिए कई महत्वपूर्ण और मरीज़ों के हित में फैसले लिए हैं। इन सुधारों से आम नागरिकों को ज़्यादा व्यापक, गुणवत्तापूर्ण और कैशलेस स्वास्थ्य सेवाएं मिलने का रास्ता साफ हुआ है।

इस सुधार के तहत, उपलब्ध इलाज की संख्या 1,356 से बढ़ाकर 2,399 कर दी गई है, जिसमें बड़ी संख्या में गंभीर और विशेष इलाज शामिल हैं। इसके साथ ही, अस्पतालों को सरकार से मिलने वाली इलाज की दरों में बढ़ोतरी की गई है और कई पैकेज में भी बदलाव किया गया है। इससे अस्पतालों की भागीदारी बढ़ेगी और मरीज़ों को बेहतर सेवाएं मिलेंगी।

इलाज की गुणवत्ता को और बेहतर बनाने के लिए, NABH और NVAAS जैसे गुणवत्ता मानकों को पूरा करने वाले अस्पतालों को क्लेम राशि पर अतिरिक्त 10 से 15 प्रतिशत प्रोत्साहन देने का फैसला किया गया है। इससे गुणवत्तापूर्ण इलाज को बढ़ावा मिलेगा।

योजना को प्रभावी ढंग से लागू करने और शिकायतों के समाधान के लिए, ज़िला कलेक्टर की अध्यक्षता में एक 'ज़िला निगरानी और शिकायत निवारण समिति' का गठन किया गया है। साथ ही, इस काम की समीक्षा और मार्गदर्शन के लिए पालक मंत्री की अध्यक्षता में एक 'ज़िला स्तरीय सार्वजनिक स्वास्थ्य संरक्षण कार्यकारी' का गठन किया गया है।

मरीज़ों को जानकारी चाहिए या सेवाएं प्राप्त करने में कोई कठिनाई हो, तो संपर्क करने के लिए 24 घंटे टोल-फ्री कॉल सेंटर सेवा शुरू की गई है। इसके लिए निम्नलिखित नंबर उपलब्ध कराए गए हैं: 155388 / 18002332200 और 14555 / 1800111565।

हर मान्यता प्राप्त अस्पताल के सामने के क्षेत्र में एक योजना कक्ष स्थापित करना अनिवार्य कर दिया गया है और इस कक्ष में 'आरोग्य मित्र' नियुक्त किए गए हैं। आरोग्य मित्रों के माध्यम से, मरीज़ों को योजना के बारे में जानकारी दी जाएगी, दस्तावेज़ पूरे किए जाएंगे और कैशलेस इलाज प्राप्त करने के लिए आवश्यक मार्गदर्शन दिया जाएगा।

योजना के तहत दिए जाने वाले इलाज और सुविधाओं से संबंधित शिकायतों के तत्काल समाधान की ज़िम्मेदारी ज़िला समन्वयक, क्षेत्रीय प्रबंधक, कार्यान्वयन सहायता एजेंसियों के ज़िला और मंडल प्रमुखों और ज़िला चिकित्सा अधिकारी को सौंपी गई है। अस्पताल के कमरों में सभी संबंधित अधिकारियों के कॉन्टैक्ट नंबर प्रमुखता से डिस्प्ले करने के भी निर्देश दिए गए हैं।

ये सभी सुधार राज्य के नागरिकों को ज़्यादा भरोसेमंद, सुलभ और अच्छी क्वालिटी की हेल्थकेयर सर्विस देंगे, जो स्वास्थ्य सुरक्षा की दिशा में एक महत्वपूर्ण कदम है।

उद्धव सेना का युवा वोटरों पर फोकस, आदित्य के जिम्मे ये अहम जिम्मेदारी

मुंबई(संवाददाता)

मंत्र न्यूज

राज्य में 29 नगरपालिकाओं के लिए चुनाव की घोषणा होते ही राजनीतिक माहौल गरमा गया है। सभी प्रमुख राजनीतिक दल मुंबई नगर निगम चुनावों के लिए कमर कस रहे हैं, जिन्होंने पूरे देश का ध्यान आकर्षित किया है और ऐसा लगता है कि आने वाले हफ्तों में मुंबई की राजनीति और भी रंगीन हो जाएगी। इस पृष्ठभूमि में, राजनीतिक गलियारों में यह चर्चा चल रही है कि शिवसेना-भाजपा-एनसीपी गठबंधन के रूप में मुंबई नगर निगम चुनाव एक साथ लड़ेंगे। दूसरी ओर, ऐसे संकेत मिल रहे हैं कि ठाकरे बंधुओं का समूह मुंबई नगर निगम को अपने नियंत्रण में रखने के लिए एकजुट हो रहा है। इसलिए, यह चुनाव केवल स्थानीय स्वशासन निकायों तक ही सीमित नहीं रहेगा, बल्कि प्रतिष्ठा और शक्ति की परीक्षा होगी। अगले सप्ताह तक उम्मीदवारों के नामों की सूची को अंतिम रूप दिया जाना है, इसलिए सभी पक्षों के बीच तेजी से गतिविधियां चल रही हैं।

बीएमसी की सत्ता में वापसी की कोशिश में जुटी उद्धव सेना द्वारा आदित्य ठाकरे को मुंबई में एक महत्वपूर्ण जिम्मेदारी दी गई है। आदित्य बीएमसी चुनाव में रैलियों और प्रचार की कमान संभालेंगे। चुनाव में युवा मतदाताओं को उद्धव सेना से जोड़ने की रणनीति का हिस्सा होगा। उद्धव सेना के एक नेता ने कहा कि शिवसेना में विभाजन के बाद से आदित्य ठाकरे बीएमसी में विभिन्न परियोजनाओं और विकास कार्यों पर विशेष नजर रख रहे हैं। उन्होंने बीएमसी में विभिन्न भ्रष्टाचार के मामलों और प्रशासक की नियुक्ति के बाद अराजकता के खिलाफ समय-समय पर अपनी आवाज उठाई है। आदित्य मुंबईकरों की असल दिक्कतों और परेशानियों को जानते हैं, तो उन्हें चुनाव प्रचार के दौरान किन मुद्दों पर जोर देना है, किस मुद्दे को कहां उठाना है, उन्हें पता है।

आधुनिक चुनाव प्रचार विधियों के माध्यम से युवा मतदाताओं पर फोकस

आदित्य ठाकरे बीएमसी सहित तीन से चार मनपाओं के चुनाव पर करीबी नजर रखे हुए हैं। आदित्य आगे आकर कई मुद्दों पर पार्टी का पक्ष रख रहे हैं। इसमें चुनाव आयोग का काम और वोटर लिस्ट में घोटाला शामिल है। हालांकि, बीएमसी सहित सभी चुनाव पार्टी अध्यक्ष उद्धव ठाकरे के नेतृत्व में लड़ा जा रहा है, लेकिन अहम जिम्मेदारियां आदित्य ठाकरे ने संभालने के लिए अपनी तैयारी दिखाई है। आदित्य ठाकरे मनपा चुनाव के दौरान मुंबई के साथ नासिक, पुणे, छत्रपति संभाजी नगर मनपा पर फोकस करेंगे।

वर्ली से चुनाव प्रचार का आगाज

वर्ली के एनएससीआई डोम में आयोजित एक कार्यक्रम में उन्होंने बीएमसी चुनाव प्रचार की औपचारिक शुरुआत की। यहां उन्होंने शिवसैनिकों को संबोधित करते हुए पार्टी के पिछले कामों का जिक्र किया। आदित्य ठाकरे ने कार्यक्रम में पिछले 25 वर्षों में शिवसेना द्वारा मुंबई के लिए किए गए विकास कार्यों का विस्तृत प्रेजेंटेशन पेश किया।

कमिश्नर डॉ. कैलाश शिंदे ने चुनाव संबंधी कामों के लिए नोडल अधिकारियों की समीक्षा बैठक की

मुंबई(संवाददाता)

मंत्र न्यूज

नवी मुंबई नगर निगम के आम चुनाव 2025-26, 15 जनवरी 2026 को होने वाले हैं और 15 दिसंबर से आचार संहिता लागू कर दी गई है। आचार संहिता के अनुसार, माननीय राज्य चुनाव आयोग के आदेशों के अनुसार 72 घंटे के भीतर अनाधिकृत बैनर, पोस्टर और होर्डिंग्स के खिलाफ कार्रवाई शुरू की गई है। इसके तहत, 72 घंटे के भीतर आठ विभागीय कार्यालय क्षेत्रों में 1001 अनाधिकृत बैनर, 578 कटआउट/होर्डिंग्स, 204 पोस्टर, 120 झंडे और 84 भित्तिचित्र हटाए गए हैं।

इसी तरह, सरकारी कार्यालयों और इमारतों के साथ-साथ सार्वजनिक और निजी स्थानों, जिसमें नगर निगम की संपत्तियां भी शामिल हैं, से राजनीतिक सामग्री भी हटा दी गई है। इस संबंध में की गई कार्रवाई की समीक्षा नगर आयुक्त डॉ. कैलाश शिंदे ने चुनाव के लिए नियुक्त नोडल अधिकारियों की समीक्षा बैठक में की। इस अवसर पर अतिरिक्त आयुक्त श्री सुनील पवार और डॉ. राहुल गेठे, उप चुनाव आयुक्त भागवत दोइफोडे, शहर अभियंता श्री शिरीष आर्डवाड, मुख्य लेखा और वित्त अधिकारी श्री सत्यवान उबाले, अतिरिक्त शहर अभियंता श्री अरविंद शिंदे और अन्य विभाग प्रमुख नोडल अधिकारी उपस्थित थे।

चुनाव के अनुसार निर्धारित समय के भीतर आवश्यक कार्यों के लिए नोडल अधिकारियों को नियुक्त किया गया है और आयुक्त ने विषयवार इसकी समीक्षा की। कल, राजनीतिक दलों के प्रतिनिधियों की एक बैठक हुई और उन्हें चुनाव से संबंधित कार्यों के बारे में सूचित किया गया। इसी तरह, आचार संहिता की अवधि के दौरान पालन किए जाने वाले नियमों के बारे में भी बताया गया। तदनुसार, यह जांचने के लिए कि आचार संहिता का पालन किया जा रहा है या नहीं, अतिरिक्त आयुक्त श्री सुनील पवार की देखरेख में एक आचार संहिता सेल स्थापित किया गया है और तदनुसार, चुनाव निर्णय अधिकारी-वार गश्ती दल और चेक पोस्ट स्थायी दल और वीडियो निगरानी दल स्थापित किए गए हैं और आयुक्त ने कार्रवाई को सख्ती से लागू करने के निर्देश दिए।

अतिरिक्त आयुक्त डॉ. राहुल गेठे कानून और व्यवस्था के संबंध में आवश्यक कार्रवाई करने के लिए पुलिस विभाग के साथ समन्वय करेंगे, और चुनाव अवधि और मतदान के लिए एक सुरक्षा योजना तैयार की जा रही है। चीफ अकाउंट्स और फाइनेंस ऑफिसर, श्री सत्यवान उबाले, मीडिया सेल और श्ण्श् कमेटी के नोडल अधिकारी हैं। इनका काम चुनावों के लिए उम्मीदवारों और पार्टियों द्वारा दिए गए विज्ञापन सामग्री की जांच और सर्टिफ़िकेट देना, साथ ही मीडिया की निगरानी करना और मीडिया को चुनावों से संबंधित जानकारी देना है। इस सेल का काम शुरू कर दिया गया है।

इस बार, चूंकि चार सदस्यों वाला वार्ड स्ट्रक्चर है, इसलिए 28 में से 27 वार्डों में, एक वोटर को चार सदस्यों के लिए वोट देना होगा और वार्ड नंबर 28 में, उसे 3 सदस्यों के लिए वोट देना होगा। इसी के अनुसार, वोटिंग प्रक्रिया के बारे में बड़े पैमाने पर जागरूकता फैलाने के लिए विभिन्न मीडिया का इस्तेमाल किया जाएगा और सॉलिड वेस्ट मैनेजमेंट के डिप्टी कमिश्नर डॉ. अजय गाडे वोटर जागरूकता कार्य के लिए नोडल अधिकारी हैं।

ये काम चुनाव के पहले चरण में बहुत महत्वपूर्ण हैं और कमिश्नर ने उसी के अनुसार तुरंत कार्रवाई करने का निर्देश दिया। इसके साथ ही, वोटिंग और गिनती के लिए ज़रूरी गतिविधियों की योजना तुरंत शुरू करने और रोज़ाना प्रोग्रेस रिपोर्ट नियमित रूप से जमा करने के स्पष्ट निर्देश दिए गए।

नामांकन पत्र दाखिल करते समय, संभावित उम्मीदवारों को संपत्ति कर, जल कर और विभिन्न विभागों से अनापत्ति प्रमाण पत्र (नो ऑब्जेक्शन सर्टिफ़िकेट) की आवश्यकता होती है और इस संबंध में, सभी की सुविधा के लिए, कमिश्नर द्वारा यह सुनिश्चित करने के लिए तुरंत कार्रवाई की जानी चाहिए कि सभी आवश्यक प्रमाण पत्र प्रत्येक विभाग के कार्यालय में सिंगल विंडो योजना के माध्यम से एक ही स्थान पर उपलब्ध हों। इसी तरह, कमिश्नर ने संकेत दिया कि बैठकों के लिए दिए गए मैदानों की अनुमति से संबंधित प्रक्रिया भी इस तरह से की जानी चाहिए जिससे सभी को समान न्याय सुनिश्चित हो।

चुनाव कार्य के लिए वोटिंग और वोटों की गिनती के लिए 6275 कर्मचारियों की आवश्यकता है और मानव संसाधन प्रबंधन के नोडल अधिकारी, प्रशासन विभाग के डिप्टी कमिश्नर किसानराव पालंडे को उन्हें उपलब्ध कराने के लिए तुरंत कार्रवाई करने के निर्देश दिए गए हैं।

कमिश्नर ने यह भी सलाह दी कि सभी पोलिंग स्टेशनों और रिटर्निंग अधिकारियों के कार्यालयों को जियो-टैग किया जाना चाहिए ताकि उनका स्थान तुरंत सभी को पता चल सके।

नवी मुंबई नगर निगम चुनाव को निडर, स्वतंत्र और पारदर्शी माहौल में कराने के उद्देश्य से, नगर आयुक्त डॉ. कैलाश शिंदे के मार्गदर्शन में विभिन्न चुनाव संबंधी कार्यों के लिए नियुक्त नोडल अधिकारियों के माध्यम से आवश्यक कार्रवाई की जा रही है।

आजम खान को बड़ी राहत!

2019 के भड़काऊ भाषण केस में एमपी-एमएलए कोर्ट का बड़ा फैसला–सबूत नहीं, किया बरी

लखनऊ **(एजेंसी)**। रामपुर की एमपी-एमएलए स्पेशल कोर्ट (मजिस्ट्रेट ट्रायल) ने समाजवादी पार्टी के वरिष्ठ नेता मोहम्मद आजम खान को भड़काऊ भाषण के एक पुराने मामले में बरी कर दिया है। यह मामला साल 2019 के लोकसभा चुनाव के दौरान दर्ज हुआ था। कोर्ट ने सबूतों के अभाव में आजम खान को दोषमुक्त करार दिया। अभियोजन और बचाव पक्ष की लंबी बहस सुनने के बाद अदालत ने फैसला सुनाया। हालांकि, इस समय आजम खान एक अन्य मामले में मिली 7 साल की सजा के चलते रामपुर जेल में बंद हैं, जो उन्हें 17 नवंबर 2025 को सुनाई गई थी। यह मामला 2019 के लोकसभा चुनाव के समय का है, जब आजम खान सपा-बसपा गठबंधन के उम्मीदवार थे। चुनाव प्रचार के दौरान उन्होंने रामपुर स्थित सपा कार्यालय में कार्यकर्ताओं को संबोधित किया था। उसी भाषण को लेकर तत्कालीन कांग्रेसी नेता फैसल खान 'लाला' ने शिकायत दर्ज कराई थी। शिकायत में आरोप लगाया गया था कि आजम खान ने जिलाधिकारी और अन्य प्रशासनिक अधिकारियों के खिलाफ भड़काऊ बयान दिए और कार्यकर्ताओं को हिंसा के लिए उकसाया। इसके आधार पर रामपुर शहर कोतवाली में उनके खिलाफ मामला दर्ज किया गया था। सुनवाई के दौरान अभियोजन पक्ष की ओर से एक सीडी अदालत में पेश की गई थी। इस वीडियो में आजम खान पर आरोप था कि उन्होंने कहा था कि अधिकारी रामपुर को 'खून से नहलाना चाहते हैं' और जिन जिलों में वे पहले तैनात रहे हैं, वहां कमजोर लोगों पर अत्याचार हुए हैं।हालांकि, कोर्ट ने दोनों पक्षों की दलीलें सुनने और उपलब्ध साक्ष्यों की जांच के बाद यह माना कि आरोपों को साबित करने के लिए पर्याप्त और ठोस सबूत नहीं हैं। इसी आधार पर आजम खान को इस मामले में बरी कर दिया गया। आजम खान के खिलाफ रामपुर में बड़ी संख्या में मुकदमे दर्ज हैं, जिनमें से कई अभी अदालतों में लंबित हैं। ऐसे समय में भड़काऊ भाषण के इस पुराने केस में बरी होना उनके लिए कानूनी रूप से बड़ी राहत माना जा रहा है। भले ही वे फिलहाल जेल में हैं, लेकिन इस फैसले को उनके समर्थक एक अहम जीत के तौर पर देख रहे हैं।

वृंदावन में आश्रम का सनसनीखेज मामला!

अनिरुद्धाचार्य महाराज के गार्ड ने दुकानदार को दिनदहाड़े घसीटा और पीटा, मच गया हड़कंप

लखनऊ **(एजेंसी)**। प्रसिद्ध कथावाचक अनिरुद्धाचार्य महाराज के सुरक्षाकर्मी एक बड़े विवाद में घिर गए हैं। वृंदावन स्थित उनके गौरी गोपाल आश्रम के पास दुकान चलाने वाले एक दुकानदार की कथित रूप से बेरहमी से पिटाई किए जाने का मामला सामने आया है। घटना के बाद पीड़ित परिवार ने अनिरुद्धाचार्य महाराज और उनके सुरक्षाकर्मियों पर गंभीर आरोप लगाए हैं।

पीड़ित दुकानदार विवेक कुमार गौरी गोपाल आश्रम के पास ही अपनी दुकान चलाते हैं। परिजनों का आरोप है कि दिनदहाड़े आश्रम के सुरक्षाकर्मी दुकान पर पहुंचे और विवेक को जबरन घसीटते हुए आश्रम के अंदर ले गए। दुकानदार की बेटी का कहना है कि जब उनके पिता ने इसका विरोध किया तो सुरक्षाकर्मियों ने उन्हें बुरी तरह पीटना शुरू कर दिया। मारपीट में विवेक को

गंभीर चोटें आई हैं।

मारपीट के बाद घायल दुकानदार को अस्पताल ले जाया गया, लेकिन परिजनों का कहना है कि वहां भी उन्हें सही इलाज नहीं मिल रहा है। दुकानदार की पत्नी ने आरोप लगाया कि अस्पताल प्रशासन अनिरुद्धाचार्य महाराज के दबाव में काम कर रहा है। उनका दावा है कि भर्ती होने के बावजूद विवेक को न तो समय पर दवाएं दी गईं और न ही उचित इलाज किया जा रहा है, जिससे उनकी हालत और बिगड़ सकती है।

पीड़ित परिवार का गुस्सा पुलिस कार्रवाई को लेकर भी सामने आया है। पत्नी का कहना है कि पुलिस ने आरोपियों पर जानबूझकर हल्की धाराएं लगाई हैं। उन्होंने मांग की है कि आश्रम के नाम पर घूम रहे इन लोगों को गिरफ्तार किया जाए और उनके खिलाफ सख्त कानूनी कार्रवाई हो। परिजनों का कहना है कि अगर जल्द न्याय नहीं मिला तो वे आंदोलन करने को मजबूर होंगे। घटना से जुड़ी तस्वीरें और जानकारी सामने आने के बाद सोशल मीडिया पर भी लोगों का गुस्सा देखने को मिल रहा है। लोग मामले की निष्पक्ष जांच और दोषियों पर कड़ी कार्रवाई की मांग कर रहे हैं। फिलहाल अनिरुद्धाचार्य महाराज की ओर से इस मामले पर कोई आधिकारिक बयान सामने नहीं आया है। वहीं स्थानीय पुलिस ने मामले की गंभीरता को देखते हुए जांच शुरू कर दी है और सभी पक्षों से जानकारी जुटाई जा रही है।

एसएमएटी : ईशान किशन का फाइनल में तूफानी शतक, रिकॉर्ड बुक में दर्ज कराया नाम

नई दिल्ली **(एजेंसी)**। भारतीय घरेलू क्रिकेट में ईशान किशन ने एक बार फिर साबित कर दिया कि उनका नाम बड़े मैचों के खिलाड़ियों में क्यों लिया जाता है। पुणे के एमसीए स्टेडियम में खेले गए सैयद मुश्ताक अली ट्रॉफी के फाइनल में झारखंड के कप्तान ने हरियाणा के खिलाफ विस्फोटक शतक जड़कर फाइनल मुकाबले को खास बना दिया। टीम इंडिया से बाहर चल रहे इस विकेटकीपर-बल्लेबाज ने न सिर्फ रिकॉर्ड बुक में अपना नाम दर्ज कराया, बल्कि शानदार फॉर्म से चयनकर्ताओं को भी मजबूत संदेश दे दिया।

टॉस के बाद झारखंड की बल्लेबाजी की जिम्मेदारी संभालते हुए ईशान किशन ने शुरुआत से ही आक्रामक रुख अपनाया। हरियाणा के गेंदबाजों पर दबाव बनाते हुए उन्होंने मैदान के चारों ओर आकर्षक शॉट खेले। पावरप्ले में तेजी से रन बटोरने के बाद किशन ने मिडिल ओवर्स में भी स्ट्राइक रोटेशन और बड़े शॉट्स का बेहतरीन संतुलन बनाए रखा।

किशन ने अपना छठा टी -20 शतक सिर्फ 45 गेंदों में पूरा किया। यह ऐतिहासिक लम्हा तब आया जब उन्होंने मीडियम पेसर अंशुल कंबोज की गेंद पर कवर के ऊपर से एक हाथ से शानदार छक्का जड़ा। स्टेडियम में मौजूद दर्शकों के लिए यह पल किसी हाइलाइट से कम नहीं था और झारखंड डगआउट में जबरदस्त उत्साह देखने को मिला।

इस शतक के साथ ईशान किशन ने सैयद मुश्ताक अली ट्रॉफी के इतिहास में सबसे ज्यादा शतकों के मामले में अभिषेक शर्मा के रिकॉर्ड की बराबरी कर ली। यह टूर्नामेंट में उनका पांचवां शतक था, जो उनकी निरंतरता और दबाव में प्रदर्शन करने की क्षमता को दर्शाता है। मौजूदा सीजन में यह उनका दूसरा शतक रहा, इससे पहले उन्होंने त्रिपुरा के खिलाफ 50 गेंदों में नाबाद 113 रन की पारी खेली थी। झारखंड की पारी के 15वें ओवर में सुमित कुमार ने ईशान किशन को 49 गेंदों में 101 रन पर क्लीन बोल्ड किया। हालांकि तब तक किशन अपना काम कर चुके थे। उनकी इस पारी ने झारखंड को बड़े स्कोर की नींव दे दी और हरियाणा के गेंदबाजों को बैकफुट पर धकेल दिया।पूरा सैयद मुश्ताक अली ट्रॉफी सीजन ईशान किशन के नाम रहा है। 10 पारियों में उन्होंने 197.32 के जबरदस्त स्ट्राइक रेट से 517 रन बनाए हैं और टूर्नामेंट के सबसे ज्यादा रन बनाने वाले बल्लेबाज बने हुए हैं।

'सबसे खराब टेक्नोलॉजी' : एडिलेड टेस्ट में स्निको विवाद पर मिशेल स्टार्क का तीखा हमला

नई दिल्ली **(एजेंसी)**। एशेज सीरीज के एडिलेड टेस्ट में अंपायरिंग और टेक्नोलॉजी एक बार फिर बड़े विवाद की वजह बन गई। दूसरे दिन लगातार दो फैसलों ने खिलाड़ियों और दर्शकों, दोनों को हैरान कर दिया। ऑस्ट्रेलिया के अनुभवी तेज़ गेंदबाज़ मिशेल स्टार्क ने स्निको टेक्नोलॉजी पर खुलकर नाराज़गी जताते हुए इसे 'सबसे खराब टेक्नोलॉजी' करार दिया और यहां तक कह दिया कि इसे हटाने की ज़रूरत है। विवादित फैसलों के बीच इंग्लैंड और ऑस्ट्रेलिया, दोनों ही खेमों में असंतोष साफ दिखाई दिया।

विवाद की शुरुआत तब हुई जब पैट कमिंस की एक तेज़ शॉर्ट बॉल इंग्लैंड के बल्लेबाज़ स्मिथ पर अजीब उछाल लेकर आई। स्मिथ ने खुद को बचाने की कोशिश की और गेंद फर्स्ट स्लिप की ओर गई, जहां उस्मान ख्वाजा ने आगे की ओर डाइव लगाई।

ऑस्ट्रेलियाई खिलाड़ियों ने ज़ोरदार अपील की, लेकिन ऑन-फील्ड अंपायर को संदेह था कि गेंद बल्ले या ग्लव्स से लगी है या नहीं। मामला थर्ड अंपायर के पास गया। रिप्ले में साफ दिखा कि गेंद स्मिथ के हेलमेट से टकराई थी, इसके बावजूद स्निको मीटर में स्पाइक नजर आया। अंततः फैसला नॉट-आउट रहा, लेकिन इसी स्पाइक ने पूरे विवाद को जन्म दे दिया। इस फैसले के बाद मिशेल स्टार्क को स्टंप माइक पर अंपायर से चर्चा करते हुए सुना गया। उन्होंने साफ शब्दों में कहा कि स्निको टेक्नोलॉजी भरोसेमंद नहीं रही है। स्टार्क ने कहा कि यह टेक्नोलॉजी पहले भी गलत साबित हो चुकी है और एक बार फिर खिलाड़ियों को भ्रमित कर रही है। उनके मुताबिक, ऐसे अहम टेस्ट मैच में इतनी बड़ी गलती स्वीकार्य नहीं है।

पहले विवाद की गर्मी अभी ठंडी भी नहीं हुई थी कि जेमी स्मिथ के आउट होने पर एक और बहस छिड़ गई। पैट कमिंस की शॉर्ट गेंद पर स्मिथ ने पुल शॉट खेलने की कोशिश की, लेकिन संपर्क साफ नहीं था। गेंद विकेटकीपर एलेक्स कैरी तक पहुंची और अंपायर ने फैसला थर्ड अंपायर को भेजा। हालांकि वीडियो रिप्ले में बल्ले और गेंद के बीच साफ गैप नजर आ रहा था, लेकिन गेंद के बल्ले के पास से गुजरते ही स्निको में एक स्पाइक दर्ज हुआ। इसी आधार पर थर्ड अंपायर ने स्मिथ को आउट करार दे दिया।

एडिलेड टेस्ट की घटनाओं ने एक बार फिर स्निको टेक्नोलॉजी की विश्वसनीयता पर सवाल खड़े कर दिए हैं। खिलाड़ी, पूर्व क्रिकेटर और फैंस अब यह सोचने पर मजबूर हैं कि क्या सिर्फ ऑडियो स्पाइक के आधार पर बड़े फैसले लेना सही है।

छोटी कारों को कड़े ईंधन दक्षता मानकों से छूट देने का टाटा मोटर्स ने किया विरोध

नई दिल्ली **(एजेंसी)**। अग्रणी वाहन निर्माता टाटा मोटर्स ने छोटी पेट्रोल कारों को कड़े कॉरपोरेट औसत ईंधन दक्षता (कैफे) मानकों से छूट देने का विरोध करते हुए कहा है कि इससे देश में टिकाऊ एवं स्वच्छ प्रौद्योगिकी पर आधारित मॉडल, खासकर इलेक्ट्रिक वाहनों (ईवी) का विस्तार प्रभावित होगा। टाटा समूह की कंपनी ने प्रधानमंत्री कार्यालय (पीएमओ) को भेजे पत्र में कहा है कि भविष्य की प्रौद्योगिकियों में नवाचार और सीधे उन्नत प्रौद्योगिकी को अपनाने की क्षमता अब भारत में दिखने लगी है और यात्री कारों में ईवी की हिस्सेदारी करीब पांच प्रतिशत तक पहुंच गई है।

कंपनी ने इस पत्र में कहा, 'हम यह कहना चाहते हैं कि 909 किलोग्राम तक वजन वाली, 1200 सीसी से कम इंजन क्षमता और 4, 000 मिलीमीटर से कम लंबाई वाली पेट्रोल कारों को इन मानकों से छूट देने का प्रावधान, टिकाऊ प्रौद्योगिकी अपनाने पर फोकस को कमजोर कर सकता है।' कैफे मानक एक वाहन कंपनी के सभी मॉडल की औसत ईंधन दक्षता और कार्बन उत्सर्जन को नियंत्रित करने के लिए तय किए जाते हैं। इनका उद्देश्य वाहन कंपनियों को इलेक्ट्रिक और अन्य स्वच्छ प्रौद्योगिकी अपनाने के लिए प्रोत्साहित करना है।

टाटा मोटर्स ने इस बात को लेकर आगाह किया कि वाहन के वजन के आधार पर छूट देने से वाहन कंपनियां आवश्यक सुरक्षा सुविधाओं की कीमत पर वजन कम करने के लिए प्रोत्साहित हो सकती हैं। इससे पिछले कुछ वर्षों में वाहन सुरक्षा के क्षेत्र में हुई प्रगति पर असर पड़ सकता है। कंपनी ने सरकार से अपील की है कि कैफे मानकों के तहत रियायत देने के उद्देश्य से आकार या वजन के आधार पर कारों की कोई विशेष श्रेणी न बनाई जाए।

सरकार ने अप्रैल 2027 से मार्च 2032 के बीच यात्री वाहनों की ईंधन खपत और कार्बन उत्सर्जन को नियंत्रित करने के लिए कैफे मानदंडों के मसौदा नियम जारी किए हैं। प्रस्तावित ढांचा कंपनियों के लिए सख्त समग्र लक्ष्य तय करता है, जबकि छोटी पेट्रोल कारों को कुछ राहत देने का प्रावधान भी करता है। टाटा मोटर्स ने कहा कि वाहन की किसी विशेष उप-श्रेणी को मानकों से छूट देने से ईवी जैसे विकल्प अपनाने की जरूरत कम हो जाती है।

फ्रांस के पूर्व स्ट्राइकर हेनरी को मिलेगा स्पोर्ट्स पर्सनैलिटी लाइफटाइम अचीवमेंट अवॉर्ड

लंदन। आर्सेनल और फ्रांस के पूर्व स्ट्राइकर थियरी हेनरी को 2025 के बीबीसी स्पोर्ट्स पर्सनैलिटी ऑफ द ईयर कार्यक्रम में आज लाइफटाइम अचीवमेंट अवॉर्ड् से सम्मानित किया जाएगा। 2014 में पेशेवर फुटबॉल से संन्यास लेने वाले हेनरी ने इस पुरस्कार से सम्मानित किये जाने को लेकर कहा कि यह सम्मान मिलना बहुत गर्व की बात है। उन्होंने कहा, 'फुटबॉल ने मुझे सब कुछ दिया है और मैंने भी इसे अपना सब कुछ दिया है। इस लाइफटाइम अचीवमेंट अवॉर्ड के साथ इसके इतिहास का हिस्सा बनने के लिए पहचाना जाना, और फैंस और मेरे टीम के साथियों के लिए अपनी पहचान बनाना, यह कुछ ऐसा है जिसे मैं कभी हल्के में नहीं लूंगा।'

आर्सेनल के साथ दो बार खेलते हुए, हेनरी ने 377 मैचों में 228 गोल किए, और 2005 में इयान राइट को पीछे छोड़कर क्लब के सर्वकालिक शीर्ष स्कोरर बन गए। गनर्स के साथ उनके सम्मानों में दो प्रीमियर लीग खिताब और तीन एफए कप शामिल हैं, जिसमें सबसे खास 2003-04 का सीजन था जब आर्सेनल अजेय रहा और 'इनविंसिबल' का दर्जा हासिल किया। हेनरी ने चार बार प्रीमियर लीग गोल्डन बूट जीता, जो एक संयुक्त रिकॉर्ड है और लगातार 6 सीजन तक पीएफए टीम ऑफ द ईयर में नामित हुए।

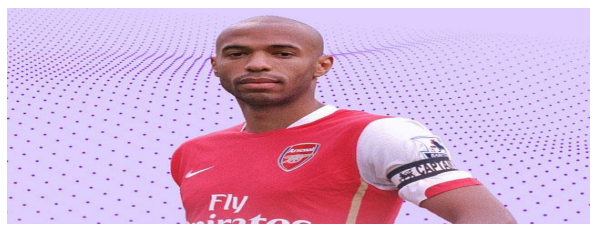

पीएसजी ने जीता फीफा इंटरकॉन्टिनेंटल कप, पेनल्टी शूटआउट में फ्लेमेंगो को हराया

दोहा (कतर)। पेरिस सेंट-जर्मेन (पीएसजी) ने रोमांचक फाइनल मुकाबले में ब्राज़ील की फ्लेमेंगो टीम को पेनल्टी शूटआउट में हराकर फीफा इंटरकॉन्टिनेंटल कप का खिताब अपने नाम कर लिया। यह पीएसजी की इस साल की छठी बड़ी ट्रॉफी है, जिससे क्लब का सुनहरा सीजन और भी यादगार बन गया।

अल रेयान स्थित अहमद बिन अली स्टेडियम में खेले गए इस फाइनल में निर्धारित समय और अतिरिक्त समय के बाद स्कोर 1-1 से बराबर रहा। इसके बाद हुए पेनल्टी शूटआउट में पीएसजी ने फ्लेमेंगो को 2-1 से मात देकर खिताबी जीत दर्ज की।

मैच की शुरुआत से ही दोनों टीमों ने आक्रामक रुख अपनाया। पीएसजी को पहला गोल 38वें मिनट में खिचा क्वारात्सखेलिया ने दिलाया, जिससे फ्रेंच क्लब ने बढ़त हासिल की। हालांकि, हाफटाइम के बाद फ्लेमेंगो ने जोरदार वापसी की। 62वें मिनट में जोर्जिन्हो ने पेनल्टी को गोल में बदलते हुए स्कोर बराबर कर दिया। इसके बाद दोनों टीमों को कई मौके मिले, लेकिन गोल करने में सफलता नहीं मिली। मैच के अंतिम क्षणों में पीएसजी गोल के बेहद करीब पहुंचा, मगर फ्लेमेंगो के गोलकीपर ऑगस्टिन रॉसी ने शानदार बचाव कर टीम को बचाए रखा। निर्धारित समय और अतिरिक्त समय में कोई गोल नहीं होने के बाद मुकाबला पेनल्टी शूटआउट में पहुंचा। यहां पीएसजी के खिलाड़ियों ने बेहतर संयम दिखाया और फ्लेमेंगो को 2-1 से हराकर ट्रॉफी पर कब्जा जमाया।

फीफा इंटरकॉन्टिनेंटल कप जीतने के साथ ही पीएसजी ने इस साल अपनी छठी ट्रॉफी हासिल की। इससे पहले क्लब ने लीग 1, कूप डी फ्रांस, ट्रॉफी डेस चैंपियंस, यूईएफए चैंपियंस लीग और यूईएफए सुपर कप के खिताब भी अपने नाम किए थे।

कौन हैं पायल गेमिंग? प्राइवेट वीडियो लीक होने के बाद विवादों में घिरी, एमएमएस पर मचा बवाल

इंफ्लुएंसर और पॉपुलर यूट्यूबर पायल धारे, जो सोशल मीडिया पर पायल गेमिंग के नाम से जानी जाती हैं, एक प्राइवेट वीडियो के सोशल मीडिया पर सर्कुलेट होने के बाद ऑनलाइन अटकलों में घिर गई हैं, जिसमें दावा किया जा रहा है कि क्लिप में दिख रही महिला वही हैं। उनके फैंस तुरंत उनकी मदद के लिए आगे आए और इसे एक डीपफेक क्लिप बताया।

एक प्राइवेट वीडियो ऑनलाइन सर्कुलेट होने लगा, जिसमें दावा किया जा रहा था कि क्लिप में दिख रही महिला वही हैं। हालांकि, इस पर कोई पुष्टि नहीं हुई है। उनके फैंस ने सोशल मीडिया पर जाकर दावा किया कि यह एक डीपफेक वीडियो है। इसी बीच, आइए पायल गेमिंग और वह क्या करती हैं, इसके बारे में और जानते हैं। यह वीडियो सोशल मीडिया पर तेजी से फैल गया, जिसमें कई यूजर्स ने बिना किसी पुष्टि के पायल गेमिंग का नाम इससे जोड़ा। इसके

तुरंत बाद, उनके फैंस उनके बचाव में आगे आए, इस बात पर जोर देते हुए कि क्लिप नकली लग रही थी और आरोप लगाया कि यह ध्यान आकर्षित करने के लिए बनाया गया एक एआई जेनरेटेड डीपफेक क्लिप हो सकता है। ऑनलाइन चर्चा के बावजूद, पायल गेमिंग ने अब तक सार्वजनिक रूप से कोई टिप्पणी नहीं की है या दावों पर कोई बयान जारी नहीं किया है। वह अपनी दुबई यात्रा की झलकियां पोस्ट कर रही हैं।

जैसे-जैसे स्क्रीनशॉट और छोटी क्लिप सर्कुलेट होती रहीं, उनके फैंस की चिंता बढ़ती गई। कई लोगों ने यूजर्स से जिम्मेदारी से काम करने और बिना वेरिफाई किए कंटेंट शेयर न करने का आग्रह किया। एक यूजर ने लिखा, 'लोगों को यह समझने की जरूरत है कि अब डीपफेक वीडियो बनाना कितना आसान है। बिना सबूत के पायल गेमिंग का नाम इसमें घसीटना गलत है।'

एक अन्य यूजर ने ऐसे कंटेंट के दुरुपयोग की निंदा करते हुए कहा, 'मैं उनका फैन भी नहीं हूं, लेकिन यह असली नहीं लग रहा है। व्यूज के लिए किसी की इमेज खराब करने के लिए एआई वीडियो का इस्तेमाल करना घिनौना है।'

पायल ने सिर्फ़ दो सालों में यूट्यूबर पर एक मिलियन सब्सक्राइबर पूरे कर लिए, जो किसी भी क्रिएटर के लिए एक बड़ी उपलब्धि है। उन्होंने इस प्लेटफ़ॉर्म पर तीन मिलियन से ज़्यादा सब्सक्राइबर वाली पहली भारतीय महिला गेमर बनकर इतिहास रचा, जिससे देश में सबसे महत्वपूर्ण गेम डेवलपर्स में से एक के रूप में उनकी जगह पक्की हो गई।

डीजीएफटी ने भारत-यूएई व्यापार समझौते के तहत सोने के आयात के लिए बोलियां आमंत्रित कीं

नई दिल्ली **(एजेंसी)**। विदेश व्यापार महानिदेशालय (डीजीएफटी) ने बुधवार को कहा कि उसने भारत-यूएई व्यापक आर्थिक साझेदारी समझौते (सीईपीए) के तहत 2025-26 के लिए सोने के आयात कोटा के पहले चरण का आवंटन करने के लिए बोलियां आमंत्रित की हैं। अक्टूबर में यह निर्णय लिया गया था कि भारत-संयुक्त अरब अमीरात (यूएई) सीईपीए के तहत सोने के लिए शुल्क दर कोटा (टीआरक्यू) का आवंटन प्रतिस्पर्धी बोली/ निविदा प्रक्रिया के आधार पर किया जाएगा।

डीजीएफटी ने एक सार्वजनिक सूचना में कहा, ''इसके अनुसार, विदेश व्यापार महानिदेशालय वित्त वर्ष 2025-26 के लिए भारत- यूएई व्यापक आर्थिक साझेदारी समझौते (सीईपीए) के तहत सोने के

टीआरक्यू के पहले चरण के आवंटन के लिए बोलियां/ निविदा आमंत्रित करता है।'' शुल्क दर कोटा के तहत, तय मात्रा तक कुछ वस्तुओं का आयात कम शुल्क पर करने की अनुमति दी जाती है। डीजीएफटी ने सोने के आयात के लिए टीआरक्यू के पहले चरण के आवंटन की प्रक्रिया भी निर्धारित की है। मौजूदा आवंटन चरण में कुल मात्रा 30 टन तक सीमित रखी गई है।

मध्य रेल
सोलापुर मंडल
विद्युतीकरण कार्य

भारत के राष्ट्रपति के लिए और उनकी ओर से वरिष्ठ मंडल विद्युत इंजीनियर (क.वि), मध्य रेल, सोलापुर, निम्नलिखित कार्य के लिए ख्याति प्राप्त, अनुभवी और लाईसेंसधारी विद्युत ठेकेदारों से रेल्वे की ई प्रोक्यूरमेंट वेबसाइट **www.ireps.gov.in** पर ऑनलाइन ई निविदा आमंत्रित करते है। **निविदा क्रं.: सोला/क.वि./नि/2025/29R, दिनांक: 17.12.2025. कार्य का नाम**: सोलापुर मंडल के अनवायर्ड पिट लाइन / साइडिंग का विद्युतीकरण का कार्य। (पुनर्निविदा)। **अनुमानित लागत**: रु.1,53,83,701.79. **बयाना राशि**: रु.2,26,900/-. **कार्य पुरा करने की अवधि**: 12 माह। **निविदा प्रस्ताव की वैधता**: 60 दिन। **वेवसाइट पर निविदा बंद होने की तिथि और समय: दि. 12.01.2026 को 15:00 बजे।**

वरिष्ठ मंडल विद्युत इंजिनीअर, मध्य रेल, सोलापुर
DE/Sur-70
खतरनाक व विस्फोटक सामान के साथ यात्रा करना दंडनीय अपराध है

मध्य रेल
ई-निविदा सूचना

मध्य रेलवे के नागपुर मंडल पर निम्नलिखित कार्य के निष्पादन के लिए स्थापित ठेकेदारों से सीनियर डिईई / टिआरएस / ईएलएस / एक्यू द्वारा डिजिटल रुप से हस्ताक्षरित ऑनलाइन खुली ई-निविदाएं आमंत्रित की जाती है। **ई-निविदा सूचना क्रमांक.: ELS/AQ/DRG/WCQ/25-26/24, दिनांक 15-12-2025. कार्य का नाम**: ईएलएस / अजनी के एसी लोकोमोटिव के विभिन्न क्षमता वाले डीसीपी और सीओ2 प्रकार के अग्निशामक यंत्रों (Fire Entinguishers) की मरम्मत/ ओवरहॉलिंग और रीफिलिंग करना। **कार्य की अनुमानित लागत**: रु. 3,34, 032.45. **बयाना राशि**: रु. 6,700/-. **टेंडर जमा करने की आखिरी तारीख और समय: 08.01.2026 Time 15:00 Hrs. वेबसाइट का पता: http:www.ireps.gov.in**

सीनियर डिईई/टिआरएस/ईएल एस/एक्यू मध्य रेल, नागपुर
DE/346
खतरनाक व विस्फोटक सामान के साथ यात्रा करना दंडनीय अपराध है

मध्य रेल
सोलापुर मंडल
निर्माण और आपूर्ति कार्य

भारत के राष्ट्रपति के लिए एवं उनकी ओर से मंडल स्टोर कार्यालय मध्य रेलवे, सोलापुर, निम्नलिखित कार्यों के लिए सक्षम, प्रतिष्ठित फर्मों/ठेकेदारों से रेलवे की ई-प्रोक्योरमेंट वेबसाइट **www.ireps.gov.in** पर ऑनलाइन ई-निविदाएं आमंत्रित करता है। **टेंडर नंबर संख्या: SUR/SR.DMM/T.NO. 96255333A, दिनांक: 17.12.2025. विवरण**: आरडीएसओ स्पेसिफिकेशन नंबर एम&सी / एनडीटी / 128/ 2007 (बी-स्कैन) रिव.- IV अगस्त 2021 के अनुसार, डिजिटल अल्ट्रासोनिक सिंगल रेल टेस्टर जिसमें 9 प्रोब रंगीन सिगनल और रियल ए स्कैन पल्स इको के साथ बी स्कैन की लगातार रिकॉर्डिंग प्रत्येक प्रोब का स्टोरेज और डेटा सेटअप शामिल हैं, साथ ही एसेसरीज़ की सूची अनुलग्नक - 1 (संलग्न) के अनुसार। **मात्रा:** 4 नग। **बयाना राशि (INR)**: रु. 109320/-. **www.ireps.gov.in पर निविदा बंद होने की तिथि और समय 08.01.2026 11:30 बजे के बाद**। संभावित निविदाकर्ताओं को सलाह दी जाती है कि वे निविदा समाप्ति की तिथि से पहले वेबसाइट पर बार-बार विजिट करते रहें ताकि इस निविदा के लिए जारी किए गए किसी भी परिवर्तन / शुद्धिपत्र पर ध्यान दिया जा सके। वेबसाइट:

वरिष्ट मंडल सामग्री प्रबंधक मध्य रेल, सोलापुर
DE/Sur-71
खतरनाक व विस्फोटक सामान के साथ यात्रा करना दंडनीय अपराध है

मध्य रेल
ई-निविदा सूचना

वरिष्ठ मंडल विद्रुत इंजीनियर (सा.) मध्य रेल्वे, कार्यालय डी आर एम बिल्डिंग नागपुर द्वारा भारत के राष्ट्रपति की ओर से निम्नलिखित कार्य के लिए वेबसाइट **www.ireps.gov.in** के माध्यम से ई-निविदा आमंत्रित किए जाते हैं। **ई-निविदा सूचना: NGP/L/2025/T/29R20 दि. 16.12.2025. कार्य का नाम**: नागपुर मंडल पर SPIC 200109 CR पर लगे KOEL मॉडल 40 KVA इंजन का व्यापक रखरखाव और मरम्मत इंजन मॉडल HA 494 TCI GI का 3 वर्ष की अवधि के लिए व्यापक रखरखाव और मरम्मत। **अनुमानित लागत रूपये में** : 6,23,558.00/- (छह लाख तेईस हजार पांच सौ अट्ठावन रुपये मात्र)। **बयाना राशि रू. में**: 12,500/-. **टेंडर डॉक की कीमत रूपये में**: Nil. **कार्य पूर्ण करने की अवधि**: 36 महिने। **यह ऑफर 60 दिनों तक खुला रहेगा। निविदा जमा करने की तिथि एवं समय**: 09.01.2026 up to 11:00 Hrs. **निविदा खुलने की तिथि एवं समय**: 09.01.2026 up to 11:15 Hrs. **वेब साइट: www.ireps.gov.in** विस्तृत निविदा सूचना वरिष्ठ मंडल विदूत इंजीनियर मध्य रेल्वे नागपुर, कार्यालय, डीआरएम बिल्डिंग नागपुर कार्यालय के नोटिस बोर्ड पर लगाई गई है।

वरिष्ठ मंडल विद्युत इंजीनियर (सामान्य), मध्य रेल, नागपुर
DE/344
खतरनाक व विस्फोटक सामान के साथ यात्रा करना दंडनीय अपराध है

कॉम्प्रोमाइज नहीं किया, तो फिल्मों से निकाल दिया गया, मालती चाहर के खुलासे ने सबको किया हैरान

क्रिकेटर दीपक चाहर की बहन और फिल्म 'जीनियस' से बॉलीवुड में कदम रखने वाली एक्ट्रेस मालती चाहर इन दिनों सुर्खियों में हैं। हाल ही में बिग बॉस 19 में नजर आईं मालती ने फिल्म इंडस्ट्री के काले सच यानी 'कास्टिंग काउच' पर खुलकर बात की है। उन्होंने बताया कि कैसे करियर की शुरुआत में उन्हें डरावने अनुभवों से गुजरना पड़ा।

सिद्धार्थ कनन को दिए इंटरव्यू में मालती ने एक चौंकाने वाला खुलासा किया। उन्होंने बताया कि एक नामी और उम्रदराज डायरेक्टर ने उन्हें जबरदस्ती किस करने की कोशिश की थी। मालती ने कहा, 'मैं उन्हें पिता समान मानती थी। काम खत्म होने के बाद जब मैंने उन्हें साइड हग किया, तो उन्होंने मेरे होंठों पर किस करने की कोशिश की। मैं सन्न रह गई थी।' मालती ने उसी वक्त उन्हें टोक दिया और फिर कभी उनसे नहीं मिलीं।

मालती का कहना है कि जब आप इंडस्ट्री में झुकने से मना कर देते हैं, तो इसका खामियाजा आपको काम खोकर भुगतना पड़ता है। उन्होंने बताया, 'कई बार मेरा लुक टेस्ट हो जाता था, सब फाइनल होता था, लेकिन जब उन्हें पता चलता कि मैं 'कॉम्प्रोमाइज' नहीं करूंगी, तो मुझे लास्ट मिनट पर फिल्म से निकाल दिया जाता था। यह मेरे साथ कई बार हुआ है।' चूंकि मालती के पिता एयरफोर्स में रहे हैं, इसलिए उनकी परवरिश काफी सख्त माहौल में हुई। उनके पिता ने उनसे साफ कहा था, 'तुम पढ़ी-लिखी हो, अगर यहां काम न बने तो घर वापस आ जाना, लेकिन कभी गलत रास्ता मत चुनना।' मालती का मानना है कि इंडस्ट्री में लोग आपकी बॉडी लैंग्वेज देखकर समझ जाते हैं कि आप किस तरह के इंसान हैं।

पश्चिम रेलवे बांद्रा टर्मिनस ⇌ जयपुर के बीच स्पेशल ट्रेन चलाएगी

ट्रेन नंबर	प्रारंभिक स्टेशन और गंतव्य	सेवा की तिथि	प्रस्थान	आगमन
09704	बांद्रा टर्मिनस – जयपुर	26/12/2025	10:15 बजे (शुक्रवार)	07:30 बजे (अगले दिन)
09703	जयपुर – बांद्रा टर्मिनस	25/12/2025	08:10 बजे (गुरुवार)	07:25 बजे (अगले दिन)

हॉल्ट: बोरीवली, वापी, वलसाड, सूरत, वडोदरा, रतलाम, विक्रमगढ़ आलोट, भवानी मंडी, रामगंज मंडी, कोटा, सवाई माधोपुर और दुर्गापुरा स्टेशन दोनों दिशाओं में।

संरचना: फर्स्ट एसी, एसी 2-टियर, एसी 3-टियर, स्लीपर क्लास और जनरल सेकंड क्लास कोच।

ट्रेनों के ठहराव के समय एवं संरचना के संबंध में विस्तृत जानकारी के लिए यात्री कृपया www.enquiry.indianrail.gov.in पर जाकर अवलोकन कर सकते हैं।

ट्रेन नंबर 09704 की बुकिंग 20/12/2025 से सभी PRS काउंटर और IRCTC वेबसाइट पर शुरू होगी। यह ट्रेन स्पेशल किराए पर स्पेशल ट्रेन के तौर पर चलेगी।

पश्चिम रेलवे
wr.indianrailways.gov.in
हमें लाईक करें : facebook.com/WesternRly
हमें फॉलो करें : x.com/WesternRly
instagram.com/WesternRly

कृपया सभी आरक्षित टिकटों के साथ अपना वास्तविक पहचान पत्र भी साथ रखें

बीजेपी का मिशन साउथ! 20 दिसंबर को नितिन नबीन का तमिलनाडु दौरा, 23 को जाएंगे पीयूष गोयल

नई दिल्ली। केंद्रीय मंत्री और तमिलनाडु राज्य चुनाव प्रभारी पीयूष गोयल अगले साल होने वाले विधानसभा चुनावों से पहले 23 दिसंबर को चेन्नई का दौरा करेंगे। यह जानकारी भाजपा नेता आरएन जयप्रकाश ने गुरुवार को दी। एक प्रेस कॉन्फ्रेंस को संबोधित करते हुए तमिलनाडु भाजपा उपाध्यक्ष आरएन जयप्रकाश ने यह भी बताया कि नव निर्वाचित भाजपा राष्ट्रीय कार्यकारी अध्यक्ष 20 दिसंबर को चेन्नई आएंगे। उन्होंने कहा कि हमारे नए राष्ट्रीय कार्यकारी अध्यक्ष नितिन नबीन चेन्नई हवाई अड्डे पर आएंगे, जहां हम उनका भव्य स्वागत करेंगे। इसके बाद उनकी पुडुचेरी जाने की योजना है। केंद्रीय मंत्री और तमिलनाडु राज्य चुनाव प्रभारी पीयूष गोयल 23 दिसंबर को चेन्नई आएंगे।

मुख्यमंत्री एमके स्टालिन पर निशाना साधते हुए भाजपा नेता ने दावा किया कि डीएमके सरकार ने 2021 के चुनावों के दौरान किए गए अपने वादों को अभी तक पूरा नहीं किया है। उन्होंने पत्रकारों से कहा कि मुख्यमंत्री ने महिलाओं के लिए कई योजनाएं शुरू की थीं। फिर भी, हमें समझ नहीं आता कि उन्होंने स्वर्ण मंगलसूत्र योजना और एलपीजी सब्सिडी जैसे चुनावी वादे क्यों नहीं पूरे किए। मदुरै कार्तिकई दीपम को लेकर चल रहे विवाद के बीच भाजपा के शीर्ष नेता पीयूष गोयल और नितिन नबीन राज्य का दौरा करेंगे। इस विवाद में भाजपा ने तिरुप्परनकुंड्रम पहाड़ी पर स्थित पत्थर के स्तंभ पर दीपथून के ऊपर दीपक जलाने के अदालत के निर्देश का समर्थन किया है, जबकि डीएमके सरकार इसका विरोध कर रही है।

इससे पहले मंगलवार को भाजपा नेता के. अन्नामलाई ने तमिलनाडु के हिंदू धार्मिक और धर्मार्थ बंदोबस्ती विभाग (एचआर एंड सीई) को भंग करने की मांग की, जो दीपथून के ऊपर दीपक जलाने के निर्देश का विरोध कर रहा है। पुडुचेरी में एक जनसभा को संबोधित करते हुए अन्नामलाई ने कहा कि सरकारी विभाग ने इस निर्देश का विरोध किया है, जबकि मुस्लिम समुदाय ने मद्रास उच्च न्यायालय के फैसले पर कोई सवाल नहीं उठाया है।

भाजपा नेता ने कहा कि तमिलनाडु के हिंदू धार्मिक एवं धर्मार्थ बंदोबस्ती विभाग को समाप्त करने का समय आ गया है। उन्होंने आगे कहा कि यह आश्चर्यजनक है कि 1 दिसंबर के फैसले के बाद किसी भी मुस्लिम या स्थानीय व्यक्ति ने इस पर सवाल नहीं उठाया। लेकिन मंदिर सचिव ने अपील की। इसीलिए हम पूछते हैं कि तमिलनाडु में हिंदू धार्मिक एवं धर्मार्थ बंदोबस्ती विभाग क्यों है?

करूर भगदड़ के बाद तमिलनाडु में विजय की पहली रैली कहा- डीएमके एक बुरी ताकत और टीवीके पवित्र दल

चेन्नई। अभिनेता-राजनेता विजय ने गुरुवार को इरोड में एक जनसभा में सत्तारूढ़ डीएमके सरकार पर तीखा हमला बोलते हुए उस पर विफल शासन, अधूरे वादे और भ्रष्टाचार का आरोप लगाया। उन्होंने डीएमके को बुरी ताकत बताते हुए अपनी पार्टी तमिलगा वेट्री कज़गम (टीवीके) को 2026 के विधानसभा चुनावों से पहले स्वच्छ और पवित्र ताकत के रूप में पेश किया। 41 लोगों की जान लेने वाली करूर भगदड़ के बाद तमिलनाडु में विजय की यह पहली जनसभा थी।

सांस्कृतिक प्रतीकों का जिक्र करते हुए विजय ने कहा कि हल्दी का प्रयोग परंपरागत रूप से किसी अच्छे कार्य की शुरुआत के समय किया जाता था और मंजल का एक अलग ही महत्व है, जो तमिलनाडु के ध्वज में भी झलकता है। हल्दी की खेती के लिए प्रसिद्ध इरोड की शुभ भूमि बताते हुए उन्होंने इस क्षेत्र की पहचान को कृषि से जोड़ा।

सिंचाई के बारे में बात करते हुए, विजय ने कालिंगरायन नहर का विशेष रूप से उल्लेख किया और कहा कि इसने कृषि को फलने-फूलने में अत्यंत महत्वपूर्ण भूमिका निभाई है। एक स्थानीय लोककथा का जिक्र करते हुए उन्होंने बताया कि कालिंगरायन की माता ने दही और दूध बेचकर जो पैसा कमाया, उससे नहर का निर्माण पूरा करवाया। विजय ने कहा मां के सहयोग से कुछ भी हासिल किया जा सकता है। साथ ही यह भी कहा कि इरोड के लोगों द्वारा दिखाया गया विश्वास उन्हें भी वैसी ही शक्ति प्रदान करता है। विजय ने आरोप लगाया कि कई लोग साजिशों के जरिए इसे बर्बाद करने की सोच रहे हैं। लेकिन उन्होंने कहा कि जनता के साथ उनका रिश्ता नया नहीं है। उन्होंने कहा कि यह कोई नया रिश्ता नहीं है, सिनेमा में आने के बाद से यह 34 साल पुराना है। उन्होंने आगे कहा कि आप चाहे जो भी कोशिश कर लें, विजय, जिसने सब कुछ त्याग दिया है, जनता से निराश नहीं होगा।

भीड़ से प्रतिक्रिया की उम्मीद करते हुए उन्होंने कहा कि लोग मेरे साथ खड़े रहेंगे, क्या आप सब नहीं रहेंगे? आगे कहा कि इस उत्साह के लिए वे जीवन भर आभारी रहेंगे। समाज सुधारक पेरियार का जिक्र करते हुए विजय ने उन्हें इरोड का लौह पुरुष कहा और बताया कि वे तमिलनाडु को बदलने वाले व्यक्ति थे। उन्होंने कहा कि पेरियार ने वैचारिक आधार प्रदान किया। जबकि अन्ना और एमजीआर ने चुनावी रणनीतियां तैयार कीं। विजय ने कहा अन्ना और एमजीआर का इस्तेमाल करने पर कोई आपत्ति नहीं कर सकता।

नए साल से कार खरीदना पड़ेगा महंगा जेएसडब्ल्यू एमजी मोटर ने बढ़ाए दाम

नई दिल्ली **(एजेंसी)**। अगर आप जल्द नई कार खरीदने की योजना बना रहे हैं, तो यह खबर आपके लिए अहम है। साल 2025 के खत्म होते-होते ऑटो सेक्टर में एक बार फिर महंगाई की आहट सुनाई देने लगी है। जेएसडब्ल्यू एमजी मोटर इंडिया ने अपनी गाड़ियों की कीमतें बढ़ाने का ऐलान किया है, जिससे ग्राहकों की जेब पर सीधा असर पड़ेगा।

कंपनी ने गुरुवार को बताया कि वह 1 जनवरी 2026 से अपने वाहनों की कीमतों में 2 फीसदी तक की बढ़ोतरी करेगी। यह बढ़ोतरी अलग-अलग मॉडल और वेरिएंट के हिसाब से होगी यानी कुछ गाड़ियों पर मामूली असर पड़ेगा, जबकि कुछ मॉडल्स के दाम ज्यादा बढ़ सकते हैं।

जेएसडब्ल्यू एमजी मोटर इंडिया के मुताबिक, इनपुट कॉस्ट में लगातार इजाफा और वैश्विक आर्थिक हालात इस फैसले की मुख्य वजह हैं। कच्चे माल, लॉजिस्टिक्स और मैन्युफैक्चरिंग से जुड़े खर्चों में बढ़ोतरी का दबाव अब सीधे ग्राहकों तक पहुंच रहा है। ऐसे में कंपनी के लिए कीमतें बढ़ाना जरूरी हो गया है।

जेएसडब्ल्यू एमजी मोटर का यह फैसला ऐसे वक्त आया है, जब पूरी ऑटो इंडस्ट्री लागत बढ़ने के दबाव से जूझ रही है। इलेक्ट्रिक और पेट्रोल-डीजल दोनों सेगमेंट में वाहनों की लागत बढ़ रही है, वहीं ग्राहकों की मांग को संतुलित रखना कंपनियों के लिए चुनौती बना हुआ है। कीमतों में यह बढ़ोतरी खासतौर पर उन ग्राहकों को प्रभावित करेगी, जो नए साल में कार खरीदने की तैयारी कर रहे थे।

यमुना एक्सप्रेसवे पर अब तक 19 लोगों की हो चुकी है मौत, राज्य सरकार ने जारी किए सख्त दिशानिर्देश

मथुरा के जिला मजिस्ट्रेट सीपी सिंह ने पुष्टि की है कि यमुना एक्सप्रेसवे पर कई वाहनों की टक्कर से हुए हादसे में मरने वालों की संख्या बढ़कर 19 हो गई है। उन्होंने बताया कि यमुना एक्सप्रेसवे अधिकारियों और राज्य सरकार ने ऐसी घटनाओं की पुनरावृत्ति रोकने के लिए सख्त दिशानिर्देश जारी किए हैं। सीपी सिंह ने कहा कि 16 दिसंबर को यमुना एक्सप्रेसवे पर हुए इस दुखद हादसे में 19 लोगों की मौत हो गई है। चार शवों की पहचान हो चुकी है और बाकी शवों के डीएनए सैंपल लिए गए हैं। इस हादसे में करीब 90 लोग घायल हुए हैं। ज्यादातर घायलों को अस्पताल से छुट्टी दे दी गई है और उन्हें घर भेज दिया गया है, जबकि छह लोगों का अभी भी इलाज चल रहा है।

अधिकारी ने आगे बताया कि उत्तर प्रदेश सरकार ने निर्देश जारी किए हैं ताकि भविष्य में ऐसी घटना दोबारा न हो। उन्होंने कहा कि वाहनों को काफिले में चलना चाहिए। कम दृश्यता होने पर

वाहनों को रोक देना चाहिए। राज्य सरकार ने कैमरे लगाने के निर्देश दिए हैं। सड़क सुरक्षा ऑडिट किया गया है। यमुना एक्सप्रेसवे प्राधिकरण के अधिकारियों सहित चार सदस्यीय दल जांच कर रहा है। गति सीमा का ध्यान रखना चालक की जिम्मेदारी है।

इससे पहले, उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने मंगलवार को मथुरा जिले में यमुना एक्सप्रेसवे पर हुई भीषण वाहन दुर्घटना का संज्ञान लेते हुए मृतकों के परिवारों को तत्काल 2 लाख रुपये और घायलों को 50,000 रुपये की आर्थिक सहायता देने का निर्देश दिया। महोदय पर गहरा शोक व्यक्त करते हुए मुख्यमंत्री ने शोक संतप्त परिवारों के प्रति अपनी संवेदना व्यक्त की और अधिकारियों को सभी घायलों के लिए शीघ्र, उचित और निःशुल्क चिकित्सा उपचार सुनिश्चित करने और हर संभव सहायता प्रदान करने का निर्देश दिया।

मुख्यमंत्री कार्यालय ने एक्स पर एक पोस्ट में लिखा, 'मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने मथुरा जिले में हुई सड़क दुर्घटना का संज्ञान लिया है और जानमाल के नुकसान पर गहरा दुख व्यक्त किया है। मुख्यमंत्री जी ने मृतकों के परिवारों के प्रति संवेदना व्यक्त की है और अधिकारियों को निर्देश दिया है कि घायलों को तत्काल, उचित और निःशुल्क उपचार मिले और उन्हें हर संभव सहायता प्रदान की जाए। मुख्यमंत्री जी ने निर्देश दिया है कि दुर्घटना में जान गंवाने वालों के परिवारों को 2-2 लाख रुपये और घायलों को 50-50 हजार रुपये की वित्तीय सहायता प्रदान की जाए। मुख्यमंत्री ने त्वरित राहत और बचाव कार्यों की आवश्यकता और प्रभावितों की चिकित्सा देखभाल की कड़ी निगरानी पर भी जोर दिया।'

बेल्जियम की सुप्रीम कोर्ट से चोकसी की अपील खारिज

कहा-भारत में न्याय से इनकार का खतरा नहीं

ब्रसेल्स। पीएनबी घोटाले में वांछित मेहुल चोकसी को भारत लाने की राह अब साफ हो गई है। बेल्जियम की सबसे बड़ी अदालत बेल्जियम की कोर्ट ऑफ कैसेशन ने भगोड़े हीरा व्यापारी मेहुल चोक्सी द्वारा उठाई गई आपत्तियों को निराधार मानते हुए भारत को प्रत्यर्पण के खिलाफ उनकी अपील खारिज कर दी है। कोर्ट ने पुष्टि की है कि वे अपने आत्मसमर्पण की अनुमति देने वाले पूर्व आदेशों में हस्तक्षेप करने के लिए कोई कानूनी या तथ्यात्मक आधार स्थापित करने में विफल रहे हैं। अपने फैसले में बेल्जियम के सर्वोच्च न्यायालय ने एंटवर्प कोर्ट ऑफ अपील के अभियोग कक्ष के 17 अक्टूबर, 2025 के फैसले को बरकरार रखा और निष्कर्ष निकाला कि प्रत्यर्पण की कार्यवाही घरेलू कानून के साथ-साथ यूरोपीय मानवाधिकार मानकों का पूरी तरह से अनुपालन करती है।

कोर्ट ने कहा कि भारत में चोकसी को न्याय से इनकार, यातना या अमानवीय व्यवहार का कोई वास्तविक और गंभीर खतरा नहीं है। कोर्ट ने चोकसी पर 11, 000 रुपए (104 यूरो) का जुर्माना भी लगाया है। यह फैसला एंटवर्प कोर्ट ऑफ अपील की इंडाइटमेंट चैंबर के आदेश को बरकरार रखता है। इसमें कहा गया था कि चोकसी के दावे पर्याप्त नहीं हैं कि भारत में उसे न्याय नहीं मिलेगा या उसके साथ अमानवीय व्यवहार होगा। चोकसी ने अपनी अपील में एंटिगुआ से कथित अपहरण, इंटरपोल की फाइलों की निगरानी करने वाले आयोग (सीसीएफ) की राय, मीडिया कवरेज और भारत में निष्पक्ष सुनवाई न मिलने की आशंका जैसे तर्क दिए थे। लेकिन कोर्ट ने इन्हें खारिज कर दिया। चोकसी का यह भी आरोप था कि अभियोजक ने सीसीएफ की रिपोर्ट को एंटवर्प कोर्ट के सामने नहीं रखा, लेकिन सुप्रीम कोर्ट ने इसे भी मानने से इनकार कर दिया।

सभी कानूनी औपचारिकताओं का विधिवत पालन किए जाने पर, कोर्ट ऑफ कैसेशन ने अपील खारिज कर दी और चोकसी को 104.01 यूरो का खर्च वहन करने का निर्देश दिया। चोकसी और उनके भतीजे नीरव मोदी पर पंजाब नेशनल बैंक के खिलाफ लगभग 2 अरब डॉलर की धोखाधड़ी करने का आरोप है। केंद्रीय जांच ब्यूरो और प्रवर्तन निदेशालय ने भारत में उनके खिलाफ कई आरोपपत्र दायर किए हैं, और इस मामले से संबंधित कई गैर-जमानती वारंट लंबित हैं।

गणतंत्र दिवस 2026 के मेहमान पर भारत का बड़ा ऐलान, 27 देशों संग होगी 100 बिलियन की डील!

नई दिल्ली **(एजेंसी)**। भारत और यूरोप की दोस्ती की बड़ी खबर सामने आ रही है। उसकी बड़ी वजह है भारत का वो ऐतिहासिक फैसला जो सिर्फ दिल्ली नहीं जो वाशिंगटन नहीं मॉस्को नहीं बीजिंग नहीं पूरे यूरोप में गूंज रहा। 26 जनवरी 2026 भारत का गणतंत्र दिवस पर ना ट्रंप होंगे, ना पुतिन होंगे, ना मेलोनी होंगे, ना फ्रांस के राष्ट्रपति होंगे, ना जर्मनी के चांसलर होंगे और ना ही इंग्लैंड के पीएम होंगे। इस बार यह सिर्फ परेड नहीं होगी। इस बार सिर्फ झांकी नहीं होगी। यह सिर्फ सम्मान नहीं होगा। यह भारत के वैश्विक पहचान का प्रदर्शन होगा। दरअसल सबसे पहले बात करते हैं उन नामों की जो नहीं आ रहे। अमेरिका आज भी सुपर पावर है लेकिन उसकी नीतियां बदलती रहती है। एक राष्ट्रपति आता है। सब कुछ उलट देता है। रूस भारत का पुराना मित्र है। लेकिन आज वह युद्ध और प्रतिबंधों से जूझ रहा है। उलझा हुआ है।

फ्रांस भारत का पक्का दोस्त है। लेकिन भरोसेमंद नहीं कहा

जा सकता। भारत जानता है कि 21वीं सदी एक देश की नहीं ब्लॉक की सदी है और इसीलिए भारत ने किसी एक चेहरे को नहीं पूरे यूरोपीय संघ को चुन लिया है क्योंकि भारत ने तय किया है कि 2026 के गणतंत्र दिवस पर वो दुनिया की किसी एक सुपर पावर को नहीं बल्कि पूरे यूरोप के नेतृत्व को बुलाएगा और यही वो फैसला है जिसने दुनिया को चौंका दिया। दरअसल 26 जनवरी 2026 के मुख्य अतिथि हैं यूरोपीय आयोग की अध्यक्ष यानी ईयू की सरकार की प्रमुख उर्सला वन डेथ लेन और एंटोनियो कोस्टा जो यूरोपीय परिषद के अध्यक्ष यानी 27 देशों के नेताओं के प्रतिनिधि हैं। यह पहली बार होगा जब भारत गणतंत्र दिवस पर किसी अंतरराष्ट्रीय संगठन के दो शीर्ष नेताओं को एक साथ बुला रहा। यह अपने आप में इतिहास है। गणतंत्र दिवस का मुख्य अतिथि केवल सम्मान नहीं होता।

यह संकेत होता है। यह संकेत होता है कि भारत आने वाले सालों में किसके साथ किस दिशा में आगे चलने वाला है। जब भारत एशियन देशों को बुलाता है तो वो दक्षिण पूर्व एशिया को प्राथमिकता देता है। जब भारत अमेरिका को बुलाता है तो वो इंडोपेसिफिक को संदेश देता है और जब भारत ईओ को बुला लेता है तो वह कहता है कि हम एक से नहीं एक महाद्वीप से साझेदारी करना चाहते हैं। उम्मीद है कि 26 जनवरी ही वो तारीख है या उसके अगले दिन जब भारत और यूरोप के बीच फ्री ट्रेड एग्रीमेंट साइन हो जाएगा और लागू भी हो सकता है। ऐसे में अगर यह समझौता हो जाता है तो भारत को यूरोप के बाजारों में आसानी से एंट्री मिल जाएगी। एक्सपोर्ट में जबरदस्त बढ़ोतरी आ जाएगी। निवेश का बाढ़ जैसा प्रवाह हो जाएगा। इतना ही नहीं। दूसरी तरफ ईओ को चीन का विकल्प मिल जाएगा।

रूस से खरीदा तेल तो लगेगा तगड़ा टैरिफ, अमेरिकी सीनेट में आया नया बिल

वाशिंगटन। अमेरिकी सीनेटरों के एक समूह ने एक नया प्रस्ताव पेश किया है। इसका मकसद उन विदेशी कंपनियों पर आर्थिक प्रतिबंध लगाना है जो रूस से तेल खरीदना जारी रखती है। अमेरिका का कहना है कि रूस इन पैसो का इस्तेमाल यूक्रेन के खिलाफ लड़ाई को और मजबूत करने में करता है। ओहियो के रिपब्लिकन सीनेटर जॉन हस्टेड द्वारा पेंसिल्वेनिया के सीनेटर डेव मैककॉर्मिक, मैसाचुसेट्स की सीनेटर एलिजाबेथ वॉरेन और डेलावेयर के सीनेटर क्रिस्टोफर कून्स के साथ मिलकर पेश किया गया 'डिक्रीजिंग रशियन ऑयल प्रॉफिट्स (डीआरओपी) एक्ट ऑफ 2025' अमेरिकी सरकार को रूसी पेट्रोलियम उत्पादों की खरीद में प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष रूप से शामिल पाए जाने वाले विदेशी व्यक्तियों पर प्रतिबंध लगाने का अधिकार देता है। सीनेटर जॉन हस्टेड ने कहा कि यह विधेयक दुनिया को स्पष्ट संदेश देता है कि रूसी तेल खरीदना जारी रखने के परिणाम भुगतने होंगे। उन्होंने आगे कहा कि कांग्रेस उन देशों के पाखंड को अब और बर्दाश्त नहीं करेगी जो विश्व मंच पर व्लादिमीर पुतिन के कार्यों की निंदा करते हैं, जबकि संदिग्ध तेल खरीद के माध्यम से उनकी युद्ध मशीन को वित्त पोषित करते हैं। प्रस्तावित कानून के तहत, कुछ सीमित शर्तों के तहत देशों को प्रतिबंधों से छूट मिल सकती है, जिनमें यूक्रेन को सैन्य या आर्थिक सहायता प्रदान करना शामिल है। इस उपाय का उद्देश्य अमेरिकी सहयोगियों और व्यापारिक साझेदारों को रूसी ऊर्जा आपूर्ति पर निर्भरता कम करने के लिए प्रोत्साहित करना भी है।

हस्टेड ने कहा कि अगर हमारे सहयोगी और व्यापारिक साझेदार तेल खरीदना चाहते हैं, तो वे अमेरिकी तेल खरीद सकते हैं। जो देश रूसी तेल खरीदने पर अड़े हैं, यह विधेयक उन्हें यूक्रेन को समर्थन देने के लिए प्रोत्साहित करेगा।

पीएम मोदी को मिला ओमान का सर्वोच्च नागरिक सम्मान, मंडेला और एलिजाबेथ की सूची में शामिल

मस्कट। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को गुरुवार को ओमान के राष्ट्रीय सम्मान 'प्रथम श्रेणी के ऑर्डर ऑफ ओमान' से सम्मानित किया गया। यह प्रधानमंत्री मोदी को प्राप्त होने वाला 29वां राष्ट्रीय सम्मान है। यह सम्मान इससे पहले महारानी एलिजाबेथ, नेल्सन मंडेला, महारानी मैक्सिम, सम्राट अकिहितो और जॉर्डन के राजा अब्दुल्ला सहित कई प्रतिष्ठित हस्तियों को दिया जा चुका है। प्रधानमंत्री मोदी अपने तीन देशों के दौरे के अंतिम चरण में ओमान पहुंचे। दोनों नेताओं के बीच द्विपक्षीय बैठक से पहले मस्कट के अल बराका पैलेस में सुल्तान हैथम बिन तारिक ने उनका स्वागत किया।

प्रधानमंत्री मोदी को इस सम्मान समेत दूसरे देशों में 28 से अधिक उच्चतम नागरिक सम्मान से नवाजा जा चुका है। हाल ही में उन्हें इथियोपिया में ग्रेट ऑनर निशां ऑफ इथियोपिया और कुवैत में ऑर्डर ऑफ मुबारक अल-कबीर से सम्मानित किया गया था। भारत और ओमान के बीच कूटनीतिक संबंधों की 70वीं वर्षगांठ के अवसर पर मोदी ओमान की यात्रा पर हैं। इस यात्रा के दौरान दोनों पक्ष व्यापार, निवेश, ऊर्जा, रक्षा और संस्कृति में रणनीतिक साझेदारी को प्रगाढ़ बनाने पर ध्यान केंद्रित कर रहे हैं। प्रधानमंत्री मोदी बुधवार को मस्कट पहुंचे थे, जहां उनका गर्मजोशी से स्वागत करते हुए 'गार्ड ऑफ ऑनर' दिया गया।

ट्रंप का अब तक का सबसे बड़ा 'प्रहार', 39 देशों के लोगों के लिए अमेरिका में नो एंट्री!

वाशिंगटन। अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने मंगलवार यानी 16 दिसंबर को एक नया घोषणापत्र प्रोक्लेमेशन पर साइन कर दिए हैं। इससे अमेरिका में एंट्री पर पूरी तरह से या पार्शियल बैन वाले देशों की संख्या 19 से बढ़कर 39 हो गई है। यह बदलाव 1 जनवरी 2026 से लागू होंगे। व्हाइट हाउस के मुताबिक यह प्रतिबंध उन देशों पर लगाए गए हैं जहां स्क्रीनिंग, वेटिंग लिस्ट और जानकारी साझा करने में गंभीर कमियां हैं। इसका मकसद अमेरिका की राष्ट्र सुरक्षा, आतंकवाद विरोध और इमीग्रेशन कानून को मजबूत करना है। कई देशों में आतंकवादी गतिविधियां, भ्रष्टाचार और वीजा ओवरस्टे की हाई फ्रीक्वेंसी को इसकी वजह बताया गया है।

जिन लोगों के पास पहले से वीजा है, जो अमेरिका के वैध स्थायी निवासी हैं, जो राजनयिकों या खिलाड़ियों जैसी कुछ विशेष वीजा श्रेणियां के तहत अमेरिका आते हैं या जिनका अमेरिका में प्रवेश देश के हित में माना जाता है, उन्हें इन प्रतिबंधों से छूट दी गई है। घोषणा में कहा गया है कि ये बदलाव एक जनवरी से प्रभावी होंगे। जून में ट्रंप ने घोषणा की थी कि 12 देशों के नागरिकों को अमेरिका आने से प्रतिबंधित किया जाएगा। आपको बता दें कि ट्रंप ने अपने पहले कार्यकाल में भी मुस्लिम बहुल देशों पर ट्रैवल बैन लगाया था। जिसे सुप्रीम कोर्ट ने मंजूरी दी थी। बाइडन जब आए तो उन्होंने यह ट्रैवल बैंड्स हटा दिए। अब दूसरे कार्यकाल में ट्रंप ने एक बार फिर से यह कारवाही शुरू कर दी है। जनवरी 2025 से ट्रंप ने इमीग्रेशन को सख्त करना शुरू कर दिया था। जून महीने में 19 देशों पर बैन लगाया गया। नवंबर में वाशिंगटन में एक अफगान व्यक्ति द्वारा नेशनल गार्ड पर हमले के बाद ट्रंप ने और सख्ती की बात कही। दिसंबर में यह विस्तार हुआ। वाइट हाउस का कहना है कि यह डाटा आधारित फैसला है।

Facebook: https://www.facebook.com/profile.phpid=100063787346044 Twitter: https://twitter.com/mantrabharatt=8tJONQ7H-h6EKqqap2tVMw&s=08 Mobile No: 7007837917

मंत्र भारत : R.N.I. MAHHIN/ 2016/65841 स्वात्वाधिकारी राकेश शर्मा के लिए राकेश शर्मा द्वारा AIS Printing solution प्लॉट नं0-A- 544 TTC इंडस्ट्रियल एरिया एमआईडीसी माहपे-नवी मुंबई, थाने 400709 से मुद्रित एवं शाप.नं. 36, द्वितीय तल, प्लाट -490.1. जाम मील बिल्डिंग, डॉ बाबा साहेब अम्बेकर रोड, लाल बाग परेल, मुम्बई-400012प्रकाशित एवं सम्पादित । कार्यालय : शाप.नं. 36, द्वितीय तल, प्लाट -490.1. जाम मील बिल्डिंग, डॉ बाबा साहेब अम्बेकर रोड, लाल बाग परेल, मुम्बई-400012 । फोन : 022-24706563 । कार्यकारी सम्पादक- योगेन्द्र चौधरी
E-Mail : editormantrabharat@gmail.com mantrabharatmumbai@gmail.com । सम्पादक : विनोद आर शर्मा, मोबाइल : 7007837917 । समूह सम्पादक : डॉ दयानन्द तिवारी। वैधानिक सूचना : मंत्र भारत से संबंधित समस्त विवाद निपटारे के लिए मंत्र प्रधान कार्यालय क्षेत्र प्रयागराज/ इलाहाबाद न्यायालय ही होगा। प्रधान कार्यालयः 80ए मेंहदौरी, तेलियरगंज, प्रयागराज-211004 (नोटः कानूनी पत्र व्यवहार का पता प्रधान कार्यालय ही होगा।)